भ्रष्टाचार हथियार

परिवारवाद पर वार

सफलता के 14वें वर्ष में प्रवेश

वार्षिकांक

मूल्य 30/-

सितंबर, 2022

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

छठा डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव एवं इंटरनेशनल अवार्ड-2022

नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की संभावनाएं

Follow us on

GEM MINES®
CERTIFIED & NATURAL GEMS

When you
choose
Gem Mines,
You choose
Authenticity
and Purity

100% ORIGINAL GEMSTONES

Free Janampatri and Consultation

on selected days (Tuesday, Friday, Saturday & Sunday)

098108 00550

SHOP ONLINE

www.gemmines.in

SCAN THE BARCODE FOR WHATSAPP

2547/6, 2nd Floor, Beadonpura, Gurudwara Road, (Near Post Office) Karol Bagh, Delhi

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की वाह संवाद की राह

सितंबर, 2022

06

दिल्ली में डायलॉग इंडिया एकेडमिया कांक्लेव व इंटरनेशनल अवार्ड - 2022 की धूम

14

छठा डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव - 2022

30

करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी का रजत जयंती समारोह
भारतीय शिक्षा के स्वदेशीकरण का समय

44

क्या जम्मू-कश्मीर से कांग्रेस का सफाया करके ही दम लेंगे गुलाम नबी आजाद?

66

दिल्ली का दारू घोटाला

72

भाषा किसी देश की सांस्कृतिक समृद्धि की सूचक होती है

74

चीन में मंदी की आहट

76

ताइवान पर अमेरिका और चीन में क्या हो सकता है युद्ध ?

78

यूरोप में 500 साल का सबसे बड़ा सूखा

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की वाह संवाद की राह

वर्ष- 14 अंक- 1

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी

संपादकीय सलाहकार
संजीव शर्मा, मयंक मधुर एवं सिद्धार्थ जैन

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, डॉ. अर्चना पाटिल
आदित्य गोयल, डॉ. यशवंत चौधरी

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल एवं निर्भय कुशवाहा

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - रूपक कुमार
बिहार - नंद शर्मा
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
गौतमबुद्ध नगर - मनीष गुप्ता
गाजियाबाद - घनश्याम शर्मा

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : **www.dialogueindia.in**

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

सितंबर, 2022 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

डायलॉग इंडिया के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल सम्मानित

गोल्डन सिग्नेचर संस्था द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के ली मरिडीयन होटेल में आयोजित सीईओ कॉन्फ्रेन्स - 2022 में देश की प्रमुख हस्तियों सहित मौलिक भारत व करियर प्लस के अध्यक्ष व डायलॉग इंडिया समूह के संपादक अनुज अग्रवाल को समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 'इंडिया बियोंड 75 प्लेटिनम एक्सलेन्स अमृत अवार्ड-2022' से सम्मानित किया। सम्मान प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कबीर बेदी द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि नॉएडा निवासी अनुज अग्रवाल लगातार विभिन्न सामाजिक व शैक्षिक मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और निरंतर आम आदमी पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं।

सही दिशा की खोज में

आजादी के अमृत महोत्सव के मध्य डायलॉग इंडिया समूह ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। अब हम अपने प्रकाशन के तेरह वर्ष पूर्ण कर चौदहवे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। राष्ट्रवादी व सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता, सत्य के साथ जनोन्मुख लेखन, सुशासन व वैकल्पिक नीतियो के मुद्दों पर निरंतर बहस की हमारी पहचान आज भी बनी हुई है। कोविड व लॉकडाउन के कठिन समय में भी हमने कुछ अपवादों को छोड़ अपने कार्य को थमने नहीं दिया। आशा है हमारे पाठक व शुभचिंतक इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दो वर्षों के विराम के बाद हमने उच्च शिक्षा के निजी संस्थानो पर अपनी रैंकिंग इसी माह जारी की व पुन: 'डायलॉग इंडिया एकेडमिया कांक्लेव एवं इंटरनेशनल अवार्ड - 2022' सफल व भव्य आयोजन दिल्ली में किया। इस वर्ष भारत सरकार के अनेक मंत्रियों व लोकसेवकों के साथ सैकड़ों शिक्षाविद व अन्य क्षेत्रों के दिग्गज जुटे व 'कैसे भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुन: वैश्विक केंद्र बन सकता है' इस विषय पर गहन मंथन किया। इस चिंतन - मंथन का सार हम इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह बहस आगे बढ़ेगी व सार्थक स्वरूप लेगी व भारतीय उच्च शिक्षा को सही दिशा मिलेगी।

देश की राजनीति व दुनिया नित नए रंग बदल रहे हैं, किंतु यह बदलाव सही दिशा में नहीं हो रहे। राजनीति का स्वरूप व स्तर बहुत घटिया व ओछा होता जा रहा है। भ्रष्टाचार व अपराधीकरण इतना हावी हो चुका है कि देश के हर राज्य में जांच एजेंसियां नित नयी कार्यवाही कर रहीं है व राजनेताओं की लूट के नए-नए किस्से सामने आते जा रहे हैं। आजादी के 75 वर्षों बाद भी लालकिले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री को आह्वान करना पड़ रहा है कि जनता भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष करे। यह कड़वी सच्चाई है कि वंशवाद की राजनीति से ही भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है। मोदी जी ने अपने भाषण में आगामी पच्चीस वर्षों के लिए में पांच प्रणों का भी जिक्र किया। ये हैं-विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। निश्चित रूप से ये बड़े व सार्थक लक्ष्य हैं व प्रत्येक देशवासी को इनको प्राप्त करने में जुट जाना चाहिए। बीते कुछ समय में देश गांधी परिवार के साथ साथ महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, दिल्ली, झारखंड व उत्तर प्रदेश के राजनेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्यवाहियों का गवाह बना है। इन कार्यवाहियों में जो लूट व घोटालों के दु:खद सत्य सामने आए उससे देश की जनता दु:खी व हैरान है। ऐसे समय जबकि देश व दुनिया कठिन परिस्थितियों से दो चार हैं, इन नेताओं की दोनो हाथों से खुली लूट देख जनता ठगी महसूस कर रही है। उम्मीद है यह जांच अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगी व ये लुटेरे कड़ी सजा पाएंगे। विपक्षी दलों के आरोप हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक बदले व सत्ता पर कब्जे के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है जबकि भाजपा शासन में भी भ्रष्टाचार चरम पर है और जो भी विपक्षी नेता भाजपा में आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है व उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इस दावे में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है किंतु इससे विपक्षी नेताओ की लूट व भ्रष्टाचार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर हो कि विपक्ष भाजपा नेताओ व सरकारों में अगर भ्रष्टाचार है तो उसे तथ्यों सहित सामने लाए व न्यायालयों में जाए व उनको सजा दिलाए। तभी देश व राजनीति सही दिशा पकड़ पाएंगे।

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हो रहा क्लाईमेट चेंज हर दिन वीभत्स स्वरूप लेता जा रहा है। इसके कारण पूरी धरती भयंकर सूखे व बाढ़ से जूझ रही है। इस सबके बाद भी सरकारें विकास, बाजार व जीडीपी आधारित नीतियो से हाथ झाड़ने को तैयार नहीं। बाजार के दुश्चक्र में उलझे लोगों को एक चक्रवात में फंसा दिया गया है। जिस प्रकार परिस्थितियां हर दिन के साथ तेजी से बदल रही हैं और प्रकृति सिकुड़ती जा रही है, दुनिया खाद्य पदार्थों की भीषण कमी से दो चार होने वाली हैं। अनाज, फलों व सब्जियों का संकट जहां महंगाई को बढ़ा रहा है वहीं मंदी भी बढ़ रही है और इसका अगला स्वरूप ग्रहयुद्ध व देशों के बीच युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। बेहतर हो कि दुनिया के राजनेता एक साथ बैठें व अपनी नीतियो व सोच में आमूलचूल परिवर्तन करें व दुनिया को सही दिशा में ले जायें अन्यथा आसन्न संकट पूरी मानवता को निगल जाएगा।

अनुज अग्रवाल
संपादक

दिल्ली में डायलॉग इंडिया एकेडमिया कांक्लेव व इंटरनेशनल अवार्ड - 2022 की धूम

- जारी की गई वर्ष 2022 के लिए निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग
- केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने किया कॉन्क्लेव का उद्घाटन तो समापन सत्र व अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह
- एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा बनी देश की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 6 अगस्त, 2022 को शंगरी-ला होटल में छठा डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवां डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड फंक्शन - 2022 आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक समूहों, विभिन्न शैक्षणिक विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं को अपने मन की बात कहने और विचारोत्तेजक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने 'नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की संभावनाओं' पर चर्चा की।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों व सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति यों द्वारा डायलॉग इंडिया द्वारा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों की 11वीं वार्षिक रैंकिंग का विमोचन किया गया। यह रैंकिंग प्रकाशन के दोनो पोर्टल पर सभी के लिए निशुल्क उपलब्ध है व निम्न लिंक पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है :

1. http://dialogueindia.in/wp-content/uploads/w®ww/®}/dialogue-india-annual-survey-w®ww.pdf
2. http://dialogueindiaacademia.com/wp-content/uploads/w®ww/®}/dialogue-india-annual-survey-w®ww.pdf

डायलॉग इंडिया एकेडेमिया अवार्ड्स की वीडियो क्लिप–2022

3. इसी रैंकिंग के आधार पर कार्यक्रम के समापन पर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह ने देश के सर्वश्रेष्ठ निजी संस्थानों को पुरस्कृत किया। सर्वे के अनुरूप एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा देश की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी बनकर उभरी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य प्रमुख संस्थानों की सूची निम्नलिखित है –

INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH
Third Best Management College of Uttar Pradesh - 2022

Ajay Kumar Garg Engineering College,Ghaziabad, Uttar Pradesh,
Best Private Engineering College of Uttar Pradesh – 2022 &
Among top Five Engineering college of North, East & NE India

ABES Engineering College, Ghaziabad (UP)
Best Private Engineering College of Uttar Pradesh – 2022

K S R Institute of Engineering & Technology, Tiruchengode,
Namakkal D.T., Most Promising Engineering college of
Tamilnadu in the field of R & D

R.D.Engineering College, Ghaziabad, U P
Among top Ten Engineering college of UP – 2022

Era Lucknow Medical College, Lucknow, UP
Best Private Medical College of Uttar Pradesh - 2022 and
Among top 10 Private Medical College in India - 2022

Subharti Medical College ,Meerut (UP)
Third Best Private Medical College of Uttar Pradesh – 2022

Subharti Dental College, Meerut (UP)
Third Best Private Dental College of Uttar Pradesh - 2022

DAV Centenary Dental College, Yamunanagar, Haryana
Best Private Dental College of Haryana - 2022

Mangalayatan University, Mathura-Aligarh Highway, Aligarh, UP
Best Emerging Private University of Uttar Pradesh - 2022

Usha Martin University, Ranchi
Best Private University of Jharkhand - 2022

Amity University, Gwalior ,Madhya Pradesh
Best Private University in Madhya Pradesh – 2022

IIMT University, Meerut, UP
Best Emerging Private University of Uttar Pradesh - 2022
(Remarkable work in the field of Innovation)

Chitkara University, Patiala , Punjab
Best Private University of Punjab - 2022 & Third Best Private University of India - 2022

Marwadi University,Rajkot
Best Emerging Private University in Gujrat - 2022

Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad,Haryana
Best Private Deemed University of Haryana – 2022

Mody University of Science & Technology, Laxmangarh District - Sikar Rajasthan, Rajasthan- 332311, Third Best Private University of Rajasthan & Best Women University of India - 2022

G.L.A. University , Mathura,UP
Best Private University of Uttar Pradesh and Among Best Private University of India - 2022

Amity University, Noida, UP
Best Private University of India - 2022

Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha
Third Best Private Deemed University of India - 2022

Dr. Urvashi Makkar, Director IMS
Dialogue India Editor Choice Education Excellence Award - 2022
(For remarkable services in the field of Education)

Shri Yogesh Mohanji Gupta, Chairman, IIMT University, Meerut, UP,
Dialogue India Life Time Achievement Award – 2022
(For Tremendous Services in the Field of Higher Education)

Dr. Atul Chauhan, Chancellor, Amity University , Noida, UP
Dialogue India Education Icon of the Year -2022

Mr. Mohsin Ali Khan, Trustee ,Era Lucknow Medical College , Lucknow, UP, Dialogue India Education Icon of the Year -2022

Dr. Pankaj Kumar Singh - Director -Research, R D Engineering College
Best Research Director in the field of Biological waste water treatment and Plant Medicine

Simpy Matharoo, CMD, Soul Spry, Noida
Editor Choice Education Excellence Award – 2022
(For Excellent work in Natural Science)

Dr. G. M Patil, Vice Chancellor, Lingaya's Vidyapeeth, Faridabad, Dialogue India Editor Choice Education Excellence Award - 2022
(For remarkable services in the field of Education)

• • • • • • • •

Mr. Neeraj Gupta,CEO- GLA University, Dialogue India Education Icon of the Year -2022

• • • • • • • •

Dr Ravi Shankar Singh, Postdoctoral Research Associates
University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, UT, USA. Best Global Researcher in the field of Innate immunity, auto-immunity & Cancer.

• • • • • • • •

Dr Vivek Singh, Associate Professor, UDAI Pratap College, Varanasi, Best Researcher in the
Field of Blue-green algae as a biofertilizer !!

11th
DIALOGUE INDIA
National Ranking
2022
6th
DIALOGUE INDIA
Academia Conclave
8th
DIALOGUE INDIA
International Academia Awards
2022

6th
DIALOGUE INDIA
Academia Conclave

6th DIALOGUE INDIA Academia Conclave 2022

छठा डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव - 2022

नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की संभावनाएं

11th DIALOGUE INDIA National Ranking (For Private Higher Education Institutions in India) 2022

6th DIALOGUE INDIA Academia Conclave 2022

8th DIALOGUE INDIA International Academia Awards (For Private Higher Education Institutions in India) 2022

Mr. Anuj Agarwal, Founder & Group Editor, Dialogue India
Welcome to Gen. V K singh Ji, Minister, Govt. of India

Mr. Anuj Agarwal, Founder & Group Editor, Dialogue India
Welcome to Sh. Ashwini Kumar Choubey,Minister, Govt. of India

Welcome to the Chief Guest
Dialogue India Academia Conclave & Awards -2022

Mr. Anuj Agarwal, Founder & Group Editor, Dialogue India,
Welcome to Sh. Ramdas Athawale, Minister, Govt. of India

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 6 अगस्त, 2022 को शांगरी-ला होटल में छठा डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवां डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडेमिया अवार्ड फंक्शन-2022 आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक समूहों, विभिन्न शैक्षणिक विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं को अपने मन की बात कहने और विचारोत्तेजक चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिला। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए सैंकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने 'नई शिक्षा नीति और भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की संभावनाओं' पर चर्चा की।

कार्यक्रम की शुरुआत में डायलॉग इंडिया के **संपादक अनुज अग्रवाल और डायलॉग इंडिया के सलाहकार सिद्धार्थ जैन** ने सभी प्रतिष्ठित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

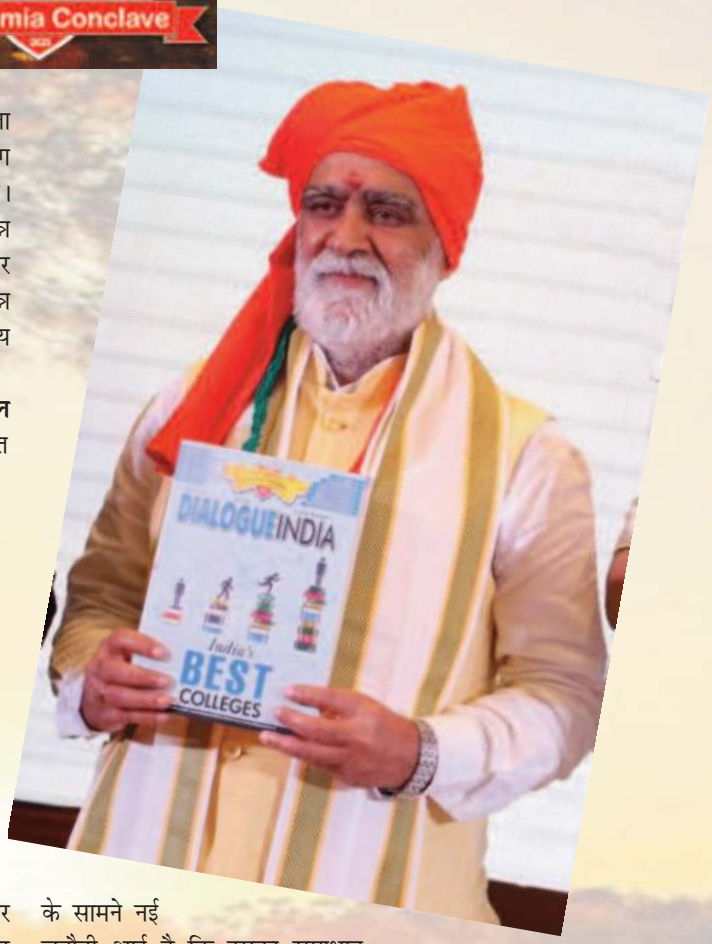

शिक्षा जगत को जलवायु परिवर्तन और डिजिटलाइजेशन से निपटना होगा - अनुज अग्रवाल, समूह संपादक, डायलॉग इंडिया

इस अवसर पर चर्चाओं और विचार-मंथन का एजेंडा निर्धारित करते हुए डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल ने कहा कि हमारी उच्च शिक्षा और शोध को बदलती वास्तविकताओं के अनुसार ढलना होगा। देश के लगभग 3000 संस्थान घूमने के बाद वह यह कह सकते हैं कि अब बुनियादी ढ़ांचे की कहीं कोई कमी नहीं है और वित्तीय निवेश भी पर्याप्त है। अब तकरीबन सारे बड़े कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घराने इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। इन सब के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी खूब तरक्की कर रहे हैं। इस तरह हालात पहले से बेहतर हैं। अब हमारे लिए जरूरी यह है कि हम बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार बदलाव लाने पर ध्यान दें। उनके अनुसार 'जिस तरह दुनिया बदल रही है और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उससे उच्च शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम ही बदलने वाला है।' उन्होंने बल देकर कहा कि हमें पूरी शिक्षण सामग्री ही बदलनी होगी क्योंकि अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, शायद कल वह अप्रासंगिक हो जाए। आज जिस जगह पर जो फसल होती है, वह फसल भविष्य में वहां नहीं होगी तो ऐसे में हमें अपनी किताबें भी बदलनी होंगी।

जलवायु परिवर्तन और मौसम में तेजी से आ रहे बदलावों के शैक्षिक जगत पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक क्षेत्र में काफी विविधता और डायनेमिस्म है, अब उद्योग हो या व्यवसाय, इनकी मांग-पूर्ति श्रृंखला बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गई है। इससे प्रबंधन छात्रों के सामने नई चुनौती आई है कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। चाहे खाद्य पदार्थ हों या अन्य सामान, अगर बाजार में विभिन्न चीजों की आपूर्ति कम हो जाए तो यह प्रबंधन के लिए नई चुनौती है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन मौसम बदल रहा है, प्रतिदिन बाढ़-बारिश आ रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग शिक्षकों एवं छात्रों के लिए यह बड़ी चुनौती और बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें इसका हल निकालना होगा कि हम इन 'न्यू नॉर्मल' स्थितियों में कैसे जीवित रहें क्योंकि आज की तारीख में मानवता का बचना ही दांव पर लगा है। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि यह मानवता की आखिरी सदी है। इसके बाद पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी का इतनी तेजी से क्षरण हो रहा है। हर तरफ ग्लेशियर बेहद तेजी से पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से सारे समुद्रों में पानी बढ़ रहा है, पूरी धरती अस्त-व्यस्त है। हम रोज तीव्र मौसम का सामना कर रहे हैं और इसे महसूस कर रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान दे सकते हैं। यदि हम इस प्रासंगिक और चुनौती पूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे और इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रम और शोध निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिह्न लग जाएगा। आज अगर मानवता को नए 50 डिग्री के तापमान पर जीना है तो हमारी मेडिकल साइंस को इसके अनुसार काम करना होगा। हमें यह अनुमान लगाना होगा कि नई बीमारियां कैसी होंगी और इनके क्या नए उपचार होंगे। हमने आज तक सतत रूप से 50 डिग्री तापमान का सामना नहीं किया है।

आगे उन्होंने कृषि क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए बताया

देश को नेतृत्व में सक्षम युवाओं की जरूरत

जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्यमार्ग राज्य मंत्री

छठे डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवें डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडेमिया अवार्ड फंक्शन-2022 के दौरान **केंद्र सरकार में सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्यमार्ग राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)** ने नई शिक्षा नीति को सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बताया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने सबसे पहले डायलॉग मीडिया को बधाई दी कि उन्होंने नई शिक्षा नीति पर विचार-मंथन के लिए विभिन्न विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्हें चर्चा का मंच उपलब्ध करवाया। उन्होंने डायलॉग इंडिया द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग पर भी प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से शैक्षणिक जगत में प्रतिस्पर्धा आएगी और गुणवत्ता को परिमाणित किए जाने में सहायता मिलेगी।

इसके बाद नई शिक्षा नीति पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि नई नीति शिक्षा जगत और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि पहले पाठ्यक्रम में राष्ट्र-संस्कृति का ज्ञान मिलता था परंतु कुछ समय से यह परिदृश्य बदल गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की लक्ष्मीबाई पर लिखी कविता का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले हमारी स्कूली किताबों में देशप्रेम, संस्कृति और इतिहास के बारे में पर्याप्त सामग्री होती थी लेकिन अब विश्व भर की जानकारी बच्चों की किताबों में समाहित करने के प्रयासों चलते हमारी किताबें एनसाइक्लोपीडिया जैसी बन गई हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बच्चों की किताबें आसान और सहज

भाषा में लिखी जानी चाहिए। उनके बताया कि आज के छात्र पहले की अपेक्षा में अधिक मेधावी, तेज और कुशाग्र है परंतु उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिलता जहां वे सीख सकें, सीखने की प्रक्रिया में गलती कर सकें या गहन जानकारी ले सकें।

भारत में उच्च शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि हमें विश्व के प्रत्येक देश से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। अमेरिका का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां बचपन में बच्चों के दिमागों में जानकारी का भंडार भरे जाने के बजाय इस बात पर बल दिया जाता कि वे जानकारी हासिल करना, इसे संसाधित करना और अभिव्यक्त करना सीखें। ऐसे में बच्चों पर किताबों का ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता हालांकि कॉलेज और विश्वविद्यालय में उन्हें मौलिक शोध और ज्ञान अर्जन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारत में भी हमें ज्ञान अर्जन एवं परिणाम आधारित शिक्षा मॉडल अपनाना होगा। हमें उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा के मार्ग खोलने होंगे। यह सब चीजें सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति में अधिकाधिक विकल्प और मार्ग उपलब्ध करवाए गए हैं। उच्च शिक्षा पर अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ पढ़े-लिखे युवाओं के बजाय नेतृत्व करने में सक्षम युवा चाहिए।

विषय से इतर राजनीति में उनके प्रवेश पर प्रश्न पूछे जाने पर श्री सिंह ने बताया कि वह बहुत सोच-समझकर राजनीति में नहीं आए। यह सब अचानक और बिना किसी योजना के हो गया। सेना में 42 बिताने के देश से मिले सम्मान, आदर और प्रेम को लौटाने के लिए वह राजनीति में आए।

नए और पुराने भारत का संगम नई शिक्षा नीति

अश्विनी कुमार चौबे

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

छठे डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवें डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडेमिया अवार्ड फंक्शन-2022 के दौरान प्रतिभागियों को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मंत्री महोदय ने नई शिक्षा नीति को समुद्र मंथन से जोड़ा। डायलॉग इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा पर चर्चा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे विचार-विमर्श से सरकार को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन संबंधी रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन शिक्षा प्रणाली को समाहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि आज के विकसित देशों में जब विकास की पहली किरण भी नहीं पहुंची थी तब भारत में उत्तम शिक्षा व्यवस्था थी। आज सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के बारे में हमें वैज्ञानिक बताते हैं परंतु भारत में आज से लाखों वर्ष पहले उज्जैन के वेदपाठी पंडित बिना किसी कम्प्यूटर की सहायता से इसकी सटीक जानकारी देते थे। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली मात्र व्यवसाय देने तक सीमित नहीं थी बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास का साधन थी। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था 'असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।' अर्थात असत्य से सत्य और अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के विचार पर आधारित थी। यह प्रणाली व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक चेतना जगाने के साथ-साथ समग्र सामाजिक और सांस्कृतिक एकता सुनिश्चित करती थी। इसका पाठ्यक्रम बेहद व्यापक था और यह मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चारों पक्षों को उजागर और विकसित करती थी।

उन्होंने खेद जताया कि आज की शिक्षा में इन चीजों का अभाव है। हमने मैकॉले द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा प्रणाली अपना ली है जो अंग्रेजों ने हमें क्लर्क बनाने के तैयार की थी। आज हमारे बच्चे स्कूल बैग के बोझ तले दबे हैं।

शिक्षा के उद्देश्य पर प्राचीन भारत की संकल्पना के बारे में बताते हुए उन्होंने ऋग्वेद के दसवें मंडल से उद्धृत किया कि इसमें वेद एवं कर्मकांड के ज्ञान के साथ-साथ समाज में सम्मान प्राप्त करना, सभा-समितियों में संभाषण करने में सक्षम होना और उचित-अनुचित का बोध होना शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में वर्णित है। उन्होंने इस तरह प्राचीन काल में शिक्षा के बेहद व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सभी को कार्य के अनुरूप शिक्षा देने की व्यवस्था थी। हमारे मंदिर और आश्रम आवासीय विद्यालयों या विश्वविद्यालयों के रूप में शिक्षा प्रदान करते थे। उन्होंने चाणक्य के श्लोक 'पुत्राश्च विविधैः शीलैर्नियोज्याः सततं बुधैः। नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताःद्यद्य' और 'माता शत्रु - पिता वैरी येन बालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।।' जैसे श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहा कि अपनी संतानों को शिक्षित करना प्राचीन भारत में माता-पिता का मुख्य दायित्व माना गया है।

उन्होंने कहा कि नालंदा, विक्रमशिला एवं तक्षशिला हमारे इतिहास के तीन विश्वविद्यालय इसका प्रमाण है कि प्राचीन काल में भारत शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर था। मैत्रेयी, गार्गी, घोषा और लोपामुद्रा का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राचीन शिक्षा में नारी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। फिर उन्होंने उभय भारती द्वारा शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य को परास्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में प्रत्येक कालखंड में महिलाओं को उच्च शिक्षा और सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। इस स्थिति को वर्तमान हालात से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा लगाना पड़ रहा है, यह वस्तुतः हमारा पतन है। उन्होंने 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' के श्लोक को इसका प्रमाण बताया कि नारी का सम्मान हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल तत्व है।

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में चौथे लक्ष्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है परंतु भारत में शिक्षा सदैव से ही समावेशी रही है। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा का एक साथ पढ़ना इसका प्रमाण है कि हमारे आश्रमों में विशिष्ट और सामान्य दोनों के साथ-साथ पढ़ने की व्यवस्था थी। उन्होंने राजा जनक द्वारा अपनी शंका-निवारण दिव्यांग ऋषि अष्टावक्र से करवाने को भी समावेशी शिक्षा-व्यवस्था का उदाहरण बताया।

नई शिक्षा नीति के बारे में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आधुनिक शिक्षा में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली को समायोजित कर नई शिक्षा नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि नई नीति में छात्रों को ज्ञानवान बनाने के साथ प्रकृति, संस्कृति और संस्कार उन्मुख बनाया जाएगा। मोदी सरकार का प्रयास है कि विश्व के सौ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के परिसर भारत में खुलेंगे। इससे हमारे युवाओं को भारत में विश्व-स्तरीय शिक्षा मिल पाएगी और वह विदेश आने-जाने और वहां रहने के खर्च से बच सकेंगे।

उन्होंने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और गुणवत्ता आकलन को संस्थागत रूप देने के प्रयासों के लिए डायलॉग इंडिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि किसी प्रतिष्ठित एवं निष्पक्ष संस्थान द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाए और डॉयलाग इंडिया बेहद प्रामाणिकता से यह काम कर रहा है।

'हमारी कृषि उपज सिकुड़ रही है और हमारी प्रकृति सिकुड़ रही है। इस वर्ष के डेटा के अनुसार गेहूं की फसल 20% तक कम हुई है और धान की फसल 30% तक कम हुई है।' ऐसे में मानवता के सामने बड़ा प्रश्न है कि फसल कम होने पर हम कैसे जी पाएंगे, विश्व की 800 करोड़ आबादी कैसे जी पाएगी। ऐसे में हमारे कृषि संस्थानों के लिए यह बड़ी चुनौती है कि ज्यादा तापमान में कम पानी से ज्यादा फसल देने वाली कृषि पर शोध किया जाए। आज की तारीख में कई निजी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। उनके लिए यह अच्छा अवसर है कि वे इन शोध विषयों पर काम करें। यदि हम इन मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो हमारे संस्थान एशिया और विश्व की उम्मीद बन जाएंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो संस्थान अप्रासंगिक और बंद हो जाएंगे।

आगे उन्होंने डिजिटलाइजेशन के नए दौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी दुनिया तेजी से डिजिटलाइज हो रही है। सारे पाठ्यक्रम डिजिटलाइज हो रहे हैं। आज सब कुछ युट्यूब पर उपलब्ध है। सरकार सौ नए चैनल ला रही है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि कक्षा में शिक्षक से कौन पढ़ेगा, शिक्षक की क्या प्रासंगिकता होगी। आगे भविष्य में सब कुछ वर्चुअल होगा। वर्चुअल कक्षाओं में शिक्षक वर्चुअल होंगे। अगर किसी समूह के बीस संस्थान हैं तो बीस स्थानों पर बीस शिक्षक रखने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक एक स्थान से बीस संस्थानों में पढ़ा सकेगा। उन्होने बताया 'इससे आगे शिक्षक नियोजित करने की जरूरतों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह कहीं भी पुराने तौर-तरीके कारगर नहीं होंगे। हमें नई परिस्थितियों से स्वयं को समायोजित करना होगा और चुनौतियों पर विजय पाकर अपना अस्तित्व सुनिश्चित करना होगा।'

अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने मौजूद लोगों से आग्रह किया कि इन सब चुनौतियों और बदलते हालातों बीच हमें प्रसन्न रहना भी सीखना है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 संकटों के बीच हम मुस्कराना और प्रसन्न रहना ही भूल गए हैं। आगे उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले विशेषज्ञों और चिंतकों से आह्वान किया कि वे भारत-केंद्रित और पर्यावरण-अनुकूल शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए समाज का मार्गदर्शन करें।

PANEL DISCUSSION - 1

TOPIC : SWOT ANALYSIS OF INDIAN HIGHER EDUCATION

नैतिक और मूल्य आधारित होनी चाहिए शिक्षा

'भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूतियों, कमजोरियों, अवसरों एवं खतरों (SWOT) का विश्लेषण' पर पहली पैनल चर्चा का संचालन **डायलॉग इंडिया समूह के वरिष्ठ पत्रकार और कार्यकारी संपादक अमित त्यागी** द्वारा किया गया। इस चर्चा में डॉ. नूतन शर्मा, पूर्व मुख्य आयुक्त, आयकर; श्री दिगवंता चक्रवर्ती, क्षेत्रीय निदेशक एवं मानव संसाधन प्रमुख, ट्रिनिटी लाइफ साइंसेस; गुरु पवन सिन्हा; श्री कुणाल गुप्ता, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, माउंट टैलेंट; श्रीमती शोभना नारायण, कत्थक नृत्यांगना और श्री सिद्धार्थ जैन, फ्लेयर महासचिव, ईपीएसआई सलाहकार ने भाग लिया। चर्चा की शुरूआत करते हुए श्री अमित त्यागी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विरोधाभासी स्थिति पर ध्यान दिलाया कि भारत में एक तरफ बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षित लोग है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ गैर-संगठित क्षेत्र में लाखों ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

● ● ●

चर्चा की शुरुआत करते हुए **श्री कुणाल गुप्ता, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक, माउंट टैलेंट** ने कहा कि अगर हम पांच वर्ष में लाभप्रद रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा पाए तो हमारा देश अराजकता की तरफ बढ़ेगा। आज विश्व ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां रोजगार नहीं होने की स्थिति में लोगों को रोजगार भत्ता या सार्वभौमिक आय प्रदान किए जाएंगे। ऐसे में बेरोजगारी की स्थिति नई तरह की समस्याएं खड़ी करेगी। देश की शिक्षा समस्याओं पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाती है जबकि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा मात्र अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। कई छात्र स्थानीय भाषाओं में शुरुआती शिक्षा लेने के चलते उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणाएं समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में छात्र उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए नामांकन नहीं करवाते हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इस तरह हमें छात्रों के भाषायी ज्ञान पर भी ध्यान देना होगा। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने आगे कहा कि मात्र दसवीं के बजाय व्यावसायिक शिक्षा करने वाले बच्चों की कमाई दोगुनी होगी। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता पर किया गया निवेश समाज और व्यक्ति दोनों के लिए लाभदायक है। उन्होंने रोजगार के अधिकाधिक अवसर निर्मित करने के लिए सरकार से लघु और मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सरकारें इन उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाती हैं और ऋण के प्रावधान करती हैं परंतु ये सब प्रयास जमीन पर नहीं उतर पाते। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम छात्रों को संस्थानिक व्यवहार और टीम में काम करने के कौशल सिखाएं। उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा को समय की जरूरत बताया। उनके अनुसार जब तक हम छात्रों को नैतिकता और मूल्यों का ज्ञान नहीं देंगे तब तक हम चरित्रवान चिकित्सक और चरित्रवान सीए या सीएस तैयार करने की उम्मीद नहीं कर सकते।

● ● ●

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए **अध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा** ने कहा कि आज हमारा समाज बढ़ते अपराधों, परिवारों के टूटने और युवाओं में विनम्रता के बजाय आक्रामकता की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके अनुसार इन समस्याओं का कारण यह है कि हम आज शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों को उचित स्थान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में शिक्षा के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में साधन संपन्न लोग शामिल हैं जिनके पास सभी साधन और बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध है परंतु मूल्य रहित शिक्षा के चलते यह वर्ग इतना भटक रहा है कि राष्ट्रीयता तक से दूर हो गया है। शिक्षा के आजीविका और नैतिकता संबंधी लक्ष्यों पर अपने विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा को मूल्यों और नैतिकता के बजाय धनार्जन का साधन माना जाता है। ऐसे में अपराधीकरण, समाज का पतन, परिवारों का टूटना और युवाओं में स्वच्छंदता और आक्रामकता का बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने में शिक्षण संस्थानों और परिवार-समाज दोनों की बराबर भूमिका है। उन्होंने जानकारी दी कि उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल में शिक्षा को मानव निर्माण से जोड़ने का आंदोलन था परंतु वर्तमान में हमारी शिक्षा और सरकारी मान्यता आदि के मानक मानवीय विकास के बजाय तंत्र आधारित है। ऐसे में तंत्र का हावी होना स्वाभाविक है। उन्होंने इतिहास के अत्यधिक महिमामंडन से भी बचने की सलाह दी। उनके अनुसार हमें बार-बार इतिहास में जाने के बजाय वर्तमान समस्याओं का समाधान तलाशना होगा।

● ● ●

आयकर में **मुख्य आयुक्त के पद पर कार्यरत रह चुकी डॉ. नूतन शर्मा** ने इस पर खेद जताया कि आज हमारी शिक्षा से हमारे धर्मग्रंथों आदि पर आधारित नैतिकता-उन्मुख शिक्षा बाहर चुकी है। उन्होंने ययाति का उद्धरण देते हुए कहा कि हमारे छात्रों को पढ़ाए जाने पर यह प्रसंग छात्रों को सिखाएगा कि धनार्जन या भोग जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। नैतिकता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा ही भ्रष्टाचार समाप्त कर सकती है और युवाओं में समाज के प्रति सरोकार, संतोष और धैर्य जैसे गुण ला सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के धनार्जन और नैतिकता संबंधी लक्ष्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।

● ● ●

श्री दिगवंता चक्रवर्ती, क्षेत्रीय निदेशक एवं मानव संसाधन प्रमुख, ट्रिनिटी लाइफ साइंसेस ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज हमारे छात्र किताबों का गहन अध्ययन करने के बजाय गूगल, युट्यूब और वाट्सएप से मिलने वाली त्वरित जानकारी पर भरोसा करते हैं। हम आज के समय से पीछे चल रहे हैं। 1193 में खिलजियों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आक्रमणकारियों ने हमें नष्ट करने के लिए हमारी ज्ञान परंपरा नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें शिक्षा की मजबूतियों, कमजोरियों, अवसरों एवं खतरों पर चर्चा करने के बजाय इसकी मजबूतियों एवं अवसरों पर चर्चा करनी चाहिए।

● ● ●

कथक नृत्यांगना श्रीमती शोभना नारायण ने आज सूचना के भरमार और सफलता की होड़ के माहौल से अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि ज्ञान में हमारा स्वर्णिम इतिहास वस्तुतः तर्क एवं जिज्ञासा पर आधारित है जबकि आज हम रट्टा मार रहे हैं। प्राचीन भारत में तर्क की प्रधानता पर

उन्होंने कहा कि भागवत गीता पर 200 भाष्य उपलब्ध हैं, इन भाष्यों में गीता की विभिन्न मतों एवं दर्शनों के अनुसार व्याख्या की गई है। ये व्याख्याएं जिज्ञासा और तर्क की हमारी परंपरा की प्रतीक है। हमें स्कूल और कॉलेज में आलोचनात्मक एवं तर्क-आधारित अध्ययन की शुरूआत करनी होगी। उन्होंने इस तरफ सब का ध्यान दिलाया कि हमारे युवा विदेशों में शोध सुदृढ़ कर रहे हैं परंतु भारत में हम शोध अनुकूल परिस्थितियां नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समकालीन शिक्षा के पतन का प्रभाव कलाओं पर भी पड़ा है और वहां भी पतन हुआ है। उनके अनुसार ऐसे भी युवा हैं जिनके पास नृत्य की डिग्री है परंतु वे दो मिनट भी नृत्य नहीं कर पाते।

● ● ●

श्री सिद्धार्थ जैन, फ्लेयर महासचिव, ईपीएसआई ने अपने विचार स्पष्ट किए कि नैतिकता और मूल्य सिखाना शिक्षण संस्थानों के बजाय परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। मात्र संस्थान नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते। युवा अपने परिवारों और समाज का जैसा आचरण देखते हैं, वे वैसा ही आचरण करते हैं। अगर बच्चे आज अपने माता-पिता को दादा-दादी की सेवा करते देखेंगे तो वह भी अपने माता-पिता की सेवा करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सक्षमता आधारित एवं परिणाम आधारित शिक्षा भारत के लिए नई अवधारणाएं नहीं है। प्राचीन काल में गुरुकुलों और आश्रमों में छात्रों को उनकी योग्यता और सामर्थ्यों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी।

PANEL DISCUSSION - 2

IMPLEMENTATION: CHALLENGES AND WAY FORWARD

शोध में सुधार से संवरेगी उच्च शिक्षा की तस्वीर

छठे डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवें डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडेमिया अवार्ड फंक्शन-2022 के दौरान 'नई शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन : चुनौतियां और आगे का रास्ता' विषय पर दूसरी पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा का संचालन **प्रोफेसर प्रमोद सैनी, आईआईएमसी** ने किया। इस चर्चा में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णु कांत चतुर्वेदी; श्री शाश्वत शर्मा, सीईओ, नोवा इवेंट्स; योगेश एंडले, प्रबंधन और आईटी गुरु (आईआईटी और एमआईटी); प्रो. विजय कुमार श्रोत्रिय, वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉ मनीष गौड़, एकेटीयू प्रो वाइस चांसलर ए.के.टी.यू. एवं प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ ने अपने विचार रखे।

● ● ●

चर्चा की शुरुआत करते हुए **प्रोफेसर प्रमोद सैनी, आईआईएमसी** ने डॉयलाग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल के भारत-केंद्रित और प्रकृति-केंद्रित शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि हमारा कार्यक्रम कमोबेश भारत और प्रकृति पर केंद्रित है। फिर प्रतिभागियों को नई शिक्षा नीति से अवगत करवाते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति में उच्च शिक्षा में छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान के 26.3% आंकड़े से 2035 में 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 5000 करोड़ के बजट प्रावधान से राष्ट्रीय शोध फांउडेशन बनाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन कदमों से भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति बेहतर होगी। इसके साथ ही उन्होंने शोध में बहु-आयामी दृष्टिकोण और शैक्षणिक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने का भी समर्थन किया। उनके अनुसार शोध केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इनमें सरकारों और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका है और दोनों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

● ● ●

चर्चा के दौरान **प्रो. विजय कुमार श्रोत्रिय** ने कहा कि नीति बनाना आसान है परंतु इसे लागू करना असली चुनौती है। उन्होंने बताया कि हमारी पुरानी शिक्षा नीति रटने को बढ़ावा देती थी जबकि नई नीति से इसमें नए हस्तक्षेप लाए गए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षण का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा देश प्रतिवर्ष 16 लाख इंजीनियर तैयार करता है परंतु नैसकॉम के अध्ययन के अनुसार इनमें से मात्र 10% ही रोजगार प्रदान किए जाने योग्य हैं। उन्होंने आगे बताया कि नई नीति में छात्रों को प्रत्येक स्तर पर लचीलापन दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित विषय चुनने की आजादी देने को सार्थक बनाने के लिए बुनियादी ढ़ांचे की व्यवस्था करनी होगी और शिक्षाविदों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। नई नीति की शोध संबंधी पहलों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सही दिशा की तरफ उठाया गया कदम है और हम बेहतर शिक्षण संस्कृति की उम्मीद कर सकते हैं।

● ● ●

योगेश एंडले, प्रबंधन और आईटी गुरु ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज हमारी शिक्षा पढ़े-लिखा युवा तैयार कर रही है परंतु हमारे व्यवसायों को दूरदृष्टि रखने वाले और सब को साथ लेकर चलने में सक्षम लीडर नहीं मिल रहे हैं। उनके अनुसार आज हम ऐसे पेशेवर तैयार कर रहे हैं जो बड़े लक्ष्यों के बजाय मात्र अपने पैकेज तक सीमित हैं। हमारी शिक्षा जानने, करने और होने अर्थात स्वयं को जानने के मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव साझे करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति से पहले यदि कोई संस्थान अपने स्तर पर नवाचार या बदलाव लाने का प्रयास भी करता तो सरकारी संस्थाओं से उन्हें मान्यता नहीं मिल पाती। उन्होंने एमबीए की उदाहरण देते हुए बताया कि एमबीए पाठ्यक्रम की अब तक संकल्पना इस लक्ष्य पर आधारित है कि व्यवसाय नैतिकता से व्यवसाय करते हुए अधिकतम लाभ कमा सकें। पीएचडी की वर्तमान स्थिति का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि आज हम सैकड़ों पीएचडी अध्येता तैयार कर रहे हैं परंतु शोध की गुणवत्ता खराब होने के चलते हमारी अर्थव्यवस्था को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

● ● ●

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णु कांत चतुर्वेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारे देश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के अभाव का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। नेताओं और नौकरशाहों के भ्रष्ट गठबंधन के चलते कई ऐसे निजी संस्थान खुले हैं जो ज्ञान के बजाय मात्र डिग्रियां बांटते हैं। उन्होंने इस परिदृश्य पर उम्मीद जताई कि विदेशों में ज्ञान-आधारित नौकरियों पर ज्यादातर भारतीयों का कब्जा है और हमारे आईआईटी, आईआईएम एवं एनआईटी जैसे संस्थान वैश्विक स्तर के स्नातक तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थान अधिकाधिक खोले जाने चाहिए।

● ● ●

शिक्षा में प्रौद्योगिकी और मानवीय श्रम के परस्पर संबंधों पर अपनी बात रखते हुए **नोवा इवेंट्स के सीईओ श्री शाश्वत शर्मा** ने कहा कि प्रौद्योगिकी मानवीय भूमिका को खत्म कर नहीं कर सकती है। बच्चे स्कूल जाकर सहयोग और सामुदायिक भावना भी सीखते हैं। उनके अनुसार शिक्षकों को हालांकि नई प्रौद्योगिकियां सीखनी और अपनानी होगी परंतु शिक्षा में मानवीय भूमिका का महत्व बरकरार रहेगा।

PANEL DISCUSSION - 3

THE GLOBAL DESTINATION FOR HIGHER EDUCATION

वैश्विक हब बनने के लिए भारत को वैश्विक जरूरतों के अनुसार ढ़लना होगा

छठे डायलॉग इंडिया एकेडेमिया कॉन्क्लेव और आठवें डायलॉग इंडिया इंटरनेशनल एकेडेमिया अवार्ड फंक्शन-2022 के दौरान 'भारत- उच्च शिक्षा की वैश्विक मंजिल' विषय पर तीसरी पैनल चर्चा के दौरान इस बारे में गहन मंथन हुआ कि शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत के ऐतिहासिक गौरव को दोबारा कैसे बहाल किया जाए। चर्चा के संचालन के दौरान श्री ओंकारेश्वर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व समूह संपादक राष्ट्रीय सहारा ने पैनल सदस्यों के सामने प्रश्न खड़ा किया कि नई शिक्षा नीति अब हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद अब शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन और इस नीति के कार्यान्वयन में ऐसा क्या किया जाए जिससे सारे विश्व के छात्र भारत की तरफ आकर्षित हों।

● ● ●

चर्चा की शुरुआत करते हुए **डॉ उर्वशी मक्कड़, निदेशक, आईएमएस, गाजियाबाद** ने कहा कि भारत में शिक्षा के वैश्वीकरण लाने का अर्थ यह नहीं है कि हम भारतीय मूल्य या संस्कृति छोड़ दें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन मूल्यों को सुदृढ़ करने के प्रति शिक्षकों की सर्वाधिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की हम अपनी युवा पीढ़ी को आजादी के महत्व और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना नहीं सिखा पा रहे हैं। हमें यह स्थिति बदलनी होगी।

● ● ●

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए **डॉ कुमार कृष्ण, सीटीओ, नासा, अमेरिका** ने अपनी राय व्यक्त

की कि भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की मुहिम में विदेशों में बसे भारतीयों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमें अपना नैरेटिव विश्व के सामने रखना होगा। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि विद्या सदैव हमारी केंद्रीय थीम रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत विविधताओं, विविध भाषाओं, विविध पंथों एवं संप्रदायों का देश है। इन विविधताओं के चलते भारत वस्तुत: मिनी विश्व है। यदि इस तथ्य का प्रचार-प्रसार किया जाए तो विश्व भर के लोग भारत की तरफ आकर्षित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्व को यह समझाना होगा कि पृथ्वी एवं पर्यावरण परिवर्तनों से निपटने में विश्व एवं ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोने वाली भारत की एकीकृत शिक्षा ही कारगर है। उन्होंने भारत के तीन मूल्यों सत्य-अहिंसा-विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें यह नैरेटिव गढ़ने के साथ-साथ इन मूल्यों के शिक्षण की भी उचित व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने भारत की शिक्षा के वैश्वीकरण संबंधी प्रयासों में योग को अहम सूत्र बताया। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि आज पूरा विश्व योग के बारे में जानना और इसे सीखना चाहता है। भारत में इसके शिक्षण की व्यवस्था करके हम अपनी शिक्षा के वैश्वीकरण की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।

• • •

चर्चा में अपना मत व्यक्त करते हुए **प्रो (डॉ.) प्रसनजीत कुमार, उप कुलपति, एनआईयू** ने कहा कि नई शिक्षा नीति सरकार का साहसी कदम है। इस नीति में जिस वैश्वीकरण का सपना देखा गया, वह सपना तभी साकार हो सकता है यदि हम वैश्विक परिदृश्य को समझें। हमें यह समझना होगा कि हम जिन छात्रों को भारत की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है और वे क्या चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्वीकरण के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें अपने बुनियादी ढ़ांचे को विश्व-स्तरीय बनाना होगा और पाठ्यक्रम में वैश्विक जरूरतों के अनुसार परिवर्तन लागे होंगे। अपने संस्थान का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वह अपने संस्थान में रूस के छात्रों को पढ़ाने के इच्छुक थे। बेहद उत्कृष्ट बुनियादी ढ़ांचा होने के बावजूद रूस के सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे पाठ्यक्रम में रूस की जरूरतों के अनुसार बदलाव करने का अनुरोध किया। ऐसे में विदेशी छात्र आकर्षित करने और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों-सरकारों से सहयोग करने में सक्षम होने के लिए सरकार को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वायतत्ता प्रदान करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत में शिक्षा के वैश्वीकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए हम सहयोग एवं समझौता ज्ञापनों का मार्ग चुन सकते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय शिक्षण संस्थान अफ्रीकी देशों सहित मुख्यत: विकासशील देशों के छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं।

• • •

चर्चा का समापन करते हुए **भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत श्री नीरज कुमार** ने भारत को शिक्षा का वैश्विक हब बनाने के लिए पैनल सदस्यों और प्रतिभागियों से अपना पंच-विधा मॉडल साझा किया। अपनी बात स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बाजार आज 200 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है और 2030 तक यह आंकड़ा 430 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अपने देशों से बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आज के 50 लाख के स्तर से बढ़कर अगले तीन वर्षों में 80 लाख तक पहुंच जाएगी जबकि भारत में आकर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या मात्र 50 हजार तक सीमित है। वर्तमान में हम मुख्यत: अपने पड़ोसी देशों से ही छात्र आकर्षित कर रहे हैं, जबकि हमें अपने स्रोत देशों में विविधता लानी होगी। अपने पंच विधा मॉडल के घटकों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हम अफ्रीकी देशों से मेडिकल छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल पर्यटन के चलते अफ्रीका के लोग भारत के चिकित्सा ढ़ांचे से अवगत हैं। ऐसे में हम चिकित्सा की पढ़ाई के लिए अफ्रीकी छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों में बाल स्वास्थ्य और नर्सिंग सेवाओं के अध्ययन के लिए छात्र आकर्षित किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग विषयों के अध्ययन के लिए ईरान एवं मध्य-पूर्व देशों से छात्र भारत आ सकते हैं। इनके अलावा उन्होंने बौद्ध अध्ययन और एकीकृत जीवन के अध्ययन विषय शुरू करने का भी सुझाव दिया। उनके बताया कि पश्चिमी देशों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती समस्याओं के चलते इन विषयों के प्रति रुचि बढ़ रही है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक शिक्षा हब बनने के लिए भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाने की दिशा में लगातार काम करना होगा। हमें विदेशी छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में सरचनात्मक बदलाव लाने होंगे। इसके अलावा देश को बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और कार्मिकों के प्रशिक्षण में भारी निवेश करना होगा। हमें विदेशी छात्रों को प्रतिबद्ध सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थानों में ही वीसा परामर्श एवं समाधान सेवाएं, आरामदायक आवास इत्यादि उपलब्ध करवाने होंगे। साथ ही, हमें अश्वेत लोगों के प्रति फोबिया एवं

HONOUR OF PANALIST & SPECIAL GUEST IN DIALOGUE INDIA ACADEMIA CONCLAVE-2022

HONOUR OF PANALIST & SPECIAL GUEST IN DIALOGUE INDIA ACADEMIA CONCLAVE-2022

GLIMPSE OF DIALOGUE INDIA CONCLAVE

GLIMPSE OF DIALOGUE INDIA CONCLAVE

करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी का रजत जयंती समारोह

भारतीय शिक्षा के स्वदेशीकरण का समय

करियर प्लस ने लिया नये लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प

Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha, Managing Director, Career Plus Group.

करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी का रजत जयंती समारोह 6 अगस्त 2022 को शंगरी-ला होटल में मनाया गया। इस अवसर पर भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य के बारे में गहन चर्चा और विचार-मंथन हुए। शिक्षा क्षेत्रों के अग्रणी लोगों,कद्दावर राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन की हस्तियों ने उच्च शिक्षा के भविष्य के बारे में अपने विचार साझे किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई जिसके पश्चात राष्ट्रगान और गणेश वंदना किए गए। अपने शुभारंभ भाषण में करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंध निदेशक अनुज अग्रवाल ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने निरंतर सहायता और समर्थन के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र में मची भारी उथल-पुथल के बीच, सोसाइटी ऑनलाइन माध्यमों से छात्रों तक पहुंचने का प्रयास किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने अपने भाषण की शुरुआत में समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों को शिक्षा देने और अपने 25 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सोसाइटी से यह आग्रह किया कि यह अपना उत्कृष्ट कार्य जारी रखे और समाज के अधिक से अधिक वर्गों तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाए। उन्होंने सोसाइटी की भविष्य की योजनाओं के लिए निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। श्री अठावले ने 'अटल स्मृति व्याख्यान' के दौरान समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्होंने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित और प्रशंसा प्राप्त प्रधानमंत्रियों में से एक बताया। श्री अठावले ने उन्हें शालीनता, गरिमा और मर्यादा का मूर्त रूप बताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, प्रशासक, कवि और व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कवि हृदय की संवेदनशीलता ने श्री वाजपेयी को प्रभावशाली लोगों के हितों की पूर्ति करने के बजाय आम जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चल रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से बल दिया कि वर्तमान सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' विचारधारा वर्तमान सरकार के श्री वाजपेयी के आदर्शों के प्रति सम्मान का प्रमाण है। उन्होंने आगे शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की पहलों को रेखांकित किया। उनके अनुसार, नई शिक्षा नीति भारतीय उच्च शिक्षा की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी और भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने की ओर ले जाएगी।

इस अवसर पर इफको के उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समाज के वंचित लोगों तक ज्ञान के प्रसार के लिए करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी की प्रशंसा की।

राज्यसभा के पूर्व महासचिव श्री योगेंद्र नारायण ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के बारे में चर्चा की। विमुद्रीकरण और जीएसटी के मुद्दों पर वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अर्थव्यवस्था को अपराधीकरण से बचाने और कराधान प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानती है जिनके लिए लोगों का कल्याण सर्वोपरि था। उन्होंने कवि प्रधानमंत्री को याद करने के लिए करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी की भी सराहना की। शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र सिंह शांति ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने अनुभव साझा किए। श्री शांति ने इस मुश्किल समय के दौरान बचाव दल का गठन किया और शवों को श्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी।

आयोजन के दौरान, प्रतिष्ठित शिक्षकों को सफल समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉ विजय वर्मा, प्रोफेसर, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय; डॉ राजेंद्र कुमार, प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और डॉ रमेश प्रसाद, पाली प्रोफेसर पुरस्कृत शिक्षकों की सूची में शामिल हैं। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी विचार व्यक्त किए। करियरप्लस ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनुज अग्रवाल और नीरज कुशवाहा द्वारा सोसाइटी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी गई और नया प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 'संकल्प से सिद्धि पुरस्कार-2022' से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन होप एंड फेथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया।

करियर प्लस एजुकेशन सोसायटी का रजत जयंती समारोह एवं अटल स्मृति व्याख्यान

समावेश एवं समन्वय की मूर्ति थे अटल बिहारी

रामदास अठावले

केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

करियर प्लस एडूकेशनल सोसाइटी की रजत जयंती के इस शुभ अवसर पर, आपकी 25 वर्षों के सतत संघर्ष और अपने सामाजिक लक्ष्य की इस साधना का फल है कि आज आप सभी विद्वतजन, एकेडमिक दुनिया से जुड़े धुरंधर इस कार्यक्रम में आज एकत्रित हुए हैं। मैं आपके इस सहयोग और सामूहिक सफलता के लिए ढेरों बधाईयाँ और और शुभकामनाएं देता हूँ।

साथियों, मुझे ज्ञात हुआ कि आज एक विशेष व्याख्यान सत्र भी है, जो कि हमारे आदर्श और मार्गदर्शक, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की के जन्मसदी वर्ष व उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जा रहा, इसके लिए आयोजक संस्था करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी को मैं साधुवाद देता हूँ. ये संस्था सिविल सेवाओं के लिए प्रतिभागीओं के लिए पिछले 25 वर्षों से काम कर रही और मेरे मंत्रालय से भी जुडी है और सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी जो आपने निभाई है उसके लिए मैं संस्था के प्रबंधकों और इससे जुड़े सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों को बधाई देता हूँ।

मित्रों, वाजपेयी जी को सुशासन के लिए जाना जाता है और एक बेहतरीन नेतृत्व की मिसाल पेश करते हुए, जिस तरह उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, ये भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि सभी के लिए लीडरशिप को समझने और सुशासन के गुणों को सीखने का वृहत अध्याय है। सुशासन, सबसे उपयुक्त निर्णय लेने तथा इन निर्णयों के कार्यान्वयन की एक प्रक्रिया है, जिससे की सभी को संतुष्टि और न्यायपरक अवसर मिले। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर (अब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा) में हुआ था।

उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया। वर्ष 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिये एक पत्रकार के रूप में राष्ट्र धर्म (एक हिंदी मासिक), पांचजन्य (एक हिंदी साप्ताहिक) और दैनिक समाचार पत्रों-स्वदेश और वीर अर्जुन में काम करना शुरू किया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी जी वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1996 तथा 1999 में दो बार इस पद के लिये चुने गए थे। एक सांसद के रूप में वाजपेयी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें सभी सांसदों के लिये एक रोल मॉडल के रूप में परिभाषित करता है।

उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से और वर्ष 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका सम्पूर्ण जीवन वृत्त ही सुशासन के विद्यार्थियों के लिए आदर्श कुंजिका है।

शासन व्यवहारिक भाषा में मैनजेमेंट, डिसीजन मेकिंग आदि शब्द से बनता है जैसे कि कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय शासन। और इसको थोड़ा अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में वृहत दृष्टि और प्रो-एक्टिव अप्रोच ही निर्णय लेने में सहायक होता है।

सुशासन के आठ लक्षण संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताये गए हैं, वो हैं

भागीदारी : सभी स्टेकहोल्डर्स के विचारों को सुनकर समझकर, और निर्णय लेने से पूर्व उनके हितों का ध्यान रखते हुए ही योजना को आगे बढ़ाना, भागीदारी सुनिश्चित करता है। स्टेकहोल्डर्स द्वारा सीधे या वैध मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से भागीदारी अनिवार्य प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हों और साथ ही निर्णय लेने में लोगों को स्वतंत्र होना चाहिये।

विधि का शासन : कानूनी ढाँचा, विशेष रूप से मानव अधिकारों से संबंधित कानून सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए और यहाँ कोई भी शासन से परे या दायरे से मुक्त न हो।

पारदर्शिता : सुशासन के लिए आवश्यक है कि सूचना के मुक्त प्रवाह हो, और इसको लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है ताकि प्रक्रियाओं, संस्थाओं और सूचनाओं तक लोगों की सीधी पहुँच हो और उन्हें इनको समझने तथा निगरानी करने के लिये पर्याप्त जानकारी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहे।

जवाबदेही : संस्थाओं और प्रप्रि याओं द्वारा सभी हितधारकों को एक उचित समय सीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है।
आम सहमति : सुशासन के लिये समाज में विभिन्न हितों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में व्यापक सहमति बन सके कि यह पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
इक्विटी : सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना।
प्रभावशीलता और दक्षता : संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए ज़रूरतों को पूरा सकें।
जवाबदेही : सरकार में निर्णय लेने वाले निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ-साथ संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। बिना जवाबदेही सुनिश्चित किये व्यापक योजनाओं का निष्पादन संभव नहीं होता।

अब इन आठ अव्ययों के आलोक में अगर भारत को देखें तो हमारे देश में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी स्पष्ट हैं, और हम सभी इन चुनौतियों से निपटने के लिए दशकों से कार्य कर रहे.
महिला सशक्तिकरण में कमी : सरकारी संस्थानों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसके लिए सामाजिक बदलाव की जो आवश्यकता है, उसमे हम धीरे धीरे लगातार प्रोग्रेस कर रहे। महिलाओं की साक्षरता और भागीदारी पिछले दशकों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
भ्रष्टाचार : भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है। और हमने लगातार ऐसे मामले देखे भी हैं। ऐसी घटनाओं से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव समाज देश की मानसिकता पर पड़ता है और भ्रष्टाचार दीमक की तरह व्यवस्थाओं को नष्ट कर देता है। इससे कोई भी पहलू अछूता नहीं और भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी का विश्वास व्यवस्था से उठने लगता है। एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन कई कारक हैं, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस तरह के एक कारण के रूप में न्यायालयों में कर्मियों और संबंधित सामग्री की कमी है।
प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण : निचले स्तर की सरकारें केवल तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वे ऐसा करने के लिए सशक्त हों। यह विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रासंगिक है जो वर्तमान में निधियों की अपर्याप्तता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
राजनीति का अपराधीकरण : राजनीतिक प्रप्रि या का अपराधीकरण और राजनेताओं, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिक घरानों के बीच सांठगांठ सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।
गुड गवर्नेंस इंडेक्स : यानि GGI को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है। और अपने सुझाओं से गवर्नेंस की सुधार में बड़ी महती भूमिका निभा रहा है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना :

इसका उद्देश्य आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 'सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स' के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : की भूमिका को जितना सराहा जाए उतना कम है और ये वाकई में एक बड़ा हथियार जनता-जनार्धन के हाथों में है जिससे की हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। ये शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है।

इसके अलावा, कई अन्य पहल जैसे नीति आयोग की स्थापना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, लोकपाल आदि भी गुड गवर्नेंस की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले हैं।

भारत नयी शिक्षा नीति, नए बदलावों के आलोक में नित्य नए कीर्तिमानों को न केवल रच रहा बल्कि विश्व पटल पर अपनी महती भूमिका से आज विश्व की राजनीति, और डिसीजन मेकिंग में एक मजबूत स्तम्भ बना है। आप सभी लोग, जो सिविल सेवा परीक्षा और अन्य मैनेजमेंट संस्थाओं से जुड़े हैं, आप पर देश के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को तैयार करने का जो नैतिक दायित्व है, उसे आप पुरे समर्पण से निर्वाह करें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।

आपने मुझे यहा आमंत्रित किया, आप सुधि जनों से बात करने, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं करियर प्लस संस्था, उसे फाउंडर अनुज अग्रवाल जी सभी सभी टीम मेंबर्स, पार्टनर्स को धन्यवाद देता हूँ। रजत जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।

EMINENT SPEAKERS

Sh. Balbir Singh Ji, Vice president IFFCO

Sh. Yogendra Narain Former Secretary General, Rajya Sabha

Sh. Jeetendr Singh Shanti, Padma Shri, President, Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal

Dr. Ramesh Prasad,

Dr. Vijay Verma

Dr. Rajendra Kumar

Shri Jai Prakash
Ex. Mayor, North Delhi MCD

Dr. Anil Verma

Dr. Yashwant Chaudhary

Chief Guest of Silver Jubilee Celebration Career Plus

Sh. Balbir Singh, Vice-President, IFFCO, Sh. Ramdas Athawale, Minister of Social Justice & Empowerment, Sh. Yogendra Narain, former Secretary General of Rajya Sabha, Shaheed Bhagat Singh Seva Dal and Padma Shri Jeetendra Singh Shanti

Dr. Sarika Agarwal, Managing Editor, Dialogue India, Sh. Ramdas Athawale, Minister Govt. of India, Mr. Anuj Agarwal,Managing Director Career Plus

Mrs. Upma Kushwaha, Vice President, Career Plus, Shri Balbir Singh, Vice-President, IFFCO, Mr.Niraj Kushwaha, Managing Director, Career Plus

Sh. Yogendra Narain, Former Secretary General, Rajya Sabha, Sh. Amit Tyagi, Senior Journalist & Executive Editor, Dialogue India

Dr.Anil Verma, Founder & President, Hope & Faith Foundation(NGO), Sh. Jai Prakash Ex. Vice President & Municipal Councilor, Sadar Bazar Delhi, Mrs. Asha Verma, President , Jama Masjid Mandal, BJP

Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha, Managing Director, Career Plus with President of Shaheed Bhagat Singh Seva Dal and Padma Shri Jeetendra Singh Shanti

Awardees Civil Servant IAS-PCS

Sh. Himanshu Gupta, IAS, Director of Education, Delhi awarded by Shri Yogendra Narain, former Secretary General of Rajya Sabha

Sh. Surender Malik, Joint Commissioner, IRS, Delhi awarded by Ramdas Athawale, Minister of Social Justice & Empowerment

Rakesh Dahiya, IRS, Customs and Central Excise, Sonepat, Haryana by Ramdas Athawale, Minister of Social Justice & Empowerment,

Raghvendra Pratap Singh, IRS awarded by Ramdas Athawale, Minister of Social Justice & Empowerment

Karishma Paal, PCS awarded by IFFCO Vice-President Shri Balbir Singh

Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha, Managing Director, Career Plus with President of Shaheed Bhagat Singh Seva Dal and Padma Shri Jeetendra Singh Shanti

Career Plus Awardees: Mentor of Civil Service Examinations

Sh.Siddharth Jain, Secretary General at FLARE, Dr.Rajendra Kumar, Professor Delhi University

Mr.Gaurav Gupta, President, GTTCI, Dr. Ramesh Prasad, Prof.Sampurnanand Sanskrit University, Banaras

Mr. Sanjeev Sharma, Editorial Advisor, Dialogue India, Dr. Vijay Verma, Professor, Delhi University

Anuj Agarwal, MD Career Plus. Awardee Wing Commander (Retd.) S.K Sharma, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Karunesh Chaudhary, Awardee Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Dr. Anil Kumar, Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee R.K.Agarwal, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP MCD Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Dr. Anil Kumar, Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee Shankar Singh, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP MCD Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee Sanjay Vishwakarma, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP MCD Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, Managing Director, Career Plus

Dr.Anil Verma, Founder & President, Hope & Faith Foundation(NGO), Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee Sudhir Tripathi, Sh. Balbir Singh, VP, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP MCD Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Anuj Agarwal, MD Career Plus. Awardee Gopal Thakur, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, Vice President, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee Sulabh Dubey, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, Vice President, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee S.M Zaki Ahmad, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, Vice President, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Anuj Agarwal, MD Career Plus, Awardee Gagan Prakash, Sh. Yogendra Narain, Ex. Secretary Rajya Sabha, Sh. Balbir Singh, Vice President, IFFCO, Jai Prakash Ex. VP & Municipal Councilor Delhi, Padma Shri Jeetendra Singh Shanti, Niraj Kushwaha, MD, Career Plus

Career Plus Sankalp Se Siddhi Awards

Mr.Siddharth Jain,Secretary General at FLARE
Advisor EPSI & FICCI

Mr. Mayank Madhur, Film Producer

Mr. Sanjeev Sharma, Editorial Advisor, Dialogue India,

Mr. Yashwant Chaudhary, Editor of Sikar Times, Rajasthan

Mr. Karuna Sagar,DG Director- Modernisation, BPR&D,
Ministry of Home Affairs, New Delhi

Mr.Gaurav Gupta Founder & President, GTTCI Charter
President Lions Club Delhi

Mr. Ajit Maurya, Social Worker, Businessman

Mr. Atul Kapoor, President, Pratiyogita Darpan

Mr. Anil Kumar Yadav, ADJ, Banaras

Mr. Pratap Chaprana Social Worker Businessman

Mr. Amit Tyagi, Senior Journalist & Executive Editor
Dialogue India Group

Mr. Pankaj Babu Kushwaha, Sr. Administrative Officer, Career Plus

Mr. Hitesh Kumar, Social Worker Businessman

GLIMPSE OF CAREER PLUS SILVER JUBLIEE CELEBRATION

GLIMPSE OF CAREER PLUS SILVER JUBLIEE CELEBRATION

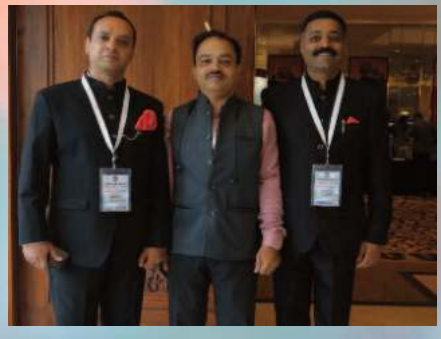

GLIMPSE OF CAREER PLUS SILVER JUBLIEE CELEBRATION

भ्रष्टाचार हथियार
परिवारवाद पर वार

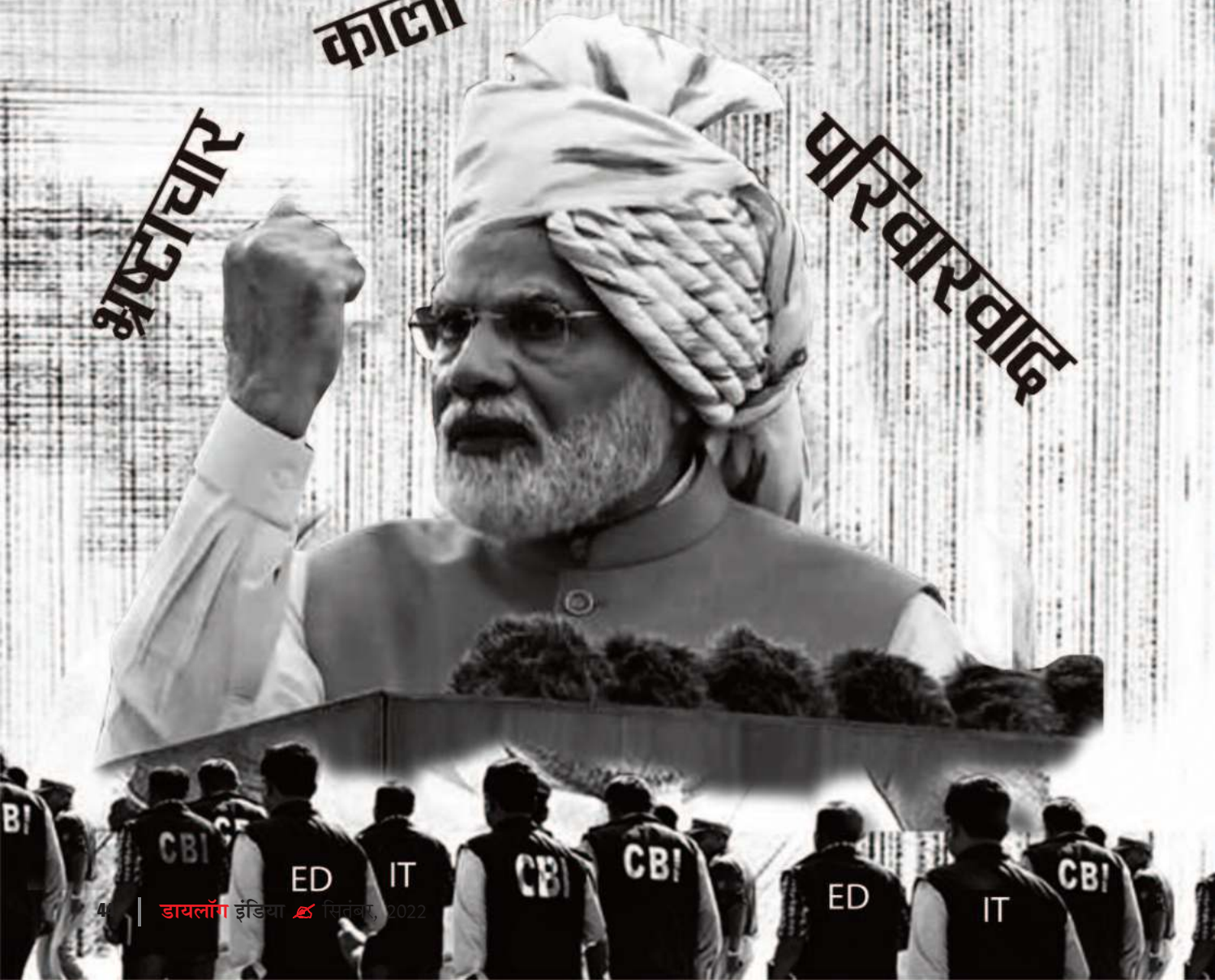

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या बताया गया। इसके साथ ही स्टार्ट अप और इनोवेशन के दौर में उन्होने जय जवान और जय विज्ञान के नारे में एक नया शब्द जय अनुसंधान को जोड़ा। विकसित भारत के अगले 25 साल का खाका पेश करते हुये उन्होने देशवासियों से पांच प्रण लेने को कहा। भ्रष्टाचार और परिवारवाद वर्तमान में भारत के लिए दीमक का कार्य कर रहा है। दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। जिस जिस प्रदेश में क्षेत्रीय दल या परिवारवाद की राजनीति देखी गयी, वहां वहां भ्रष्टाचार समानान्तर रूप से सामने आया। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवारवादी राजनीति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, गैर परिवारवादी राजनीति में भी भ्रष्टाचार दिखता है किन्तु परिवारवादी राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि परिवार तंत्र का लाभ उठाकर आस पास के चापलूस भी लाभ उठाते रहते हैं। वह परिवार को घेरे रहते हैं। आस पास के ये लोग उस परिवार के प्रति इतना सेवाभाव प्रदर्शित करते हैं कि परिवार से जुड़े लोग उस दीमक को पहचान ही नहीं पाते हैं। इसके साथ ही देश के सामने एक बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना और नए रोजगारों का सृजन करना है। इसके लिए नए अनुसंधान की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति की बातों का कितना जमीनी अनुपालन हो पाता है इस पर भी रोजगार सृजन के प्रश्न का उत्तर निर्भर करेगा। विकास की गति को बढ़ाने के लिए उन 55 प्रतिशत लोगों पर ध्यान देना होगा जो अर्थव्यवस्था में हालांकि सिर्फ 14 प्रतिशत का योगदान देते हैं किन्तु कृषि क्षेत्र से जुड़े ये लोग अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश के सामने सामाजिक चुनौतियां भी हैं क्योंकि आरक्षण के बाद भी जातिगत जड़ें उखड़ने के बजाय और गहरी होती चली जा रही हैं। सामाजिक समरसता के स्थान पर विभिन्न मतावलंबियों और अल्पसंख्यको के प्रति कड़वाहट बढ़ रही है। इस पर समय रहते निर्णायक कार्य करने की आवश्यकता है। इन सब विषयों से ऊपर सबसे महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन का है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से न भारत अछूता रह पायेगा न सत्ता एवं विपक्ष। यह ऐसा विषय है जिस पर सभी को मिलकर जिजीविषा दिखानी होगी। प्राकृतिक संसाधनों की लूट, खनन माफिया, पेड़ों का कटान और विकास के नाम पर हाइवे के किनारे बड़े पेड़ों के कटान पर विचार करना होगा। झारखंड में खनन सचिव के करीबी के पास से 19 करोड़ नकद मिला है। जनता को एक बात समझनी होगी कि नेता और सरकार सिर्फ सपने दिखा सकती हैं। सपनों में रंग जनता को ही भरने होंगे। बहरहाल, जिस तरह से केन्द्रीय जांच एजेंसियों के प्रयोग के द्वारा कई राज्यों में धड़ाधड़ छापे लग रहे हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की कमर तोड़ी जा रही है उसके बाद भ्रष्टाचारियों में खौफ दिख रहा है। अब यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई है या सिर्फ 2024 के लिए चुनावी तैयारी, इस प्रश्न का उत्तर भविष्य की गर्त में है।

● **अमित त्यागी**

लालकिले की प्राचीर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुये और स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने अगले 25 वर्षों का खाका रखा। पांच सूत्र रखे। इस दौरान उन्होने युवाओं को प्रेरित किया। मोदी का कहना था कि मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। एक भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। इन दोनों विषयों को उठाकर मोदी ने न सिर्फ हाल फिलहाल में में चर्चा में आए राजनीतिक हल्कों के चर्चित भ्रष्टाचार पर लोगों में अपेक्षा का भाव पैदा किया बल्कि उनकी बातों के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाने लगे। एक तरफ विपक्षी दल 2024 में मोदी के विकल्प के रूप में गठबंधन पर कवायद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के जरिये जनता से जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के चर्चित प्रकरण में सोनिया गांधी और राहूल गांधी से ईडी द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। यह जिस तरह के लेन देन का मामला है उसमे दोनों का फंसना लगभग तय दिख रहा है। इन सबके बीच कभी सोनिया राहुल के भारत छोडकर विदेश में बसने की चर्चा चलती है तो कभी दोनों से चल रही पूछताछ को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर बताया जाने लगता है। अब जिस तरह से कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है उसके बाद सोनिया राहुल के बाहर जाकर बसने की बात को भी नकारा नहीं जा सकता है।

पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस में गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रहता आया है और यदि बाहर के व्यक्ति को इस जिम्मेदारी के लिए खोजा जा रहा हो तो यह कांग्रेस के पास उपस्थित आखिरी विकल्प है। परिवारवाद की

नीतीश 'सुशासन बाबू' से 'पलटू राम' कैसे हो गये?

बिहार में 'सुशासन बाबू' कहलाने वाले नीतीश कुमार अब पक्के तौर पर 'पलटू राम' हो गये हैं। दो दिन की गहमागहमी के बाद उन्होंने पहले इस्तिफा देकर आखिर राज्यपाल से मुलाकात कर 160 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसे अस्तित्व की लड़ाई कहें या राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लेकिन यह सच है कि सत्ता की खातिर पाला बदलने में कोई दल पीछे नहीं रहता। लोकतांत्रिक मूल्य, प्रामाणिकता, राजनीतिक सिद्धान्त तो शायद राजनीतिक दलों के शब्दकोश से गायब ही हो गए लगते हैं। भले ही गठबंधन राजनीति में टूट-फूट नई बात न हो, और न ही जनादेश की अनदेखी किया जाना, लेकिन यह एक तथ्य है कि बार-बार पाला बदलने वाले दल अपनी साख गंवाते हैं। भारतीय राजनीति से नैतिकता इतनी जल्दी भाग रही है कि उसे थामकर रोक पाना किसी के लिए सम्भव नहीं है।

आज राष्ट्र पंजों के बल खड़ा राजनीतिक नैतिकता की प्रतीक्षा कर रहा है। कब होगा वह सूर्योदय जिस दिन राजनीतिक जीवन में मूल्यों के प्रति विश्वास जगेगा। मूल्यों की राजनीति कहकर कीमत की राजनीति चलाने वाले राजनेता नकार दिये जायेंगे। राजनीति की ये परिभाषाएं बदल जायेगी कि राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं या राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही स्थायी दुश्मन। राजनीति हो, सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सार्वजनिक क्षेत्र में जब मनुष्य उतरता है तो उसके स्वीकृत दायित्व, स्वीकृत सिद्धांत व कार्यक्रम होते हैं, वरना वह सार्वजनिक क्षेत्र में उतरे ही क्यों? जिन्हें कि उसे क्रियान्वित करना होता है या यूं कहिए कि अपने कर्तृत्व के माध्यम से राजनीतिक प्रामाणिकता को जीकर बताना होता है परन्तु आज इसका नितांत अभाव है। राजनीतिक मूल्यों के रेगिस्तान में कहीं-कहीं नखलिस्तान की तरह कुछ ही प्रामाणिक व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे लोगों का अभाव ही बार-बार तख्ता पलट करते हैं या गठबंधन को नकारते हैं।

यह सही है कि नीतीश कुमार के पास अब पहले से अधिक विधायकों का समर्थन होगा, लेकिन अब उनकी राजनीतिक ताकत पहले की तुलना में कम होगी, वे अब अपने हिसाब से शासन का संचालन करने में ज्यादा सक्षम नहीं होंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि यदि नीतीश कुमार 77 सदस्यों वाली भाजपा के दबाव का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो फिर 79 सदस्यों वाली राजद के दबाव से कैसे निपट पाएंगे? अब तो उन्हें राजद के साथ महागठबंधन के

अन्य दलों को भी संतुष्ट करना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार संख्या बल ही नहीं बल्कि नैतिक बल के मामले में जदयू ज्यादा कमजोर है। बिहार में सत्ता की चाभी भले ही जदयू के पास हो, लेकिन अब वह तीसरे नंबर की पार्टी रह गई है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था तो इससे आजिज आकर कि राजद नेता शासन संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे और वह उसे रोक नहीं पा रहे थे। क्या इस बार वह ऐसा करने में सक्षम होंगे और वह भी ऐसे समय, जब सुशासन बाबू की उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लग चुके हैं और बिहार विकास के पैमाने पर पिछड़ा है। अब तो उसके और पिछड़ने का अंदेशा है। नीतीश कुमार को उन सवालों के भी जवाब देने होंगे, जिनके तहत वह राजद नेताओं के भ्रष्टाचार को रेखांकित किया करते थे।

जहां तक भाजपा की बात है, उसके सामने बिहार में अपने बलबूते अपनी जड़ें जमाने की चुनौती आ खड़ी हुई है और इस चुनौती को झेलने में वह सक्षम है। ताजा घटनाक्रम भाजपा के लिये शुभ एवं श्रेयस्कर साबित होगा। क्योंकि भाजपा जिन मूल्यों एवं सिद्धान्तों की बात करती है, वह उन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर अपने धरातल को मजबूत कर सकेगी। विशेष रूप से भाजपा को ध्यान रखना होगा कि बिहार की जनता के बीच उसे बिना सत्ता के एक नया विश्वास अर्जित करना है। आम लोग तो यही चाहेंगे कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों ही ज्यादा ईमानदारी से काम करें। कोई शक नहीं, आने वाले कम से कम तीन-साढ़े तीन साल बिहार में जमकर राजनीति होगी, बिहार में बहुत काम शेष हैं और तेजस्वी यादव बखूबी कमियां गिनाते रहे हैं, अब उन्हें मौका मिल रहा है, तो लोगों की शिकायतों को दूर करें। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता, यही भाजपा के लिये सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेगा।

बिहार की राजनीति तो आदर्श की राजनीति मानी जाती रही है, जिसने अनेक नैतिक राजनीति के शीर्षक व्यक्तित्व दिये हैं। वहीं से भ्रष्टाचार एवं अराजकता की राजनीति को चुनौती देने के लिये जयप्रकाश नारायण से समग्र क्रांति का शंखनाद किया। जहां से हम प्रामाणिकता एवं नैतिकता का अर्थ सीखते रहे हैं, जहां से राष्ट्र और समाज का संचालन होता रहा है, अब उस प्रांत के शीर्ष नेतृत्व को तो उदाहरणीय किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अब वहां पद के लिए होड़ लगी रहती है, व प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पद को येन-केन-प्रकारेण, लॉबी बनाकर प्राप्त करने के लिये गठबंधन टूटते है, तख्ता पलट होता है, तय मानकों को बदला जाता है। अरे पद तो क्रॉस है- जहां ईसा मसीह को टंगना पड़ता है। पद तो जहर का प्याला है, जिसे सुकरात को पीना पड़ता है। पद तो गोली है जिसे गांधी को सीने पर खानी होती है। पद तो फांसी का फन्दा है जिसे भगतसिंह को चूमना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में जो भी शीर्ष पर होते हैं वे आदर्शों को परिभाषित करते हैं तथा उस राह पर चलने के लिए उपदेश देते हैं। पर ऐसे व्यक्ति जब स्वयं कथनी-करनी की भिन्नता से प्रामाणिकता एवं राजनीतिक मूल्यों के हाशिये से बाहर निकल आते हैं तब रोया जाए या हंसा जाए। लोग उन्हें नकार देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन चरित्र के ग्राफ को समझने

की शक्ति/दक्षता आज आम जनता में है। जो ऊपर नहीं बैठ सका वह आज अपेक्षाकृत ज्यादा प्रामाणिक एवं ताकतवर है कि वह सही को सही और गलत को गलत देखने की दृष्टि रखता है। समझ रखता है। यह गौर करना भी जरूरी है कि आजादी के तुरंत बाद बिहार कहां खड़ा था और आज आजादी के अमृत महोत्सव में कहां खड़ा है?

राजनीति में जब नीति गायब होने लगती है तो बेमेल गठबंधनों के बनते भी देर नहीं लगती। और, इस बुराई के लिए कमोबेश सभी राजनीतिक दल समान रूप से जिम्मेदार हैं। देखा जाए तो सबकी नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव है जहां 40 सीटों वाले बिहार की भूमिका भी अहम रहने वाली है। बिहार में नया सियासी गठबंधन कितना बदलाव लाएगा, यह भविष्य ही बताएगा। ऐसे में लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। उनका झुकाव भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अधिक देखने को मिल रहा था। तेजस्वी यादव के प्रति उनका नरम रुख प्रकट होने लगा था। मगर जब जनता दल (एकी) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया तो परदे के पीछे चल रहा खेल सामने उभर कर आ गया।

दरअसल यह अवसरवादिता और मौकापरस्ती की हद है जिसका राजनीति में प्रतिकार होना चाहिए और ऐसे नेताओं को जनता द्वारा नकारा जाना चाहिए। वास्तव में बिहार का ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस राज्य में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ने इस प्रदेश की जनता के मौलिक अधिकारों से उनको वंचित किये हुए है और इस प्रांत के लोगों को भारत का सबसे गरीब आदमी बनाया हुआ है। जबकि बिहारियों का भारत के सर्वांगीण विकास में योगदान कम नहीं हैं, सबसे अधिक मेहनती एवं बुद्धिजीवी लोग यही से आते हैं। इसकी धरती में अपार सम्पत्ति छिपी है और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के स्वर्णिम अध्याय लिखे हुए हैं। इसके बावजूद इस राज्य में पर्यटन उद्योग का विकास नहीं हो पाया। जिस राज्य के पास नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष हों उसके ज्ञान की क्षमता का अन्दाजा तो सदियां बीत जाने के बाद 21वीं सदी में भी लगाया जा सकता है। लेकिन दूषित राजनीति की कालिमाएं यहां के धवलित इतिहास को धुंधलाती रही है। यहां की राजनीति की सत्तालोलुपता एवं भ्रष्टता लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करती रही है। जबकि प्रामाणिकता एवं सिद्धान्तवादिता राजनीतिक क्षेत्र में सिर का तिलक है और अप्रामाणिकता मृत्यु का पर्याय होती है। आवश्यकता है, राजनीति के क्षेत्र में जब हम जन मुखातिब हों तो प्रामाणिकता का बिल्ला हमारे सीने पर हो। उसे घर पर रखकर न आएं। राजनीति के क्षेत्र में हमारा कुर्ता कबीर की चादर हो। नीतीश बाबू जिस महागठबन्धन की सरकार अब चलायेंगे वह बिहार के विकास की गाड़ी को उल्टी दिशा में ले जायेगी।

-ललित गर्ग

राजनीति पर मोदी की इस चोट के मायने सिर्फ सत्ता के केंद्र दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। राज्यों में भी इस तरह के परिवारवाद और घोटालों के उद्धारण भरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के नाम पर बसपा में मायावती का परिवार काबिज है। मायावती स्वयं सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। समाजवाद के नाम पर मुलायम सिंह यादव का परिवार एवं अखिलेश यादव दल के मालिक बने बैठे हैं। मुलायम सिंह यादव स्वयं आय से अधिक संपत्ति का केस झेल रहे हैं। यानि कि उत्तर प्रदेश में तीनों विपक्षी दल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा के शीर्ष नेतृत्व पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा इतना ज्यादा कसा हुआ है कि ये लोग रीढ़हीन विपक्ष बन कर रह गए हैं। देश में इस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक माहौल बना हुआ है। एक ओर मोदी भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष मोदी हटाओ के अभियान पर लगा हुआ है।

मोदी और विपक्ष का अंतर :

जिस समय मोदी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे थे उसी समय ममता बनर्जी अपने भ्रष्टाचारी नेता का बचाव कर रही थीं। मोदी का कहना था कि लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति तो नफरत दिखाई दे रही है किन्तु भ्रष्टाचारियों के प्रति अभी ऐसा भाव नहीं दिख रहा है। जब तक समाज का भाव भ्रष्टाचारियों के प्रति नफरत का नहीं होगा तब तक यह रोग दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काटकर आए लोगों का महिमामंडन हो रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्तमान में दिखने वाला यह माहौल नया माहौल नहीं है। 1977 में जेपी आंदोलन और 1989 में बोफोर्स कांड के दौरान भी भ्रष्टाचार विरोध का माहौल बना था। पर देश की एक विडम्बना यह रही है कि किसी ने सत्ता में आने के बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने एक दल का गठन किया और उसने नए भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल का वादा जनता से किया। कुछ समय बाद ही उनके दल ने भ्रष्टाचार का मॉडल एक किनारे रख दिया और मोदी के अन्य विपक्षियों की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण का मॉडल अपना लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे। जांच हुयी और अभी भी चल रही है। जांच में कभी मंत्री की याददाश्त चली जाती है तो कभी कोई और बहाना बना दिया जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित लगभग पूरे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। ईडी और सीबीआई इस समय किसी सुपर हीरो की तरह यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई दे रही है।

मोदी का कहना है कि 'एक तरफ भारत जैसे लोकतन्त्र में गरीबी से जूझ रहे बेघर लोग हैं तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनको चोरी का माल रखने की भी जगह नहीं है। हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ना है। राजनीति में परिवारवाद ने सामर्थ्यवान के साथ अन्याय किया है। हिंदुस्तान की राजनीति और सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए हमें इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिलाकर योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाना होगा। देश के सामने करोड़ों संकट हैं तो करोड़ों समाधान भी हैं। 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। मुझे इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाना है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिये।'

यदि देखा जाये तो पूरी देश में इस समय भ्रष्टाचार के विरोध में एक माहौल दिख रहा है। गंभीरता से कार्यवाही होती दिख रही है। गंभीरता इस रूप में दिखती है कि भ्रष्ट और रसूखदार लोग जेल जाने से डरने लगे हैं। इसी कारण वह इन कार्यवाहियों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत जनता का सीधा जुड़ाव अब मोदी से है। विपक्ष या भ्रष्टाचारी जब जब जब किसी विषय पर बात न करके मोदी विरोध का नारा देते हैं तब तब जनता में मोदी का पक्ष मजबूत हो जाता है। इस समय अगर आप विपक्षी नेताओं के नाम लीजिये तो पाएंगे कि वह या तो जेल में हैं या कुछ जेल जाने वाले

रंग और दल बदलते नटराज नीतीश की नयी कलाबाजी

नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते थे। 11 अगस्त 2022 से दुशासन बन गये। दुर्योधन के अनुज के नाम वाले। कारण ? सत्ता का उन्होंने एक बार फिर चीर हरण कर डाला। दो दशकों में कितनी बार पल्ला झाड़ा ? पलटूराम बने। होडल (हरियाणा) के विधायक श्री गया लाल (1967) की भांति जिन्होंने एक ही दिन में दो बार पार्टी बदली। आयाराम-गयाराम कहलाये। वे भी नीतीश से उन्नीस ही पड़े। हालांकि विगत 7 मई 2022 को ही आभास हो गया था कि नीतीश पार्टी उलटेंगे। उसी दौर में मुख्यमंत्री सरकारी आवास (1 एमएस अणे मार्ग, पटना) को तजकर वे अपने पुराने मकान (7 सर्कुलर रोड) चले गये थे। साथ में अपनी 17 गायों को भी ले गये थे। उनकी रूष्टता का कारण था कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग ने चुनाव में उनकी पार्टी की रोशनी गुल कर दी थी। नीतीश की पार्टी जनता दल (यू) केवल 43 विधायक ही जीती। भाजपा 74 जीत ले गयी। तभी नीतीश समझ गये थे कि अब डेरा बदलना होगा। भगवा को तजना होगा। यूं भी अप्रैल माह में जब लालू यादव की इफ्तार पार्टी में बकरा और चूजा चबाया जा रहा था तो उसमें बड़ी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री भाग लिया। कुर्मी-यादवों का ऐसा समागम मगध इतिहास में दिलचस्प रहा। नीतीश कुमार कुर्मी सिरमौर हैं। यूपी में बाबू बेनी प्रसाद वर्मा कभी होते थे।

फिलहाल नीतीश द्वारा एक बार पासा पलटने के पीछे अलग-अलग वजह बतायी जाती हैं। वे उपराष्ट्रपति नहीं चयनित हुये तो मन उचट गया। अगला कारण है कि वे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पिछले आम चुनाव में वे सोनिया से वार्ता हेतु भी मिलने भी गये थे। सोनिया का धूर्ततापूर्ण उत्तर था- ``राहुलजी सब देख रहे हैं।`` एक सीट पर दो कैसे बैठते ? नीतीश तो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। भलीभांति जानते हैं कि आरएसी (प्रतीक्षारत सीट) केवल एक ही को मिलती है। राहुल के मुकाबले नीतीश कहां ठहरते ? फिर वे ममता को भी पसंद नहीं करते थे। एक बार दोनों संसद भवन में रेल मंत्री के कमरे के लिये आपस में तेजी से भिड़ चुके है। भला हो जार्ज फर्नांडिस का कि साथी नीतीश को मना लिया। जिद्दन बंगालन को कमरा मिल गया। भारत के दो काबीना मंत्री एक अदना कक्ष के लिये लड़े !! वाह ! ऐसा ही एक और वाकया था। नीतीश कुमार अपने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपनी ही समता पार्टी मंत्री (बाकां के सांसद) दिग्विजय सिंह को दोबारा राज्य मंत्री स्वीकारने के लिये तैयार नहीं थे। पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दबाव डलवा कर पार्टी ने उन्हें बनवा दिया। इसी बीच शरद यादव से गठजोड़ कर नीतीश ने जॉर्ज

फर्नांडिस को पार्टी अध्यक्ष पद पर से हटवा दिया। तो कुल मिलाकर अवधारण यही बनी थी कि सत्पुरूष नीतीश धोखा, दगा, कपट और विश्वासघात में भी अपना दखल रखते हैं। उनके ज्ञासें में लालू यादव, जो स्वयं शातिर और पलट जाने में माहिर हैं, भी नीतीश के खेमे में भीतर बाहर आते जाते रहे। जेपी आन्दोलन के ये दोनों भाई समूचे बिहार को रेहन बना चुके हैं, बंधक भी।

कल की अदला बदली से अब नीतीश पर आमजन की बची खुची आस्था भी लुप्त हो जायेगी। सवाल है कि ऐसा मानसिक रूप से अस्थिर पुरूष उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा केन्द्रीय मंत्री बन जाये तो? खुदा खैर करे।अचरज होता है कि ये दोनों, (लालू यादव और नीतीश कुमार) भ्रष्ट कांग्रेसी मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हटाने के संघर्ष में जेल गये थे। मगर यही भ्रष्ट कांग्रेसी मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बाद में नीतीश कुमार की समता पार्टी के अगुवा बन गये। उन्हें चाभी दी किसने ? गत सप्ताह की घटनाओं का एक कारण यह भी है कि भाजपायी मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कह दिया था कि नीतीश कुमार केवल 2025 (तीन साल और) तक ही मुख्यममंत्री बने रहेंगे। अब नीतीश को खुद समझना चाहिये कि भाजपा में राजनीतिक रिटायरमेंट आयु सत्तर पर है। उसके बाद मार्गदर्शक मण्डल में नामित हो जाते हैं। नीतीश कहां जाते ? तो क्या तब तक नीतीश भाजपा के हमबिस्तर रहते, मुसलमानों के प्यारे बने रहते या लालूपुत्र तेजस्वी के तेज में झुलसते रहते ! यह नागवार गुजरता। फिर भी नेहरू-टाइप प्रवृत्ति से ग्रसित रहकर नीतीष तिरंगे में लिपट कर ही जाना चाहते है, तो क्यों सिंहासन छोड़े ? भले ही जनता ललकारती रहे।

एक किस्सा और। बिहार का आधुनिक इतिहास गवाह है कि बिहार का यह सियासी पुरोधा देश की मीडिया में छाया रहा। चूंकि नीतीश एनडीए के मुख्यमंत्री थे अतः यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने नीतीश कुमार को एक सुझाव दिया। इस्लामी नाम बदलने वाली अपनी रौ में योगी जी ने कहा कि पड़ोसी बिहार में नालन्दा से सटा बख्तियारपुर शहर है जो अभी भी पुराने नाम के बोझ तले दबा हुआ है। परिवर्तन की मांग उठ रही है। योगीजी की इस मांग में काफी दम है। नालन्दा विश्वविद्यालय मानव इतिहास में ज्ञान की अमूल्य धरोहर थी। कट्टर इस्लामी हमलावर ने उसे जला दिया। इतिहास साक्षी है कि बौद्ध शोध कार्य, धर्म, इतिहास आदि की पुस्तकें नालन्दा संग्रहालय में अकूत थीं। इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सब नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसी लुटेरे बख्तियार ने राख में बदल दिया था। इस्लामी क्रूरता और असहिष्णुता के ऐसे बटमारों के नाम पर रखा गया है जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र और कौटुम्बिक गांव। रेलवे स्टेशन अभी भी बख्तियारपुर जंक्शन कहलाता है। योगीजी ने याद दिलाया कि पूर्वी यूपी का मुगलसराय स्टेशन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहलाता है। यहीं पर भाजपा चिंतक की हत्या हुई थी। नीतीश कुमार दशकों से राज करते रहे पर मुस्लिम वोट के खातिर अपने क्षेत्र का नाम नहीं बदल सके। इसीलिये योगीजी ने राय दी। वोटों का दबाव ?

-के. विक्रम राव

भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त हो न्यायपालिका ?

लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का विषय उठाया। राजनीतिक क्षेत्र के बाद न्यायपालिका एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां परिवारवाद और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दिखाई देता है। हर तरफ से परेशान व्यक्ति जब न्यायपालिका की तरफ आशा भरी निगाह से देखता है तब उसे वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नजर आता है। चाहे कालेजियम के द्वारा कुछ परिवारों का न्यायिक व्यवस्था का विषय हो, या लंबित पड़े वादों का, इन विषयों का असर आम आदमी पर ही पड़ता है। 1950 मे गठित किये गये भारत के उच्चतम न्यायालय ने अब तक लगभग 40 हजार वादों मे फैसला दिया है। मामलों को निपटाने के औसत के संदर्भ मे यह 600 मामले प्रतिवर्ष बैठता है। अब अगर न्यायालय अपनी गति को लगभग दुगना करते हुये 1000 मामले प्रतिवर्ष निपटाने लगे तब भी वर्तमान मामलों को निपटाने मे अभी 60 वर्ष और लग जायेंगे। यदि उच्च न्यायालय की तरफ देखें तो अगर कोई न्यायाधीश 500 फैसले प्रतिवर्ष सुनाता है तो लगभग 640 न्यायाधीशों के हिसाब से मुकदमों के निस्तारण मे 15 वर्ष का समय अभी और लगेगा। निचली अदालतों में 15,000 न्यायाधीशों के द्वारा 2.7 करोड़ वादों के निस्तारण मे कम से कम दस वर्षों का समय लगेगा। भारत मे प्रति 10 लाख की आबादी पर 14 जज काम कर रहे हैं। ब्रिटेन मे इतनी ही आबादी पर 50 जज एवं अमेरिका मे 100 जज काम करते हैं। भारत मे एक जज औसतन 2600 वादों को निपटा देता है जबकि अमेरिका मे एक जज साल मे सिर्फ 81 मामले ही निपटाता है। इतनी बड़ी संख्या मे केसों का निपटान करने की स्थिति मे न्याय की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ये आंकड़े इतने भारी भरकम हैं कि इनको सुनने मात्र से इंसान हाफने लगता है।

कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसे अपनी सुपुर्दगी मे नहीं रख सकती है और जेल भेज देती है। अब आरोपी निर्दोष है या गुनहगार है इसका फैसला करने का अधिकार न्यायालय के पास है। न्यायालय मे मामला दशकों तक लंबित रहता है। अब अगर दस साल बाद आरोपी दोष मुक्त साबित हो भी गया तो उसका तो पूरा जीवन ही तब तक बर्बाद हो चुका होता है। संविधान ने पीड़ित और आरोपी दोनों को समान मूल अधिकार दिये हैं। न्याय मे देरी से दोनों के मूल अधिकारों का हनन होता है। आज भारत की जेलों मे बंद कैदियों मे से लगभग 75 प्रतिशत अंडर-ट्राइल कैदी हैं। गरीब पीड़ित हो या आरोपी, उसका इस व्यवस्था में बर्बाद होना तय है। अमीर तो जमानत भी प्राप्त कर लेते हैं और सजा पाने के बाद पेरोल भी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस बात के लिये निर्देशित किया है कि गरीबों के लिये जमानत की राशि इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि पीड़ित पक्ष उसे अदा ही न कर पाये। संज्ञेय अपराधों मे भी जमानत प्राप्त करना आरोपी का अधिकार है। किन्तु, ऐसा होता नहीं है। हालत तो यहां तक हैं कि कभी कभी उच्च न्यायालय मे जमानत की

अर्जी लंबित ही रह जाती है और तब तक मेन अपील भी आ जाती है। संविधान के अनु0-142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने एक फैसले मे एक बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी मामले मे यदि दो माह की समय सीमा मे फैसला नहीं आता है तो उसकी दुबारा सुनवाई की जाएगी। पर वास्तविकता मे स्वयं उच्चतम न्यायालय भी इसका पालन नहीं कर पा रहा है।

न्यायपालिका पर बोझ कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए दो बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। पहला, किस तरह लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण किया जाये? दूसरा, कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जाये जो यह सुनिश्चित करे, कि न्यायालय के सामने नये वाद कम से कम आए। कम महत्वपूर्ण विवादों को न्यायालय के बाहर ही निर्णीत करवा देना बेहतर विकल्प है। तीस साल पहले के विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए किन्तु वर्तमान मे इतनी आबादी पर सिर्फ 10 जज काम कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अनुसार देश को 70,000 नये जजों की आवश्यकता है। इसके लिए भारत मे इस समय 12 लाख से भी ज्यादा पंजीकृत अधिवक्ता हैं। 950 ला स्कूल से लगभग पांच लाख छात्र कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। यदि पंजीकृत अधिवक्ताओं मे से कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करवाया जाएगा तो न्यायालय पर बोझ काफी कम हो सकता है। न्यायालयों के कामकाजी घंटों मे बढ़ोतरी होनी चाहिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के अनुसार अगर अस्पताल, विमान सेवा और रेलवे 24 घंटे और सात दिन काम कर सकते हैं तो न्यायालय क्यों नहीं ? इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा डाली गयी ग्रीष्म-अवकाश की परिपाटी को खत्म किया जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के न्यायालय मे इस तरह के अवकाशों की कोई परिपाटी नहीं है। दूसरे बिन्दु पर चर्चा करें तो भारतीय न्यायालयों मे सबसे अधिक मामले जमीन और संपत्ति विवाद के है। इन दीवानी मुकदमो के लिये कोर्ट फीस पहले एक रुपये थी और अब बढ़कर सिर्फ पचास रुपये है।

जमीन की कीमत लाखों-करोड़ों मे होने के बावजूद मुकदमा इतने कम रुपये मे दाखिल हो जाता है। ऐसे मे अनावश्यक मुकदमों से निपटने के लिये संपत्ति के मूल्य के अनुपात मे ही कोर्ट फीस की जा सकती है। फर्जी मुकदमा करने वालों, दूसरे पक्ष को सिर्फ उलझाने के लिये न्यायालय का समय बर्बाद करने वालों पर सख्त कार्यवाही के द्वारा बोझ कम किया जा सकता है। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज जनता नहीं है बल्कि सरकार है। कुल लंबित मामलों मे से 70 प्रतिशत वाद सरकार से जुड़े हुये हैं। अफसरों के आदेशों और बला को टालने की प्रवृत्ति के चलते गेंद न्यायालय के पाले मे डालने की परिपाटी चल रही है। चूंकि, 'मामला न्यायालय मे विचाराधीन है' यह कहकर सरकारी कर्मचारी आसानी से अपना कार्यकाल बिना कुछ करे भी पूरा कर ले जाते हैं। इसके साथ ही सुधार के नाम पर की जाने वाली जनहित याचिकाओं पर भी कुछ अंकुश आवश्यक है। वर्तमान में सम्पूर्ण न्यायिक तंत्र की ओवर हालिंग की सख्त आवश्यकता है।

-अमित त्यागी

क्या दल बदलुओं की खाल उधेड़नी पड़ेगी ?

हम उनको इसलिए चुनते हैं कि हमारे नौकर बनकर कार्य करें, लेकिन वे समझ लेते हैं खुद को मालिक,यही से गड़बड़ शुरू होती है। क्या आज का वोटर यह देखता है कि कौन नेता कितना ईमानदार या बेईमान है या वह अपनी पार्टी के प्रति कितना वफादार है? क्या जनता में इतना दम नहीं कि वह दलबदलुओं को चुनावों में सबक सिखा सके? जिस सरकार से जनता परेशान थी उसी सरकार के दलबदलू मौके की नजाकत को देखते हुए दलबदल फिर से सरकार में आ जाते हैं। फिर जनता ने किसको, कैसा सबक सिखाया? जनता को चाहिए दलबदलुओं को वोट के दल-बल से राजनीति के बाहर का रास्ता दिखा दे। तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुधर सकती है।

जो विधायक या सांसद किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी बदलते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो यह कहते हैं कि उसने इसलिए पार्टी बदली है ताकि जनता की भलाई कर सके। उससे झूठा, ठग, बेलिहाज कोई नहीं हो सकता। हर विधायक, सांसद को उसके हल्के में खर्च करने के लिए फंड मिलता है, हर एक को तनख्वाह मिलती है। फिर उन्हें बदलूराम बनने की जरूरत क्या है? जवाब साफ सा है-व्यक्तिगत स्वार्थ। दरअसल विधायक, संसद को हम ही बिगाड़ रहे हैं। क्यों पहनाते हो उनको फूल माला? क्यों बुलाते हो घरेलू समारोह में?

हर कीमत पर जीत और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दूसरे दल के पहलवानों को भी अपना बनाने के लिए हर चाल चली जा रही है। पहलवान तो पहलवान ताली बजाने और दंगल में जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की भी मौज बहार आ रखी है। जिसको अपनी गली के लोग नहीं पहचानते थे वो नेताजी बन गए हैं। खुद पार्टी को भी नहीं पता होता कि ये हमारी पार्टी में था भी कि नहीं..? जब दूसरी पार्टी बोलती है कि हमने इन्हें शामिल कर दूसरे दल को बड़ा झटका दिया है तब उसे पता चलता है कि अबे ये अपनी पार्टी में था....? हर छुटभैया नेता आजकल दलबदल के लिए तैयार रहता है। वह मौके की तलाश में रहता है। मौका देख के मारो चौका। कोई बोले तो सही कि आओ, हमरे दल की शोभा बढ़ाओ। छुटभैया सोचता है, दलबदल करो तो अखबार वाले बढ़ा-चढ़ा कर

खबरें छाप देते हैं। कुछ दलबदलुओं को हर पार्टी में बहुत जल्दी दम घुटने लगता है। सुबह दल बदलते हैं, तो दोपहर को दम घुटने लगता है और वे पार्टी छोड़ देते हैं और नई पार्टी में जा घुसते हैं। सांप भी शरमा जाता है केंचुल बदलने में। चुनाव के समय दलबदल एक्सप्रेस सुपरफास्ट हो जाती है। दलबदलू जल्द-से-जल्द सफलता के स्टेशन तक पहुंचना चाहता है। किसी को टिकट मिल जाता है, तो किसी को कोई पद। जैसी जिसकी औकात।

जनसेवक की सार्थकता जनता की सेवा में है। जनसेवा मतलब टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, विजयी होना और सरकार में कोई सेवादार पद प्राप्त करना। पद न मिला तो सेवा कार्य में अड़चन होती है। इसीलिये लोग संभावित सत्ता पाने वाले दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी से जुड़ना चाहते हैं। चुनाव के समय चलने वाली हवा में वे सरकार बनाने वाली पार्टी को सूंघते हैं। आदमी कुत्ते में बदल जाता है। आत्मा की आवाज पर जमीर बेंच देता है। दलबदल लेता है। अकेले या समर्थकों सहित नये दल में शामिल हो जाता हैं। क्या लोग दलबदलुओं को खराब निगाहों से नहीं देखते। सत्ता के लिये दलबदल बेईमानी नहीं है। लालची नहीं है। लोलुप नहीं है। क्या समय के साथ लोगों की सोच बदली है। दलबदल अब मौका परस्ती नहीं रहा। वह उचित अवसर की पहचान है। अभी-अभी नितीशकुमार दल बदलुओं की तरह आंख फेरकर लालु जी से जा मिले ओर चेलेंज कर रहे हैं मोदी जी को 2024 में नही आने देंगे। क्या लगता है मित्रों? क्या सुशासन बाबु मोदीजी को रोक पायेंगे क्या? दल-बदलुओं का इतिहास भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत पुराना है। अपने राजनीतिक और निजी हित के लिए नेताओं ने इस कदर राजनीतिक पार्टियां बदली हैं कि इसके अनूठे रिकॉर्ड बन गए हैं।

वैसे 10वीं अनुसूची पर बहस बार-बार होती रही है। इसके चैप्टर 2 का पार्ट 1 (ए) कहता है कि सदन में किसी भी दल का सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से वह पार्टी से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। कांग्रेस के कानूनी सलाहकारों एवं सत्तापक्ष का मानना है कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होना (पायलट ने पार्टी व्हिप को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों का बहिष्कार किया) स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने जैसा है, लेकिन कई एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में देश भर में इस तरह के कई हाई-प्रोफाइल केस में दलबदल विरोधी कानून पर खूब बहस हई है। यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत, वोट नहीं देता है या विधायिका में वोट नहीं करता है। और यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली

है, या इस तरह के मतदान या परहेज से 15 दिनों के भीतर पार्टी द्वारा निंदा की जाती है, तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्यता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी को बदल सकते हैं। कानून एक पार्टी के साथ या किसी अन्य पार्टी में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि कम से कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे परिदृश्य में, न तो वे सदस्य जो विलय का निर्णय लेते हैं, और न ही मूल पार्टी के साथ रहने वालों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।

वैसे देखा जाए तो पार्टी निष्ठा सरकार को स्थिरता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार पार्टी के साथ ही नागरिकों के लिए भी उसके प्रति वफादार रहें। पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है। विरोधी दलबदल के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने की उम्मीद है। एक सदस्य के खिलाफ दंडात्मक उपायों के लिए प्रदान करता है जो एक पार्टी से दूसरे में दोष करता है। ऐसे में एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा असमान स्थिति या मनमुटाव की एक सार्वजनिक छवि को राजनीतिक परंपरा में वांछनीय स्थिति के रूप में नहीं देखा जाता है। हालांकि जब सरकार के गठन में अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं तो वहां दलों के बीच मनमुटाव को उचित ठहराया जा सकता है। ऐसे समय में जब भारत की रैंक 'नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक' में बुरी तरह गिर गई है, आज हमारी संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन सबको को सुधारने और मजबूत करने के लिये कदम उठाए। समयानुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दलबदल कानून में संतुलन बनाए रखने के लिये कानून में आवश्यक बदलाव किये जाने की पुरजोर आवश्यकता है। और अगर दल बदलुओं में दम है तो निर्दलीय जीतकर अपनी हनक दिखाएं ये मौकापरस्त नेता। दलबदलुओं को भी यही गलतफहमी है कि उनके अनुयायियों की भीड़ दिल से उनके साथ है, किसी दल के साथ नही।

हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट, जल्द सामने आयेगा फैसला

चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता मामले में राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि खनन-वन मंत्री रहते उन्होंने अपने नाम पत्थर खनन लीज आवंटित किया था। झारखंड में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे भ्रष्ट आचरण बताया।

हेमंत सोरेन पर लगे हैं ये आरोप

भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9a का हवाला देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग निर्वाचन आयोग से की थी। भाजपा ने कहा कि खनन-वन मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खान का आवंटन किया। यह गलत है।

हेमंत सोरेन पर मनी लाउंड्रिंग के भी लगे हैं आरोप

सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने दो जनहित याचिकाएं दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से खनन घोटाला की जांच कराने की मांग की। आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया और स्टोन क्यूएरी माइंस का आवंटन अपने नाम कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर मनी लाउंड्रिंग के भी आरोप हैं।

नहीं मिली रिपोर्ट - हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री कार्यालय ने हेमंत सोरेन की ओर से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में न तो निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें कोई चिट्ठी मिली है, न ही राजभवन की ओर से उन्हें कुछ बताया गया है।

हैं। इस पर एक प्रश्न यकायक उठता है कि क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी नेता विपक्ष में ही हैं। सत्ता दल में कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है? प्रश्न जायज लगता है किन्तु जो लोग जेल जा रहे हैं या जाने वाले हैं क्या वह लोग भ्रष्ट नहीं हैं ? भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देता है।

मोदी योगी ने तोड़ड़ा परिवारवाद का गढ़

2004-14 के कार्यकाल में भारत में भ्रष्टाचार चरम पर था और लोगों को इससे मुक्ति मिलती भी नहीं दिख रही थी। इस बीच अन्ना का आंदोलन एक झौंके की तरह आया जिसमे लोगों को एक आस दिखाई दी। यह वह दौर था जब बीमार को स्वयं भी बीमारी ठीक होने की संभावना नहीं दिखती थी। लोगों ने भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा ही मान लिया था। तब नरेंद्र मोदी का न खाऊंगा, न खाने दूंगा, का नारा बहुत पसंद किया गया। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले मोदी पर जनता ने भरोसा किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश भी 2017 के पहले परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बड़ा गढ़ माना जाता था। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का चयन भाजपा द्वारा हुआ तब यह चौकाने वाला फैसला था। हालांकि, जनमत योगी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। योगी ने उत्तर प्रदेश में पांच साल में ईमानदारी से सरकार चला कर दिखा दिया कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हो तो बड़े भ्रष्टाचार को

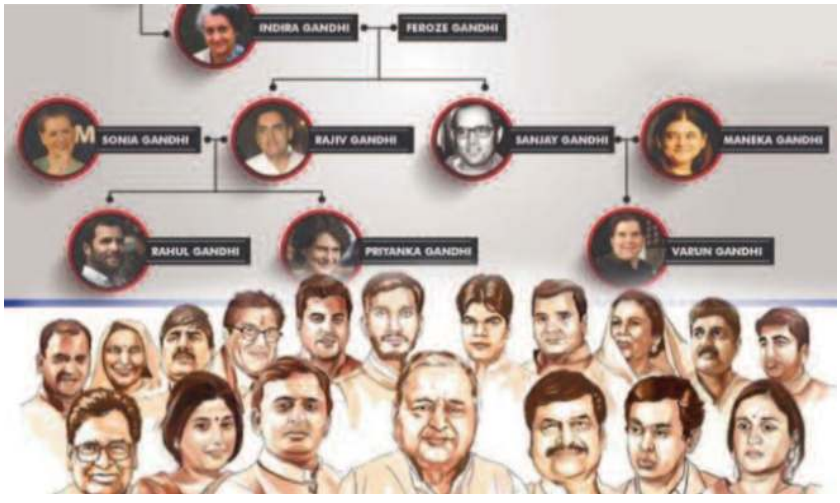

रोका जा सकता है ? मोदी की ईमानदारी उनके ही दल के लोगों को रास नहीं आयी। कई नेताओं की रातों की नींद ही उड़ गयी। जिस तरह से अपराधियों पर योगी ने ताबड़तोड़ हमले किए उसके बाद संगठित अपराध गिरोह कि तो जैसे कमर ही टूट गयी। अपराधी या तो जेल में या ऊपर वाला नारा उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगा। यह बात समझना कोई राकेट साइन्स नहीं है कि अपराधियों के द्वारा ही भ्रष्टाचार का खेल चला करता है।

राजनीतिक लोग अपराधियों और माफिया के गठजोड़ से ही धन उगाही करवाया करते हैं। ये माफिया जिस दल की सरकार बनती है उस दल से गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश में अपनी समानान्तर व्यवस्था चलाते थे। जब मुख्यमंत्री स्वयं ईमानदार हो तब माफिया का गठजोड़ सरकार से नहीं बन पाया। माफिया ने मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से गठजोड़ का प्रयास किया। इसी कारण योगी का अंतर्विरोध उनके ही दल में देखा गया। कोरोना काल की बड़ी त्रासदी के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने अकेले दम पर सरकार की वापसी करवा कर लाये हैं। जिस तरह से जनता ने एक बार फिर उन्हे निर्वाचित किया है। उसके बाद मोदी का नारा 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' पूरी तरह चरितार्थ हो गया है। अब यह एक नियम की तरह उत्तर प्रदेश में चल रहा है। परिवारवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में हाशिये पर है। सपा, बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर राजनीतिक चर्चा के समय जनता से जुड़ा महंगाई का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। सामान्य वस्तुओं के दाम पिछले कुछ समय में ही दुगुने हो गए हैं। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों का प्रभाव निचले तबके पर पड़ता है। यह वह वर्ग है जिसे न परिवारवाद की राजनीति से कोई सरोकार है न ही उच्च स्तर के भ्रष्टाचार से।

सामर्थ्यवान का हक मारता है भ्रष्टाचार :

भारतीय संविधान सभी नागरिको को समानता का अधिकार देता है किन्तु भ्रष्टाचार हमारा यह अधिकार छीन लेता है। भ्रष्टाचारी इतना पैसा कमा लेता है कि वह सब कुछ खरीदने की स्थिति में आ जाता है। अब चाहे भौतिक सुविधायें हों या व्यवस्था, भ्रष्टाचारी धन के माध्यम से सब खरीद रहा है और ईमानदारी को मुंह चिढ़ा रहा है। ईमानदार अपना पेट नही भर पा रहा है जबकि भ्रष्टाचारी बड़े सितारा होटलों में दावतों में लिप्त है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा तब दर्द देता है जब जरूरत की चीजें इतनी महँगी हो जाती हैं कि आम आदमी खरीद ही नही पाता है। एक तरफ माननीयों के घोटाले एवं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए खाने के लाले, बस यहीं से एक स्वस्थ मस्तिष्क भी अपराधिक प्रवृति की ओर बढ़ने लगता

भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं बेईमान है

हम बेवकूफ इसलिए बनाए जा रहे है, क्योंकि हम बेवकूफ है। हमारे हक इसलिए छीने जाते है ,क्योंकि हम दूसरो को छीनने की कोशिश करते है। हमारे साथ भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं बेईमान है। हमे अपने अंदर सुधार की जरूरत है, लोग खुद सुधर जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था- 'खुद में वो बदलाव लाइए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।'

देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने उम्मीदों और संकल्पों के साथ-साथ अपनी चिंताओं को भी साझा किया। पीएम ने अपने भाषण में देश में फैले भ्रष्टाचार के बारे जिक्र किया। पीएम ने करप्शन को देश के लिए खतरनाक बताते हुए इसे खत्म करने के लिए युवा पीढ़ी से आगे आने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भाई-भतीजावाद, परिवारवाद (वंशवाद और परिवार पर फोकस) सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। क्या भ्रष्टाचार से आजादी ही देश के लिए असल आजादी होगी।

भ्रष्टाचार प्रतिरोध का मार्ग है। कई मायनों में, भ्रष्टाचार वह तरीका है जिससे समाज में कम कुशल अधिक कुशल की कीमत पर आगे बढ़ते हैं। 2005 में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अध्ययन ने संकेत दिया कि 62% भारतीयों ने किसी न किसी समय नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। भ्रष्ट आय क्या है और ईमानदार आय क्या है, इसका आकलन भी एक वैकल्पिक दर्पण अर्थव्यवस्था को सामने ला सकता है। और यह निश्चित रूप से देखने के लिए एक डरावना सच है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज देश के सामने है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, यह एक बड़ा आंतरिक खतरा है। भ्रष्टाचार के दो पहलू होते हैं। देने वाले का पहलू और लेने वाला का पहलू। प्रत्येक निश्चित रूप से समान रूप से दोषी है। वास्तव में अधिक देने वाले और कम लेने वाले हैं। अगर देने वाले बंद कर दे तो भ्रष्टाचार का यह पूरा उद्योग ठप हो जाएगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जन और राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था। लेकिन इससे जो निकला वह लोकपाल के रूप में बिना किसी वास्तविक शक्ति के एक नम्र अधिनियम। भारत में सरकारी प्रणाली कम वेतन

वाली है। मगर उनकी विवेकाधीन शक्तियां निम्नतम स्तर पर भी भ्रष्टाचार की ओर ले जाती हैं। ई-गवर्नेंस को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लानी चाहिए और भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई की जाती तो राष्ट्र निश्चित रूप से एक से अधिक तरीकों से लाभान्वित होगा। राष्ट्र और कई संस्थान जो लोगों की भलाई की देखभाल करते हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। आजादी के इन सभी 75 वर्षों के बाद, भ्रष्टाचार की बिल्ली को घंटी बजाने का समय आ गया है। हमें इसकी जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। इसकी जड़ लेने वाले की तुलना में अधिक देने वालों में निहित है।

भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के लिए नागरिकों में अच्छे नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और एक बच्चे में उसके प्रारंभिक वर्षों के दौरान आत्मसात किए गए मूल्य राष्ट्र की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में पिता, माता और शिक्षक सही मूल्यों को विकसित करके प्रभावशाली दिमाग को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। साथी जीवों के प्रति ईमानदारी, सहानुभूति, सच्चाई, करुणा का भाव पैदा करना केवल माता-पिता द्वारा ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इन सभी के लिए आवश्यक है कि माता-पिता भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें और बच्चे की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करें। समय का एक बड़ा हिस्सा बच्चे द्वारा अपने माता-पिता को देखकर व्यतीत किया जाता है। इसलिए माता-पिता को न केवल उपदेश देना चाहिए बल्कि उपरोक्त मूल्यों का प्रयोग करके उदाहरण पेश करना चाहिए।

जब वे नैतिक आधारित कहानियां सुनाते हैं तो माता-पिता भी बच्चों के रचनात्मक दिमाग का निर्माण करते हैं। बच्चों को अच्छे साहित्य और फिल्मों से रूबरू कराने का काम माता-पिता भी कर सकते हैं। हरिश्चंद्र की कहानियों की तरह जो 'ईमानदारी' को चित्रित करती है। पिता हमेशा बच्चे के लिए पहला रोल मॉडल होता है। बच्चे अपने पिता का अनुसरण करके सीखते हैं। यह समय के साथ उनके दिमाग में समा जाता है और उनके अपने चरित्र का हिस्सा बन जाता है। मां को अक्सर बच्चे के लिए पहली शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। वह उसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, करुणा सिखाती है। यह अक्सर मां ही होती है जो सही और गलत के बारे में हमारी धारणा का मार्गदर्शन करती है। यह प्रारंभिक अवस्था में ही हमारे अंदर समा जाता है और हमारी अंतरात्मा का हिस्सा बन जाता है। मां हमारी धार्मिक मान्यताओं, साफ-सफाई की आदतों को प्रभावित करती है।

शिक्षक बच्चे में जिज्ञासा जगाने, उसकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने और गुप्त प्रतिभा और जुनून को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक अनुशासन को आत्मसात करने और साथियों के साथ बच्चे की अंतर-व्यक्तिगत बातचीत को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि बच्चों ने अपना लगभग आधा बचपन स्कूल में बिताया है, शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। अन्य कारक जैसे मीडिया, सहकर्मी और मित्र, भाई-बहन भी एक व्यक्ति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह शिक्षक, माता और पिता की तिकड़ी है।

ग्लोबल वॉचडॉग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार 'भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' में भारत निचले स्थान पर है। इसने न केवल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक दिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने देश के विकास को रोक दिया है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, राजनीति का अपराधीकरण, जटिल कर और लाइसेंसिंग प्रणालियां, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, पीडीएस पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं का अभाव संकट को और बढ़ा देती हैं। नौकरशाहों को कम वेतन, गरीबी और ऋणग्रस्तता भ्रष्टाचार को जन्म देती है क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति आदि की बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है।

युवा पीढ़ी में सहानुभूति, करुणा, अखंडता, समानता आदि के मूल्य को विकसित करने के लिए भारत में मूल्य शिक्षा बुरी तरह विफल रही है। वैश्वीकरण से प्रेरित जीवनशैली में बदलाव ने समाज के नैतिक ताने-बाने को और गिरा दिया है। अविकसित देशों में शिक्षा का निम्न स्तर नागरिकों को उनके अधिकारों की अज्ञानता की स्थिति में रखता है, उन्हें राजनीतिक जीवन में भाग लेने से रोकता है। जागरूकता की कमी और राज्य पर उच्च निर्भरता के कारण गरीब और हाशिए के लोग भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा शोषण का आसान लक्ष्य बन जाते हैं। व्यक्तिवाद और भौतिकवाद की ओर बढ़ते हुए बदलाव ने विलासितापूर्ण जीवन शैली के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया है। अधिक पैसा कमाने के लिए लोग दूसरों की परवाह किए बिना अनैतिक तरीके भी अपनाने को तैयार हैं।

ऐसे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एक स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011, धन की रोकथाम सहित संस्थागत और विधायी ढांचे को मजबूत करना, सटीक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का सही अर्थों में क्रियान्वयन आवश्यक है।

-- सत्यवान 'सौरभ'

है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए सिर्फ कोरोना काल एवं अन्तराष्ट्रिय परिदृश्य ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि सरकारी नीतियाँ एवं सरकारी तंत्र भी जिम्मेदार है। बड़े घोटाले तो अब नहीं दिखते हैं किन्तु निचले स्तर पर पानी अब भी रिस रहा है। मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा की नीति के सम्पूर्ण अनुपालन के क्रम में इस व्यवस्थागत कमी को भी दूर करना होगा। इसके लिए विपक्ष को भी इस विषय पर साथ आना होगा। पर ऐसा दिख नहीं रहा है।

जिस समय प्रधानमंत्री लालकिले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध की बात कर रहे थे उसी समय कोलकाता में ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अपने नेता अनुब्रत मण्डल के बचाव में हुंकार भर रही थीं। गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड घोटाले के लिए देश के सामने शर्मिंदा होने से

कमजोर कड़ियों की पहचान जरूरी

आगामी विधानसभा चुनावों और उसके साथ 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस दमदार तरीके से उतर सके, इसके लिए सोनिया गांधी और उनके साथ कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की टीम सक्रियता से जुटी हुई है। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने कांग्रेस के भीतर कई रणनीतिक बदलाव किए, खासकर मीडिया प्रबंधन पर काफी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। इसका अच्छा असर भी देखने मिला है। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने-अपने स्तर पर मौजूदा सरकार की नाकामी को उजागर करने और जनता को जागरुक करने का काम कर ही रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरु होगी, जो 148 दिन चलेगी। इस यात्रा का अहम मकसद भारत में नफरत के बढ़ते कदमों को रोकना और एकजुटता का संदेश देना है, इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यह जोश भी भरना है कि वे सब मिलकर भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी तैयारियों और मेहनत के बावजूद कांग्रेस की दशा ऐसी है कि दो कदम वह आगे बढ़ती है और उसके भीतर से ही कोई उसे चार कदम पीछे खींचने का काम कर लेता है। इस काम में सबसे अधिक माहिर जी-23 के नेता हैं, जिनकी स्पष्ट पहचान होने के बावजूद उन पर कार्रवाई न करने का खामियाजा शायद पार्टी को भुगतना पड़ेगा।

पिछले दिनों राज्यसभा चुनावों से पहले कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी थी और अब वो समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल कांग्रेस से अपनी नाराजगी को लेकर लाख तर्क गढ़ सकते हैं, लेकिन इस बात से वो भी इन्कार नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें न केवल मान-सम्मान मिला, बल्कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गईं। यही हाल गुलाम नबी आजाद का भी रहा, जिन्होंने पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रमुख का पद मिलने के कुछ घंटों बाद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण दल है और आजाद उसके कद्दावर नेता माने जाते हैं। पिछले कई महीनों से आजाद अपनी नाराजगी खुलकर दिखाते आए हैं और कई बार तो वे भाजपा के नजदीक दिखाई दिए। राज्यसभा में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उनकी विदाई में मोदीजी ने बहुत भावुक होकर भाषण दिया था। किसी कांग्रेस सांसद के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी भावुकता हैरान करती है। बहरहाल, जब जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद जैसे अनुभवी नेताओं की जरूरत थी, उन्होंने किनारा कर लिया। उनके बाद अब यही काम हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा ने किया है।

हिमाचल प्रदेश में कोई खास जनाधार न होने के बावजूद आनंद शर्मा को इस साल अप्रैल में हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति का प्रमुख बनाया गया था। साल के अंत में यहां चुनाव होने हैं और आनंद शर्मा चाहते तो उनकी उपयोगिता साबित हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इस वजह से इस पद से इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से हटकर सोचने की जरूरत है। आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक ही सीमित रखा जाए। इस बयान से साफ है कि उन्हें कांग्रेस पर गांधी परिवार के प्रभाव से परेशानी है। लोकतंत्र में हरेक को यह अधिकार है कि वह बता सके कि वह किस बात से परेशान है। आनंद शर्मा ने भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का ही उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने ये परेशानी तब बताई है कि जब कांग्रेस में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष न मिलने की वजह से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालने को मजबूर हैं और राहुल गांधी कई लोगों के आग्रह के बावजूद अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं चाहते। यानी गांधी परिवार कांग्रेस को अपने तक सीमित नहीं रख रहा, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथों में ही आती है। अब इस बात को कोई अपनी उपेक्षा या आत्मसम्मान को ठेस से जोड़ते हुए जिम्मेदारी लेने से पीछे हटे तो फिर कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे नेताओं को आगे कितनी तवज्जो दी जाए।

भाजपा इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता बचाने की जुगत में है, क्योंकि उसे कांग्रेस से गंभीर चुनौती मिल सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद अपने हाथों इस मौके को गंवा रही है। विधानसभा चुनावों के साथ-साथ भाजपा ने 2024 के लिए अभी से सीटों का लक्ष्य तय कर लिया है और उस हिसाब से रणनीति भी बना रही है। भाजपा को अगर ऐसा लगता है कि किसी राज्य में उसकी सरकार उसके प्रदर्शन पर बुरा असर डाल सकती है तो रातों रात मुख्यमंत्री के साथ-साथ समूचे केबिनेट को बदलने जैसा कठोर कदम उठा लिया जाता है। पिछले महीनों में ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर भाजपा चुनाव में जीत सुनिश्चित कर लेती है। सफल प्रबंधन का यही तरीका होता है। लेकिन कांग्रेस इस तरह के प्रबंधन में बार-बार नाकाम हो रही है। कमजोर कड़ियों की शिनाख्त होने के बावजूद हम साथ-साथ हैं वाला अभिनय करने का कोई अर्थ नहीं। जनता के बीच इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बल्कि चुनाव के पहले जब आनंद शर्मा जैसे लोग भड़ास निकालते हुए फैसले लेते हैं, तो उससे कांग्रेस की छवि कमजोर होती है।

कांग्रेस अपनी इन कमजोरियों को दुरुस्त कर लेगी, तभी भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएगी।

ज्यादा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस यह बात नहीं समझ पा रही है कि भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस की विश्वसनीयता अन्ना आंदोलन के समय ही समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद जिस तरह से मोदी ने एक एक कर राज्यों से कांग्रेस का सफाया किया और कांग्रेस के पिछले 70 सालों के कारनामे जनता के सामने आए उसके बाद कांग्रेस को कोई भी पीड़ित पक्ष मानने को तैयार नहीं है। बिहार में नितीश कुमार स्वयं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बचे हुये हैं किन्तु अब लालू यादव और उनके परिवार के साथ राजनीतिक गठजोड़ करके इस विषय पर वह भी हाशिये पर चले गए हैं। तेजस्वी यादव पर जब एफआईआर दर्ज हुयी थी तब नितीश ने उनका साथ छोड़ दिया था किन्तु अब जब आरोपों की चार्जशीट लग गयी है तब वह फिर से उनकी गोद में आ गए हैं।

बेमेल गठबंधन और संजय राऊत जेल में :

कुछ इसी तरह का बेमेल गठबंधन पूर्व में महाराष्ट्र में शिवसेना का एनसीपी आदि से हुआ। इन सभी दलों में कोई वैचारिक सामंजस्य नहीं था। शिवसेना के सांसद संजय राऊत सदैव चर्चा में बने रहने वाले सांसद हैं। कभी पहले वह अपने बेतुके बयानो के कारण चर्चा में रहते थे किन्तु अभी वह ईडी के गिरिफ्त में होने के कारण चर्चा में हैं। ईडी ने उन्हे पत्रा चाल घोटाले में गिरफ्तार किया है। संजय राऊत पर आरोप है कि पत्रा चाल घोटाले को अंजाम देने वाले आरोपियों ने संजय और उनकी पत्नी के खाते में एक करोड़ रुपये की रकम भेजी है। हजारों करोड़ के घोटाले सुनने के कारण हालांकि लोगों को एक करोड़ रुपये की रकम बेहद कम दिख रही है किन्तु पत्रा चाल घोटाले का स्वरूप इतना व्यापक है कि इसमे रकम से ज्यादा नीयत का महत्व है। 2008 में मुंबई में 47 एकड़ में बनी इस चाल में रहने वाले 672 लोगों को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी यानि म्हाडा ने प्रस्ताव दिया कि वह यहां से घर खाली कर दें। इसके बाद एक घरों को नए सिरे से बनाकर नए फ्लैट उन्हे दिये जाएंगे। जब फ्लैट का निर्माण कार्य चलेगा तब तक फ्लैट के लोग कहीं और अपमे आवास का इंतजाम कर लें और इस दौरान उनको इसका किराया दिया जाएगा। इसके बाद एक अनुबंध के साथ म्हाडा ने 47 एकड़ जमीन गुरु आशीष कंस्ट्रकशन कंपनी को सौंप दी। इस अनुबंध में यह बात स्पष्ट थी कि इन लोगों के 672 फ्लैट के साथ साथ 3000 अन्य फ्लैट बनाकर यह कंपनी म्हाडा को देगी और शेष जमीन का उपयोग अपने हिसाब से करेगी।

संजय राऊत के करीबी प्रवीण राऊत की इस कंपनी ने 2014 तक 672 लोगों को किराया दिया। इसके बाद किराया देना ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद 47 एकड़ जमीन पर फ्लैट बनाने का काम भी बंद कर दिया गया। इसके बाद आशीष कंपनी द्वारा यह जमीन आठ अन्य बिल्डरों को बेंच दी गयी। 2018 में म्हाडा होश में आया। उसने गुरु आशीष कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद यह बात सामने आई कि आशीष कंपनी उस कंपनी की सहायक कंपनी है जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल हैं। यह पूरा परिदृश्य यह साबित करता है कि किस तरह एक पूरी तैयारी के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया गया। 672 लोगो से उनकी जमीन ली गयी फिर उनको बेघर कर दिया गया। चूंकि, बिना राजनीतिक संरक्षण के यह सब संभव नहीं है इसलिए संजय राऊत की एक करोड़ की रकम भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवारवाद की राजनीति के महाराष्ट्र संस्करण शिवसेना के द्वारा इस घोटाले में लिप्त होना एक बड़ा संदेश है। संजय राऊत उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी व्यक्ति हैं और परिवार के प्रति सेवा भाव में उनकी कोई कमी नहीं है। अब बंगाल की बात करते हैं। वहां अर्पिता मुखर्जी नाम का किरदार है।

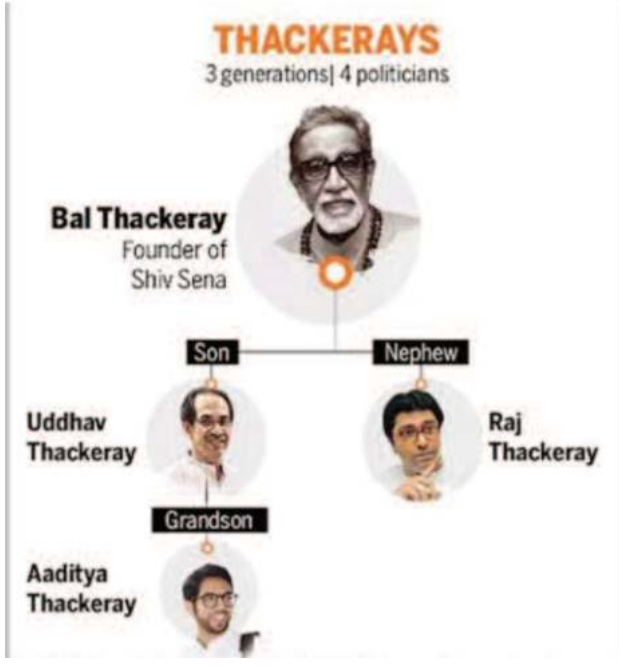

ममता के मंत्री और उनकी करीबी गईं जेल :

ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी से अर्पिता की करीबी है। अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम नकद मिली है। इसके साथ ही कीमती गहने, जमीनों के कागजात और भी कई संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुये हैं। ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। उस दौरान उन्होने कितना घोटाला किया है इसका खुलासा और आंकलन अभी बाकी है। ममता बनर्जी स्वयं पार्थ चटर्जी के क्रियाकलापों से अवगत थी या नहीं इस पर तो अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है किन्तु ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि ममता को इन सबका अंदाजा नहीं रहा होगा। 2019 के पहले जब इस घोटाले से पीड़ित लोग धरना प्रदर्शन आदि कर रहे थे तब ममता ने स्वयं उनको भरोसा दिया था कि वह इस मामले की जांच करवाएंगी। बंगाल में जब यह घोटाला हुआ था तब ही यह सुर्खियों में आ गया था किन्तु सरकार ने तब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तब अचानक रातों रात चयनित लोगों की सूची बदल गयी थी। इस पर लगातार लीपापोती की जाती रही जब तब अभ्यर्थी उच्च न्यायालय नहीं चले गए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिये। सीबीआई जांच के दौरान इसमे ईडी का हस्तक्षेप हुआ। इसकी वजह थी कि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे थे कि इस काले धन को सफेद बनाने का प्रयास हो रहा है।

बंगाल में इसके पहले भी चिट फंड घोटाला हो चुका है जिसके तार बहुत दूर तक जुड़े थे। फिर जब

राष्ट्र को दागी नेताओं से मुक्ति कब मिलेगी?

भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के नाम पर गहरा सन्नाटा पसरा है, जो लोकतंत्र की एक बड़ी विडम्बना बनती जा रही है। कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ होता है। यह कैसी विवशता है राजनीतिक दलों की? अक्सर राजनीति को अपराध मुक्त करने के दावे की हकीकत तब सामने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का मौका आता है। बिहार में नई सरकार में कानून मंत्री बने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कार्तिकेय सिंह हैं। जिन्हें मंगलवार को पटना के दानापुर में अदालत के सामने समर्पण करना था, मगर वे राजभवन में शपथ लेने पहुंच गए।

बिहार में नीतीश कुमार को एक सुशासन के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने राज्य में अपराध के खात्मे की घोषणा के बूते ही अपने राजनीतिक कद को ऊंचा किया। लेकिन ताजा उलटफेर में जिन लोगों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया है, उनमें से कई पर लगे आरोपों के बाद एक बार फिर इस सवाल ने जोर पकड़ा है कि जो लोग राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त बनाने की बात करते हैं, वे हर बार मौका मिलने पर अपने संकल्प एवं बेदाग राजनीति के दावों से पीछे क्यों हट जाते हैं? गौरतलब है कि 2014 में कार्तिकेय सिंह सहित सत्रह अन्य लोगों पर पटना के बिहटा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। कार्तिकेय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर को मारने के मकसद से अपहरण की साजिश रची थी। यह अजीब स्थिति है कि अक्सर साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार देने के दावों के बीच आपराधिक छवि के लोगों को उच्च पद देने का सवाल उभर जाता है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने ही दावों को लेकर वास्तव में गंभीर हैं? ऐसे जिम्मेदार राजनेता अपने दावों से पीछे हटेंगे तो राजनीति को कौन नैतिक संरक्षण देगा?

आज भारत की आजादी का अमृत महोत्सव की परिसम्पन्नता पर एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं अपराधी तत्वों को जिम्मेदारी के पद देकर कैसे सुशासन स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? इस तरह अपराधी तत्वों को महिमामंडित करने के बाद नीतीश कुमार के उन दावों की क्या विश्वसनीयता रह जाती है कि वे बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे?

बड़ा प्रश्न है कि आखिर राजनीति में तब कौन आदर्श उपस्थित करेगा? क्या हो गया उन लोगों को जिन्होंने सदैव ही हर कुर्बानी करके आदर्श उपस्थित किया। लाखों के लिए अनुकरणीय बने, आदर्श बने। चाहे आजादी की लड़ाई हो, देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, अपने वचन की रक्षा हो अथवा अपनी संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा का प्रश्न हो, उन्होंने फर्ज और वचन निभाने के लिए अपना सब कुछ होम दिया था। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, दुर्गादास, छत्रसाल, शिवाजी जैसे वीरों ने अपनी तथा अपने परिवार की सुख-सुविधा को गौण कर बड़ी कुर्बानी दी थी। गुरु गोविन्दसिंह ने अपने दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया और पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों का तो मन्दिर बनना चाहिए। इनके मन्दिर नहीं बने, पर लोगों के सिर श्रद्धा से झुकते हैं, इनका नाम आते ही। लेकिन आज जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन और सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं संकीर्ण बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यादा नकाबें ओढ़ रखी हैं, उसने हमारे सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया। राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोह में हैं। वक्त आ गया है जब देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर संरक्षण देने की कोशिश या राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा पर विराम लगाना ही होगा।

सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा करने वालों की केवल एक ही मांग सुनने में आती है कि मरने के बाद हमारी लाश हमारे घर पहुंचा दी जाए। ऐसा जब पढ़ते तो हमारा मस्तक उन जवानों को सलाम करता है, लगता है कि देश भक्ति और कुर्बानी का माद्दा अभी तक मरा नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा आदर्श कब उपस्थित होगा। राजनीति में चरित्र एवं नैतिकता के दीये की रोशनी मन्द पड़ गई है, तेल डालना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के घरों पर सीबीआई के छापे और जेल की सलाखें हो या बिहार मंत्री परिषद के गठन में अपराधी तत्वों की ताजपोशी-ये गंभीर मसले हैं, जिन पर राजनीति में गहन बहस हो, राजनीति के शुद्धिकरण का सार्थक प्रयास हो, यह नया भारत-सशक्त भारत की प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए।

'सभी अपनी-अपनी पहचान एवं स्वार्थपूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई

व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हैं। राजनीति की दशा इससे भी बदतर है कि यहां जनता के दिलों पर राज करने के लिये नेता अपराध, भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का सहारा लेते हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर जनता को तोड़ने की कोशिशें होती है। पर हम कितना भ्रम पालते हैं। पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार राजनीतिक चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि, ईमानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। नीतीशकुमार से बहुत उम्मीदें है, वे अपनी छवि के मुताबिक फैसले ले और ईमानदार लोगों को मंत्री बनाएं। यही उनके लिये सुविधाजनक होगा और यही उनके राजनीतिक जीवन का दीर्घता प्रदान करेंगा।

बिहार ही नहीं समूचे देश में जन प्रतिनिधि बनने एवं उसे मंत्री बनाये जाने की न्यूनतम अपेक्षाओं में उसका अपराधमुक्त होना जरूरी होना चाहिए। उस पर किसी भी अदालत में कोई मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए। बिहार की मौजूदा सरकार में हालत यह है कि जितने विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से बहत्तर फीसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैरसरकारी संगठन एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तेईस मंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें सत्रह मंत्रियों के खिलाफ गंभीर अपराधों का धाराएं लगी हुई हैं। कब मुक्ति मिलेगी इन अपराधी तत्वों से राष्ट्र को ? राजनीति में चरित्र-नैतिकता सम्पन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल (सम्माननीय) हो और वही एक्सेप्टेबल (स्वीकार्य) हो।

-ललित गर्ग-

अर्पिता के घर नोटों के ढेर निकलने शुरू हुये तो देश दंग रह गया। ममता के करीबी पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता के घर धन ऐसा बरसा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का सारा खेल सामने आ गया। सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल नहीं। भ्रष्टाचार की जड़ें झारखंड तक में दिखाई दीं। झारखंड में खनन सचिव पूजा सिंघल के करीबी चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से ईडी ने 19 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश में अवैध खनन एक बहुत बड़ा व्यापार है। ऐसे में स्वयं खनन सचिव का इसमे लिप्त होना इस बात को भी दर्शाता है कि किस तरह सरकारी तंत्र न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करवा रहा है बल्कि इसके माध्यम से बड़े भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। जब नेताओं और उनके करीबियों का यह हाल है तो इस बात का अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि इस तंत्र से जुड़े लोगों ने किस तरह की अंधी लूट मचा रखी होगी। देश एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी एक अलग ही तरह का उत्सव मना रहे थे। अलग अलग प्रदेशों में गिरफ्तार लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह ईडी का दुरुपयोग कर रही है।

प्रधानमंत्री की मुहिम एवं मोदी का विकल्प :

प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजावाद देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह बात काफी हद तक सही भी है। न्यायपालिका परिवारवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। कुछ ही परिवारों के द्वारा कालेजियम के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था पर कब्जा है। हर तरफ निराश व्यक्ति जब न्यायालय की शरण में जाता है तब उसे वहां न्याय नहीं मिलता है। घोटाले के केस भी न्यायालय में वर्षों लंबित रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था से परिचित व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे वहां शोषण होता है फिर भी पीड़ित न्याय से कोसों दूर रह जाता है। आम आदमी न्याय से दूर है और रसूखदार लोगों के लिए रात में भी न्यायिक दरवाजे खुल जाते हैं। उनके लिए छुट्टी, त्यौहार, दिन रात, सुबह शाम जैसी कोई बाधा ही नहीं है। यह ऐसा विषय है जिस पर मोदी के प्रयास अभी फलीभूत होने बाकी हैं। मोदी विरोधी इन विषयों पर चर्चा से दूर मोदी को हटाने की तैयारी करते दिखते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ विश्लेषक 2024 में मोदी की एक बार फिर से वापसी पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। यह उनकी भावना तो हो सकती है किन्तु यह अभी जनभावना नहीं है। नितीश के भाजपा के अलग होने से तीन परिदृश्य राष्ट्रिय विमर्श का हिस्सा बन गए हैं।

पहला है कि क्या नितीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। दूसरा परिदृश्य उभर रहा है कि क्या नितीश कुमार 2024 के लिए एक महागठबंधन बनाने पर काम करेंगे और उसमे सफल होंगे ? तीसरा, क्या नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आ पाएंगे ? अब चूंकि एक ओर मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तब ऐसे में विपक्षी दल किसी एक बैनर के तले अपनी मजबूत दावेदारी का प्रयास तो करेंगे ही। नितीश कुमार के रूप में उन्हे एक मजबूत चेहरा मिल गया है। विपक्षी दावेदारी में क्षेत्रीय दलों का समूह मोदी के सामने हैं। इसमे कोई एक ऐसा बड़ा राष्ट्रिय चेहरा नहीं है जो पूरे देश में स्वीकार्य हो। ये सभी दल एक एक राज्य या किसी खास क्षेत्र तक अपना सीमित प्रभाव रखती हैं। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में भाजपा के लिए जीत महत्वपूर्ण होगी। जो लोग इस समीकरण को मान कर चल रहे हैं कि जेडीयू और राजद का गठबंधन भाजपा को बड़ा नुकसान करेगा वह लोग इस बात को भूल रहे हैं कि 2019 में सपा-बसपा गठबंधन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा हुआ था। दो बड़े क्षेत्रीय दलों के गठबंधन होने से जब कोई सीट किसी एक दल के खाते में जाती है तो दूसरे सहयोगी दल का उम्मीदवार निश्चित तौर पर या तो साथ छोड़ देता है या कहीं और से दावेदारी करता है। 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन ने 64 सीटें जीतीं थीं। वहीं बसपा को दस और सपा को 5 सीटें ही मिलीं। यदि जातिगत आधार और समीकरण के अनुसार सब होता तो भाजपा का सूपड़ा साफ होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं हुआ। बिहार में भी ऐसा ही परिणाम आना संभावित दिखता है।

जातीय राजनीति नहीं समावेशी राजनीति का चुनावी समीकरण :

विनीत
नारायण

मुखरता के लिए मशहूर 'जनता के जज'

जब भी कभी किसी के बीच कोई विवाद उठता है और वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो अदालत का रुख करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनता को न्यायालयों पर पूरा विश्वास है। परंतु भारत के न्यायतंत्र में लंबित मामलों की संख्या लगभग पांच करोड़ के पार चली गई है। हाल ही में देश के कानून मंत्री ने संसद में कहा कि यदि कोई जज 50 मामलों का निपटारा करता है तो 100 और नए मामले दर्ज हो जाते हैं। देश के न्यायालयों में जजों की संख्या कम है और मामलों की काफी अधिक। ऐसे में न्याय मिलने के बजाय वादी को मिलती है तो सिर्फ़ एक नई तारीख।

कोविड महामारी ने दुनिया भर में 'ऑनलाइन' कार्य को काफी बढ़ावा दिया और इससे संसाधनों की काफी बचत भी हुई। शुक्रवार को रिटायर हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना ने अपना पद सम्भालने के कुछ ही हफ़्तों में इस बात पर काफी जोर दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। जस्टिस रमना के अनुसार ऐसा करना इसलिए उचित रहता क्योंकि अदालत में हुई सुनवाई जनता तक बिना किसी निहित स्वार्थ के सेंसर किए पहुंचती। उन्होंने मुकदमों की मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कई बार संदर्भ से हटकर खबरें छाप दी जाती हैं। इसलिए यदि कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए तो वो जनता के हित में ही होगा।

आज तकनीक का कमाल है की हम घर बैठे आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। कोविड महामारी के चलते जब कोर्ट में केवल ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट की कार्यवाही नहीं रुकी बल्कि लोग अपने घरों से ही कोर्ट की सुनवाई में शामिल होते थे। ऐसे में अदालतों की सुनवाई यदि अधिक से अधिक ऑनलाइन तरीके से होती है तो इसके कई फायदे होते हैं। यदि कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण भी हो तो कोर्ट में फालतू की भीड़ भी नहीं लगेगी। अदालत की कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों को भी इसका लाभ पहुंचेगा। किसी भी उच्च न्यायालय या उस न्यायालय में, जहां एक से अधिक कोर्ट रूम होते हैं, पत्रकारों की दिक्कत तब बढ़ जाती है जब एक से अधिक खास मामले दो अलग-अलग कोर्ट में चल रहे होते हैं। यदि सुनवाई का सीधा प्रसारण हो और वो सुनवाई के बाद भी देखा जा सके तो सुनवाई की खबर लिखने में आसानी हो जाती है। इससे पहले रांची में एक भाषण के दौरान जस्टिस रमना ने कहा था कि 'न्याय से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।'

तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमना की इस पहल को सभी ने सराहा था। उनके कार्यकाल के आखरी दिन भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण देखने को मिला। इस सुनवाई को एक 'सेरिमोनियल बेंच' का नाम दिया गया। इस सुनवाई में शुरुआती दौर में जरूरी मामलों की अगली तारीख तय करने संबंधित कार्यवाही हुई। इसके पश्चात न्यायमूर्ति एन वी रमना को अधिवक्ताओं द्वारा विदाई देने की प्रक्रिया शुरू हुई।

सीधे प्रसारण में वकीलों से खचाखच भरी हुई कोर्ट नम्बर एक का नजारा देखने लायक था। कोर्ट रूम के अलावा कई वरिष्ठ अधिवक्ता ऑनलाइन रूप से भी जुड़े हुए थे। एक-एक करके कभी कोर्ट रूम से तो कभी ऑनलाइन मोड से सभी जस्टिस रमना को उनकी शानदार पारी के लिए बधाई दे रहे थे। विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश खो रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने अपने परिवार के अलावा वकीलों और जजों के परिवारों का भी खास ख्याल रखा।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जस्टिस रमना की कार्यशैली की तारीफ करते हुए उनके द्वारा लिए गए फैसलों और उनके 16 महीने की अवधि दौरान अदालत के कामकाज में किये गये बड़े सुधारों के लिए भी याद किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में जजों की रिक्त पदों को भरने का काम किया। उनके कार्यकाल में जिला अदालतों और हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या में भी इजाफा किया गया। उन्होंने 'जज-टू-पॉपुलेशन रेश्यो' की बात की और कहा कि इसी तरीके से केस लोड को कम किया जा सकता है। एन वी रमना के कार्यकाल में 15 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी नियुक्त हुए हैं।

अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए विदाई संदेशों में कई महिला वकीलों ने भी जस्टिस रमना को उनके द्वारा महिला वकीलों के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया और आभार व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में उस समय एक भावुक माहौल बन गया जब वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे जस्टिस रमना को जनता का जज बताते हुए अपनी बात कहते-कहते रो पड़े। वे बोले, 'मैं आज अपनी भावनाओं को रोक नहीं रख सकता। आपने रीढ़ के साथ अपना कर्तव्य निभाया। आपने अधिकारों को बरकरार रखा, आपने संविधान को बरकरार रखा, आपने जांच और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखी। मुझे बहुत संतोष है कि आपका आधिपत्य न्यायमूर्ति ललित के हाथों में अदालत छोड़ रहा है। हम आपको मिस करेंगे।'

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अपने कार्यकाल के दौरान 225 न्यायिक अफसरों और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश भी की। जस्टिस रमना के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति की गई। इनमें महिला जज सुश्री बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं। 2027 में वे देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। जस्टिस रमना को उनकी मुखरता के लिए भी जाना जाएगा। उनके एक बयान की काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मैं नेता बनना चाहता था, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में आ गया।' अपने कार्यकाल में जस्टिस रमना के सामने कई अहम मामले आए जो सुर्ख़ियों में रहे। इनमें राजद्रोह मामला, बिलकिस बानो गैंगरेप मामला, पेगासस मामला, ईडी के निदेशक की सेवा विस्तार का मामला और शिवसेना पर अधिकार मामला आदि थे। आने वाले समय में यह देखना होगा जिन अहम मामलों की सुनवाई पूरी किए बिना जस्टिस रमना सेवानिवृत हो गए, उन पर भविष्य के मुख्य न्यायाधीशों का क्या रुख रहता है।

लगातार बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की मुश्किलें

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं। बतौर सीएम क्यों यह दौर उनके लिए कठिन माना जा रहा है, इसकी कुछ वजहें बिलकुल साफ हैं। पिछले कुछ समय की घटनाओं पर एक नजर डालते ही ये सामने आ जाती हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर एक के बाद एक घोटालों की जांच हो रही है और आरोपी जेल जा रहे हैं। लपेटे में आने वाले तकरीबन सारे लोग किसी न किसी रूप में ममता बनर्जी या उनकी पार्टी से जुड़े हैं।

आर्थिक मोर्चे पर राज्य बदहाल है। घोटालों और गड़बड़ी के कारण तीन अहम केंद्रीय योजनाओं- मनरेगा, पीएम ग्रामीण सड़क योजना और आवास योजना- का पैसा रुका हुआ है।

स्कूल सर्विस कमिशन की ओर से अवैध शिक्षक भर्ती का मामला ऐसा है कि लाखों रुपये देकर वेटिंग लिस्ट में चल रहे लोग नौकरी विक्रेता नेताओं से पैसा वापस मांग रहे हैं और इस क्रम में कभी-कभी हिंसक भी हो जा रहे हैं।

जो घूस देकर नौकरी पा चुके हैं, उनकी पूरी लिस्ट हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है। उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। ऐसे लोगों की तादाद हजारों में है।

आसनसोल में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाते अणुब्रत मंडल

सोचिए, इस मामले का जब फैसला आएगा, तब ये हजारों लोग तृणमूल नेताओं से घूस की रकम वापस लेने के लिए किस कदर दबाव बनाएंगे। इन हालात में सरकार की मुखिया का संकट आसानी से समझा जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बदहाली भी ममता के लिए एक सिरदर्द है। यह सही है कि इस बदहाली का लंबा सिलसिला मिलता है बंगाल में, लेकिन मुद्दा यह है कि तृणमूल के दौर में भी यह सिलसिला थमा नहीं।

आजादी के वक्त यानी 1947 में बंगाल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 30 फीसदी का योगदान करता था, 2022 में यह योगदान घटकर 3.3 प्रतिशत पर आ गया।

ममता बनर्जी 2011 में बंगाल की पहली बार मुख्यमंत्री बनीं, तब राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 1 प्रतिशत था और आज भी यह आंकड़ा वहीं है।

2011 में राज्य पर 1.92 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो 2020-21 में बढ़कर 5.35 लाख करोड़ हो गया है, जो राज्य के जीडीपी का 37.1 प्रतिशत है।

2014 से ममता सरकार खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लोकल क्लबों को पहली बार दो लाख और बाद में एक-एक लाख का अनुदान देती आई है। 2015-16 में ममता सरकार ने 7194 क्लबों को 88 करोड़ का अनुदान दिया। हकीकत यह है कि हर पाड़ा (बस्ती) में खोले गए ये क्लब कैरम, टीवी और म्यूजिक सिस्टम लगाकर आनंद उठाते हैं। कुछ क्लब रक्तदान शिविर, कंबल वितरण जैसे आयोजनों पर राशि खर्च करते हैं। कुछ लोकल तालाबों में तैराकी या दूसरे खेल आयोजित कर खानापूर्ति करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन क्लबों से जुड़े युवा चुनावों के समय वोटरों को प्रभावित करने का काम करते हैं।

बहरहाल, राज्य में आय के साधन और नया पूंजी निवेश बहुत कम है। ऐसे में सरकार कुछ खर्चों पर लगाम लगाकर धन बचा सकती है। मिसाल के तौर पर, 30 हजार इमामों को हर माह 2500 और 1500 मुअज्जिनों को 1500 रुपये का अनुदान बंद किया जा सकता है। ऐसे में 80 हजार पुरोहितों को हर महीने एक-एक हजार रुपये की मदद रोकी जा सकती है। लेकिन ममता सरकार ऐसी कोई पहल करती नहीं दिख रही।

केंद्र सरकार से भी उनकी सरकार का टकराव बदस्तूर जारी है। लिहाजा केंद्र के रुख में किसी तरह के बदलाव के कोई आसार भी नहीं दिख रहे।

राज्य में पीएम आवास योजना, मनरेगा और पीएम ग्रामीण सड़क योजना में फंड के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्रीय टीम जिलों का दौरा कर रही है। इसे लेकर भी सरकारी अमले में हड़कंप है।

नंदीग्राम के सोनाचूड़ा में लोगों ने रात 10 बजे तक खुले पंचायत कार्यालय का घेराव किया। आरोप था कि वहां बीडीओ कार्यालय का एक कर्मचारी फाइलों की हेराफेरी कर रहा था।

कूचबिहार जिले के भाटीबाड़ी पंचायत कार्यालय में भी रात को ऐसा ही वाकया हुआ। ये सब 1 से 10 अगस्त के बीच की घटनाएं हैं।

कोयला घोटाले में ईडी ने राज्य के 8 आईपीएस अफसरों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। ये लोग तस्करी वाले जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

इस तरह, पूरा सीन सरकार के खिलाफ है और लोगों में आक्रोश है। ममता बनर्जी ने अभी तक अपने तेवर नरम ही रखे थे। उनका रुख यही था कि कानून अपना काम करे, लेकिन पशु तस्करी मामले में तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अणुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद उनका सुर एकदम बदल गया है। 14 अगस्त को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक अणुब्रत को गिरफ्तार करने पर लाखों अणुब्रत पैदा होंगे। वहां मौजूद लोगों से यह भी कहा कि अगर सीबीआई मेरे घर आएगी, तो आंदोलन के लिए तैयार रहें। समर्थक दीदी के इस बदले तेवर को विरोधियों के लिए चेतावनी बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे दीदी के अंदर का भय करार दे रहे हैं।

विपक्ष में भी हाशिये पर

ममता के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की बड़ी नेता बनने की तैयारी में थीं, लेकिन बिहार में हाल में जो हुआ, उससे उनका यह ख्वाब भी पीछे छूटता नजर आ रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह में जब वह दिल्ली आईं तो विपक्षी दल के किसी नेता से नहीं मिलीं। वह न तो नवीन पटनायक और जगनमोहन टाइप की राजनीति कर रही हैं और न ही कांग्रेस को साथ रख विपक्षी खेमे को मजबूत करने की रणनीति अपना रही हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में मदद मिल सकती है, मगर ममता तो खुद चेहरा बनना चाहती हैं।

- बिमल राय

मोदी सरकार में सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की क्यों हो रही है?

मनमोहन सिंह सरकार में सबसे ज्यादा किसी केन्द्रीय एजेंसी की चर्चा रही तो वह थी सीबीआई। लेकिन मोदी के आठ साल के शासन काल में अगर किसी केन्द्रीय एजेंसी की चर्चा सबसे अधिक हुई है तो वह है ईडी। ईडी का अर्थ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक ऐसी एजेंसी है जो मुख्य रूप से मनी लांडरिंग और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होनेवाली आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआत स्वतंत्रता के समय ही हो गयी थी लेकिन 1956 में इसे एक विधिवत एजेंसी के रूप में गठित किया गया। 1947 में स्टॉक एक्सचेंज में होनेवाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन हुआ था जिसे 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में स्थापित कर दिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से फेरा, फेमा और पीएमएलए कानूनों के तहत काम करता है। इन कानूनों में आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो प्रावधान किये गये हैं उन्हीं के तहत यह आरोपियों पर कार्रवाई करता है। इस एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन इसके आफिस देशभर में है। दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसके रीजनल ऑफिस हैं। इसके अलावा लगभग हर राज्य में ईडी के जोनल और सब जोनल आफिस हैं। इस समय ईडी के तहत लगभग दो हजार आफिसर कार्यरत हैं जो विभिन्न सेवाओं से ईडी में डेपुटेशन पर आते हैं। इसमें आईआरएस, आईएएस और आईपीएस सेवाओं से आने वाले अधिकारी होते हैं।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद जैसे जैसे शेयर बाजार का महत्व बढा है वैसे वैसे ईडी के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर की जाने वाली आर्थिक धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए ईडी एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी कार्रवाई करता है। 2018 में केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पीएमएलए कानून में संशोधन करके ईडी को प्रॉपर्टी अटैच करने, आरोपी की गिरफ्तारी करने आदि के विशेष अधिकार भी दे दिये गये थे। फेरा, फेमा और पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को इतने असीमित अधिकार हैं कि वह आरोपी को तीन साल तक जमानत देने से रोक सकता है।

लेकिन इधर कुछ सालों से ईडी स्टॉक एक्सचेंज में होनेवाली आर्थिक धोखाधडी को पकड़ने या जांच करने के लिए चर्चा में नहीं है। बीते कुछ सालों से ईडी की चर्चा राजनीतिक महत्व के लोगों पर की गयी कार्रवाई के कारण चर्चा में रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में ईडी ही इस परिवार की भूमिका की जांच कर रहा है। हाल में ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने अपने ऑफिस पूछताछ करने के लिए बुलाया था जिसके कारण देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स घोटाला, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में एनसीपी नेता नवाब मलिक तो जेल में हैं जबकि शिवसेना के संजय राउत और अनिल परब की जांच चल रही है। इसी तरह फारूख अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक मामले में जांच जारी है। पंजाब कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबियों के यहां ईडी के छापे पड़ चुके हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर छापे पड़ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई पर जेल में है। झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल और पंकज मिश्रा भी ईडी की जांच के दायरे में है जिसकी आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचती दिख रही है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई से मिल रहे कैश, सोना और दूसरे कागजात देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

स्वाभाविक है जब इतने राजनीतिक लोगों पर ईडी कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ विपक्ष भी इकट्ठा होकर इसे बदले की कार्रवाई ही बतायेगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को लेकर सौ से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थी जिस पर एक साथ सुनवाई करते हुए 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में ईडी द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियां और अन्य कानूनी कार्रवाई बिल्कुल सही हैं।

ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी, जमानत और संपत्ति जब्त जैसे अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं के संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रहा है वह वर्ष 2019 में मिले कानूनी अधिकारों के तहत कर रहा है। इन संशोधनों के बाद अब पीएमएलए एक्ट की धारा-24 के तहत अभियुक्त को ही यह साबित करना होता है कि जो उसके पास से जो धन मिला है वह कानूनी रूप से वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को चुनौती दी गयी थी कि जांच एजेंसी के सामने आरोपी द्वारा कबूल की गयी किसी बात को प्रमाण कैसे माना जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ईडी द्वारा की गयी कार्रवाई और दर्ज किये गये बयान कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार्य है।

विपक्ष की आपत्तियां और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर देखें तो 2014 के बाद से ईडी की कार्रवाई में बहुत बड़ा उछाल आया है। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2014 के बीच कुल 112 छापे पड़े थे जबकि 2014 से अब तक ईडी ने 3010 छापे मारे हैं। यानी ईडी की छापेमारी में 27 गुने का उछाल आया है। ईडी की कार्रवाई में आये इस उछाल के ही कारण संभवत विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की सोची समझी कार्रवाई बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि किसी एजेंसी द्वारा अगर आर्थिक धोखाधड़ी की जांच की जा रही है तो क्या इसे सिर्फ इसलिए खारिज किया जा सकता है कि उसके कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गयी है? हां, विपक्ष की आपत्तियों से अलग ईडी की कार्रवाई पर एक सवाल तो ये उठता ही है कि उसके द्वारा दर्ज केस में सजा पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत 17 सालों में 5400 केस दर्ज हुए हैं लेकिन अभी तक सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई है।

ईडी का महत्व भी सीबीआई की जांच पर उठने वाले सवालों के बाद ही बढ़ा है। मोदी सरकार के पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए टिप्पणी किया था कि `सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जो अपने मालिक के आदेश पर बोलता है।' सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर यह टिप्पणी कोयला घोटाले में चल रही जांच पर आयी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि `कुछ अधिकारियों के दबाव में सीबीआई ने रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दिया था।' इस घटना के बाद आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में सीबीआई की बजाय ईडी का महत्व बढ़ने लगा और उसकी चर्चा भी। हालांकि आज सीबीआई और ईडी किसी

एक मामले में अलग अलग तरीकों से जांच कर सकती हैं जैसे पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में दिख रहा है। सीबीआई इसके आपराधिक हिस्से की जांच कर रहा है जबकि ईडी आर्थिक धोखाधड़ी की।

बहरहाल, आरोप प्रत्यारोप के बीच मोदी सरकार में सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की है जिसे आप भ्रष्टाचार की सफाई अभियान भी कह सकते हैं तो विपक्षी दलों पर बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई भी। जिसको जैसी राजनीतिक सुविधा होगी वो वैसी बात कहेगा। लेकिन इन सबके बीच ईडी की अपनी कार्रवाई लगातार जारी है।

90 दिनों में ईडी और सीबीआई ने मारा इन 8 ठिकानों पर छापा, करोड़ों की नकदी के अलावा जब्त हुआ ये सामान

झारखंड में हुए खनन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर रेड मारी। इसके साथ ही बिहार में आरजेडी के नेताओं के घर भी छापेमारी चल रही है। बता दें कि ईडी और सीबीआई ने पिछले तीन महीने में कई छापे मारे हैं। आइए जानते हैं।

झारखंड में हुए खनन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर भी रेड मारी गई। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से दो AK-47 राइफल और 60 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर, बिहार में भी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर छापा मारा है। इसमें लालू यादव की पार्टी RJD के नेता सुनील सिंह और सुबोध राय के अलावा राज्यसभा सांसदों अशफाक करीम और फैयाज अहमद के ठिकाने भी शामिल हैं। पिछले 3 महीनों की बात करें तो दोनों ही जांच एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी की है, जिसमें अरबों की संपत्ति बरामद हुई है। आइए जानते हैं 90 दिनों में ईडी और सीबीआई ने कहां-कहां छापा मारा और क्या-क्या बरामद हुआ।

1- मनीष सिसोदिया
किसने छापा मारा - सीबीआई
कब - 19 अगस्त, 2022
कहां - दिल्ली

दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा 21 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में 11 अधिकारियों के घर भी सीबीआई ने छापा मारा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

2- मुख्तार अंसारी के ठिकाने
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 18 अगस्त, 2022
कहां - दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के घरों पर छापेमारी की है। इसके अलावा अंसारी के भाई अफजल अंसारी के मुहम्मदाबाद स्थित घर पर भी ईडी ने रेड मारी। बता दें कि मुख्तार अंसारी इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद है। उसे पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट गया था।

3- नेशनल हेराल्ड दफ्तर
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 2 अगस्त, 2022
कहां - दिल्ली, कोलकाता

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 2 अगस्त की सुबह नई दिल्ली और कोलकाता स्थित ऑफिस के अलावा 12 जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान नेशनल हेराल्ड दफ्तर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि इससे पहले ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से पूछताछ की थी।

4- रेलवे में रिश्वतखोरी
किसने छापा मारा - सीबीआई
कब - 2 अगस्त, 2022
कहां - पटना, कोलकाता, हाजीपुर, समस्तीपुर और सोनपुर

सीबीआई ने पटना, कोलकाता, हाजीपुर, समस्तीपुर और सोनपुर में छापेमारी कर पूर्व मध्य रेलवे में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया। सीबीआई ने रेलवे के तीन बड़े अफसर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया। छापे के दौरान 46.50 लाख रुपए भी जब्त किए गए। सीबीआई ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के इन अधिकारियों पर जोन के अधीन वेंडरों को सामान की मनमर्जी के मुताबिक लोडिंग के लिए रैक उपलब्ध कराने का आरोप है। इसके बदले में कंपनी द्वारा रेलवे अधिकारियों को हर महीने रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी जाती थी।

5- पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 21 और 28 जुलाई, 2022
कहां - कोलकाता

पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इस दौरान 21 जुलाई को अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश, 20 मोबाइल फोन और 80 लाख की ज्वैलरी मिली। वहीं 28 जुलाई को अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट और अन्य ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां से 29 करोड़ कैश, 3 करोड़ का गोल्ड और 4 लग्जरी कारें बरामद हुईं।

6- **पंकज मिश्रा (हेमंत सोरेन के करीबी)**
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 8 जुलाई, 2022
कहां - धनबाद, रांची

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोल प्लाजा निविदा घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित घर और उनसे जुड़े लोगों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। साहिबगंज, बरहेट और राजमहल के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गए। ईडी की टीम ने पंकज मिश्रा के धनबाद स्थित आवास पर रेड मारी। इसके अलावा दो पत्थर कारोबारियों के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी।

7- **चाइनीज मोबाइल कंपनी Vivo**
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 5 जुलाई, 2022
कहां - देश के 40 से ज्यादा शहरों में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो और इससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की। ईडी ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के लिए देशभर में 40 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई। कंपनी के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण के राज्यों में मौजूद ठिकानों पर छापे मारे गए। बता दें कि 2020 में वीवो में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। देशभर में एक ही आईएमईआई नंबर के 13,500 स्मार्टफोन का पता चला था। ईडी को शक है कि वीवो में फर्जी तरीके से पैसों की हेराफेरी की गई है।

8- **सत्येन्द्र जैन के ठिकाने**
किसने छापा मारा - ईडी
कब - 7 जून, 2022
कहां - दिल्ली

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के 7 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा। इस दौरान एजेंसी को बड़ी संख्या में कैश और गोल्ड बरामद हुआ। ईडी ने छापेमारी में करीब 3 करोड़ कैश बरामद किया है। इसके अलावा जैन के ठिकाने से सोने के सिक्के, बिस्कुट और बड़ी मात्रा में चांदी भी मिली है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन को श्वष्ठ ने अगस्त 2017 में उनके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत अरेस्ट किया था।

- संजय तिवारी

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 40 में से 39 सीटें बिहार में मिली थीं। अब देश जातीय गणित की राजनीति से काफी आगे निकल चुका है। जातीय आधार पर अस्मिता की बात करने वाले दल अभी इस बात को भांप नहीं पाये हैं। बाद में वह लोग ईवीएम आदि कारणों को दोष देते हैं। दूसरी तरफ भाजपा का थिंक टैंक मोदी को सीधे मतदाता से जोड़ने की बात करता है। मन की बात और मोदी की योजनाओं के कारण अब मतदाता भाजपा से नहीं सीधे मोदी से जुड़ा है। इसलिए राष्ट्रिय राजनीति मोदी केन्द्रित हो गयी है जबकि अधिकतर राजनीतिक दल अभी भी राजनीति को परंपरागत अस्मितावादी, जातिवादी, अवसरवादी और समीकरण वाले चश्मे से देखते हैं। पिछले कुछ समय से जातिगत राजनीति का स्थान समावेशी राजनीति ने ले लिया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार जातिगत राजनीति का मुख्य हथियार था। परिवार की आड़ में जातिगत समीकरण के आधार पर बड़े बड़े घोटाले होते थे। लोग अपनी जाति के नेता को वोट देते थे जबकि वह जानते थे कि वह भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ है। परिवारवाद पर चोट के द्वारा मोदी ने क्षेत्रीय दलों की कमर तोड़ दी है। मोदी की तारीफ वैश्विक स्तर पर भारत के दुश्मन भी कर रहे हैं। इमरान खान मोदी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति मैन्यूल लोपेज ने तीन लोगों को वैश्विक संघर्षों को रोकने वाली कमिटी में रखने का सुझाव दिया है। इसमे मोदी, पोप और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम शामिल हैं।

अब ये कुछ ऐसे विषय है जो विपक्ष को भी समझने होंगे। वह सिर्फ राजनीतिक उठापटक के आधार पर मोदी को हराने की बात करते हैं जबकि विपक्ष के पास न तो कोई स्पष्ट वैकल्पिक विचारधारा है और न ही कोई सर्वमान्य नेतृत्व। ऐसे में कैसे राष्ट्रिय स्तर पर वह बिना किसी मुद्दे के एक राष्ट्रिय नेतृत्व को चुनौती दे पाएंगे। विपक्षी दलों के ज्यादातर लोग या तो परिवारवाद के कारण जनता के मन से उतर चुके हैं या भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सिर्फ अपने समर्थकों तक सिमट गए हैं। इनके पास सिर्फ एक नाम राष्ट्रिय राजनीति में राहुल गांधी का है जो जनता में अब विश्वसनीय नहीं दिखते हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता, शरद पवार, स्टेलिन, मायावती, अखिलेश यादव, नितीश कुमार आदि कोई भी नाम सर्वमान्य नहीं दिखता है। नेशनल हेराल्ड की जांच प्रक्रिया से लगता है कि

कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार करते राहुल गांधी

कांग्रेस से देश को यह उम्मीद थी कि यूपीए सरकार के सन 2014 में सत्ता से मुक्त होने के बाद वह अब एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को सही तरह से निभायेगी । वह केन्द्र में एनडीए सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखते हुए उसकी कमियों पर उसे घेरेगी भी और उपलब्धियों पर कभी-कभार उसकी पीठ भी थपथपा देगी। यही तो लोकतंत्र है। पर यह हो न सका। राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नकारा और थकी हुई पार्टी बनाकर रख दिया है। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे पुराने नेता आलाकमान के फैसलों से निराश हैं। गुलाम नबी आजाद और आनन्द शर्मा के चुनाव समितियों के अध्यक्ष पदों से दिए गए इस्तीफों ने यह दर्शा दिया है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दशकों से पार्टी की सेवा करने वाले आजाद और शर्मा जैसे नेताओं को भी अब कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है।

पिछले लगभग दो-तीन वर्षों से कांग्रेस लगभग नेतृत्व विहीन सा होकर रह गया है। कहना न होगा कि इसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहते और नाटकबाजी कर रहे हैं। वे न तो स्वयं कांग्रेस को नेतृत्व देने में सक्षम हैं, न ही किसी भी सक्षम नेता को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने को तैयार हैं।

राहुल गांधी कांग्रेस विहीन भारत के नरेंद्र मोदी के सपने को जाने-अनजाने खुद ही साकार कर रहे हैं। कांग्रेस के बाकी नेताओं को अब गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस को फिर से एक जुझारू पार्टी बनाया जा सकता है। कांग्रेस बिखराव की स्थिति से गुजर रही है। उसके पास समझदार नेताओं की भारी कमी है। ए.के. एंटनी जैसे तपे हुए नेता रिटायर हो गये हैं। वे वापस अपने गृह प्रदेश केरल चले गये हैं।

कांग्रेस निरंतर अपना जनाधार खोती ही चली जा रही है। यह न केवल उसके लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिये भी शुभ संकेत नहीं है। उसे विपक्ष की मजबूत और स्वस्थ भूमिका का निर्वाह करना चाहिए था। उसे जनता के मुद्दों पर सड़कों पर आना चाहिए था। पर ताजा हालात यह हैं कि उसके पास जमीनी नेताओं का घोर अभाव है। याद कीजिये कि कब कांग्रेस के नेता पिछली बार जनता के सवालों पर सड़कों पर आये।

बेशक, कांग्रेस के लिये यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि वह एक वृद्ध और बीमार अंतरिम अध्यक्ष के माध्यम से संचालित हो रही है। सोनिया गांधी जब स्वस्थ थीं तब उन्होंने पार्टी को कुल मिलाकर अपने तरीके से एक नेतृत्व दिया था। लेकिन, अब उनमें वह क्षमता और सक्रियता सम्भव नहीं है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नहीं एक 24 घण्टे, सातों दिन और 12 महीने सक्रिय रहने वाला अध्यक्ष चाहिये जैसे कि अमित शाह थे और जेपी नड्डा हैं। ये दोनों दिन रात पार्टी को मजबूती देने के लिये काम करते रहे और कर रहे हैं। राहुल गांधी को पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाना चाहिये। पर वे इस दायित्व तक को भी नहीं लेते। यह बहुत ही दुःखद स्थिति है कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली, आजादी के बाद पचपन साल तक देश का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी अपने लिये एक सक्षम अध्यक्ष तक नहीं तलाश कर पा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो सन 2024 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक होकर और अपना जनाधार खोकर इतिहास की वस्तु बन कर रह जायेगी। कांग्रेस को डुबोने का पूरा कलंक राहुल गांधी के मस्तक पर ही लगेगा जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से सार्थक या सक्रिय संवाद तक कायम नहीं कर पा रहे हैं।

कांग्रेस का बंटाधार कराने में ऐसे कुछ होनहार सलाहकारों का अमूल्य योगदान है। क्या ऐसे ही कुछ होनहार सलाहकारों के कहने पर राहुल अपने को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से अलग रखने का कथित संकेत दे रहे हैं? फिर उन्हें स्वयं इस सवाल पर गंभीर मंथन करना चाहिए।

अगर यह उनका अपना सुविचारित फैसला है तो उन्हें नये कांग्रेस अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में पूरी सक्रियता से जुट जाना चाहिए। अब राहुल गांधी अपने घर को सही किये बगैर मां और बहन को लेकर विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। वे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की `भारत जोड़ो यात्रा' करने की बात कर रहे थे, पर जा रहे हैं विदेश? कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू होने वाली पदयात्रा को उन्होंने जन यात्रा बनाने का आह्वान किया था और कहा कि यह उनके लिए तपस्या है क्योंकि पूरे देश को जोड़ने में लंबा वक्त लगेगा। यदि यह तपस्या ही थी तो अपनी माता जी के मेडिकल चेक अप के नाम पर अपनी बहन के साथ अनिश्चितकाल के लिये उनकी विदेश यात्रा जरूरी है?

बेशक, उन्हें अपनी आगामी देश भर की यात्रा से भारत को करीब से जानने में मदद ही मिलेगी। यदि वे विदेश यात्रा के बजाय भारत यात्रा करेंगे। लेकिन, राहुल गांधी तो अपनी भारत यात्रा में एन.जी.ओ. को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों ? कारण दो ही हो सकते हैं, पहला कि उन्हें कांग्रेस के संगठन या कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। दूसरा यह कि तीस्ता सीतलवाड़ किस्म के जो एन.जी.ओ. भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा में चंदा इकठ्ठा कर राष्ट्र विरोधी कार्यों में संलग्न रहकर अपने आकाओं को खुश रखकर पैसे बटोरते थे और देश में अस्थिरता उत्पन्न करते थे, उनसे राहुल गांधी की अंदरखाने कोई सांठगांठ हो गई है। पर क्या उन्हें कांग्रेस शासित राजस्थान के जालौर में नहीं जाना जाना चाहिए था जहां पर एक बेशर्म शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत हो गई? इतनी जघन्य घटना पर राहुल गांधी ने गहरा दुख जताते हुये ट्वीट कर कहा-`जालोर में निर्दयी शिक्षक द्वारा एक मासूम दलित बच्चे को बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसकी मृत्यु की घटना बेहद दुखद है। मैं इस क्रूर कृत्य की भर्त्सना करता हूं। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने कहा कि आरोपी को कठोर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।' क्या यह करना मात्र पर्याप्त है? क्या उन्हें या उनकी बहन और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को जालौर नहीं जाना चाहिए था दलित छात्र के परिजनों से मिलने के लिये? कांग्रेस शासित राजस्थान में ही कन्हैया नाम के दर्जी का सिर काट डाला गया था? राहुल गांधी बात-बात पर भाजपा सरकारों की निंदा करते हैं, पर कभी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते।

कांग्रेस के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी हो रही है कि वह बड़े अहम सवालों पर भी एक राय तक नहीं बना पाती। अब `अग्निपथ' योजना को ही लें। इस योजना की कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी पैरवी कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सेना में भर्ती की यह नयी योजना `राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने अपने एक लेख में कहा था कि `अग्निपथ' रक्षा सुधारों और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके विपरीत कांग्रेस आला कमान की `अग्निपथ' योजना के खिलाफ था। यानी कहीं भी तालमेल तक नहीं है। देखिये, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। इन नतीजों के बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि यदि गांधी परिवार से कांग्रेस का पीछा नहीं छुड़ाया गया तो सन 2024 तक इसकी हालत और पतली होगी। कांग्रेस सारे देश में सिकुड़ रही है। पर मजाल है कि राहुल गांधी या बाकी कांग्रेसी जागे।

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

छापे में नोटों के अंबार। अर्थक्रांति दे रहा समाधान?

आजकल अक्सर ही प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य जांच के छापे में बड़ी मात्रा में कैश, सोना या बेनामी संपत्ति के कागजात मिलने का समाचार प्राप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से लगभग 50 करोड़, उसके पूर्व झारखंड कीआईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया जिनके यहां से 19 करोड़, कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां से 284 करोड़ नगद बरामद किया गया ढ्ढ इस प्रकार की अन्य कई घटनाएं हाल के दिनों में हमसभी को सुनने को मिलीं। जांच एजेंसियों की भी एक सीमा है, वे कितने भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों या व्यापारियों के यहां छापे की कार्यवाही कर सकती हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित कार्यवाही भी बताता है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस समस्या का मूल कारण पता करके उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार देश में हो रहा है उसका मुख्य कारण कालेधन की उपलब्धता है जो 2000, 500 के बड़े नोट के माध्यम से उपलब्ध है। जबतक देश में 2000, 500 के बड़े नोट चलन में हैं तब तक भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। यहां समझने की मुख्य बात यह है कि कालेधन के निर्माण का सबसे मुख्य कारण देश की दोषपूर्ण कर प्रणाली है विशेषरूप से आयकर। जबतक देश की टैक्स व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तबतक कालेधन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव नहीं है। इस प्रकार की देश की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थक्रांति संगठन ने सरकार एवं देश के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है जिसमें मुख्यरूप से 100 से बड़े नोट बंद करने और सभी टैक्स समाप्त करके मात्र 2% बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स (केवल तब जब खाते में पैसा जमा होगा) लगाने की बात कही गई है। इससे सरकार को पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति होगी और विकास व अन्य योजनाओं के लिए सरकार को कर्ज नहीं लेना होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। बड़े नोट बंद होने से भ्रष्टाचार, कालेधन के साथ आतंकवाद, अपराध, नक्सलवाद, हवाला, घोटाला, नकली नोट आदि समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा।

-जय प्रकाश मिश्रा

राहुल और सोनिया शायद ही बरी हो सकें। इन दोनों के देश छोडकर जाने की चर्चा भी होने लगी है। कांग्रेस के द्वारा गांधी परिवार से बाहरी अध्यक्ष बनने की चर्चा इन बातों को बल भी देती हैं। गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ दी है।

पर इन सब राजनीतिक विषयों से महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार का उन्मूलन है न कि सिर्फ दिखावटी कार्यवाही। मोदी को प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक ठोस तंत्र बनाना होगा। सरकार को आठ साल होने के बाद भी अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। घोटालेबाजों और परिवारवाद पर प्रहार और निर्णायक युद्ध की बात अच्छी है किन्तु इसके साथ ही एक ऐसी व्यवस्था बनाना भी आवश्यक है जिसमे घोटाले हो ही न पाये। चूंकि, अभी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पायी है इसलिए जिसको जहां मौका लगता है, वह लूटपाट से बाज नहीं आता है। मोदी द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद सीबीआई और ईडी को तोता कहने वाले आरोप भी नहीं लगेंगे और मोदी द्वारा शताब्दी वर्ष में विकसित भारत का स्वप्न भी वास्तविकता में साकार होगा। ■

क्या जम्मू-कश्मीर से कांग्रेस का सफाया करके ही दम लेंगे गुलाम नबी आजाद?

● ब्यूरो रिपोर्ट

कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने का फैसला किया है। इन नेताओं के सामूहिक इस्तीफे से जहां कांग्रेस हिल गई है, वहीं आजाद ने कांग्रेस को और बड़े झटके देने का ऐलान किया है।

गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। हर रोज बड़े पैमाने पर नेता पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के उस वक्त और बड़ा झटका लगा जब केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद समेत जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

तारा चंद के अलावा, पूर्व मंत्री माजिद वानी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी घरू राम और पूर्व विधायक ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ हाई प्रोफाइल नाम हैं।

कांग्रेस को अभी और झटके लगेंगेः आजाद

कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले इन सभी 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने का फैसला किया है। इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक संयुक्त त्यागपत्र सौंपा है। 64 नेताओं के सामूहिक इस्तीफे से जहां कांग्रेस हिल गई है वहीं आजाद ने कांग्रेस को और बड़े झटके देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 'सभी ने मेरे लिए इस्तीफा दिया है। सभी मेरे साथ हैं। कांग्रेस को अभी और कई झटके लगेंगे।'

गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद ने जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी शुरू करने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद जम्मू-कश्मीर के कई पूर्व मंत्री और विधायकों सहित एक दर्जन से ज्यादा प्रमुख कांग्रेस नेता, सैकड़ों पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों के अलावा, नगर निगम के नगर सेवक और जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं ने पहले ही आजाद की पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी है।

सोनिया-राहुल के खिलाफ आजाद की तल्ख टिप्पणियों के मायने कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार तल्ख लहजे में कांग्रेस और इसकी कमान संभालने वाले नेहरू गांधी परिवार पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कई प्रवक्ताओं ने आजाद पर बीजेपी से सांठगांठ करने के आरोप लगाए थे। इनके जवाब में आजाद ने बीजेपी प्रवक्ताओं को भी आइना दिखाया था। पार्टी छोड़ते वक्त आजाद ने सिर्फ राहुल गांधी को पार्टी के बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद वह अब सोनिया गांधी को भी नहीं बख्श रहे हैं। आजाद के तल्ख लहजे और तीखे तेवरों को देखते हुए लगता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से पार्टी कांग्रेस का सफाया करने की ठान ली है। कांग्रेस छोड़ते वक्त आजाद ने राहुल गांधी पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था। लगता है आजाद जम्मू-कश्मीर से कांग्रेस का सफाया करके अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर आजाद के बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है।

क्या कांग्रेस ने आजाद को हल्के में ले लिया?

जिस तरह कांग्रेस के तमाम नेता आजाद के पीछे खड़े हो रहे हैं, उससे ये आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले चुनाव में कहीं कांग्रेस यहां से हमेशा के लिए साफ ना हो जाए। कांग्रेस में कहा जाता था कि आजाद जमीनी नेता नहीं है। जम्मू-कश्मीर में उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि 20 साल पहले 2002 उन्हीं के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी और पीडीपी के साथ गठबंधन में करके सत्ता में आई थी। उसके बाद कांग्रेस 2008 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ी।

चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी

गठबंधन की सरकार बनी थी। यह सरकार भी पूरे 6 साल चली थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद आजाद को जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं का जिस तरह व्यापक समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैरान हैं। उनका यह दावा हवा हवाई होता दिख रहा है कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार नहीं है तो फिर एक हफ्ते में ही इतने सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर आजाद दामन क्यों थाम लिया है, जबकि अभी उनकी पार्टी बनी भी नहीं है और न ही उसका कोई नाम तय हुआ है? यह सवाल अब कांग्रेस आलाकमान को परेशान कर रहे हैं।

क्या पवार और ममता की राह पर आजाद?

यूं तो आजादी के बाद कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं ने करीब 60 पार्टियां बनाई हैं। लेकिन इनमें से कुछ को ही ही कामयाबी मिली। ज्यादातर नेता गुमनामी के अंधेरे में खो गए। कई पार्टियों ने राज्यों में कांग्रेस को खत्म करके अपनी जगह बनाई है। इस मामले में सबसे पहले ममता बनर्जी का नाम आता है। ममता बनर्जी ने 90 के दशक में कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य पर है। जबकि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी हैं।

इसी तरह 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर कांग्रेस छोड़ने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र में खुद को साबित किया है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी कांग्रेस से बड़ी हो गई है। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद कांग्रेस ने उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इससे नाराज होकर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर कांग्रेस बनाई और आज वह भारी बहुमत से सत्ता में हैं। कांग्रेस का आंध्र प्रदेश से सफाया हो गया है। आजाद के तेवरों और उन्हें मिल रहे समर्थन को देखकर लगता है कि जम्मू-कश्मीर भी उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जहां कांग्रेस के बागी नेताओं ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है।

कांग्रेस की तरफ से तल्खी कम करने की कवायद

पिछले शुक्रवार को जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल था। 10 जनपथ के करीबी नेता आजाद के कांग्रेस छोड़ने से काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें लगता था कि आजाद से कांग्रेस का पिंड छूट गया है। लेकिन आजाद के लगातार तीखे होते जा रहे हमलों और उन्हें मिल रहे जनसमर्थन से कांग्रेस आलाकमान हक्का-बक्का है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और आजाद के साथ जी-23 ग्रुप ग्रुप में शामिल रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यसभा के उप नेता रहे आनंद शर्मा ने मंगलवार को आजाद से मुलाकात करके गुजारिश की है कि वह सोनिया-राहुल पर हमले करना बंद करें। जब वो कांग्रेस छोड़ ही चुके हैं तो ऐसों हमलों का क्या मतलब है। इन तीनों नेताओं ने मुलाकात को शिष्टाचार के नाते हुई मुलाकात बताया बताया है, लेकिन यह भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर आजाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाने की पहल करते है तो ये उनके साथ जा सकते हैं। तीनों ही नेता कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ जब तब मुंह खोल कर रहते हैं। तीनों ही आलाकमान से नाराज भी चल रहे हैं।

कांग्रेस से सीधे टकराव पर आमादा आजाद

कांग्रेस नेता आजाद पर पीएम मोदी और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह आजाद कांग्रेस से सीधी टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं। उससे इन आरोपों में कहीं न कहीं दम तो लगता है। वहीं ये भी हो सकता है कि आजाद सोनिया और राहुल के रवैया से कुछ ज्यादा ही आहत हुए हैं। शायद यही वजह है कि अब उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ इन्हें भी सबक सिखाने की ठान ली है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल रैली रखी है।

आजाद ने भी इसी दिन जम्मू में अपनी पहली रैली रख दी है। इसी रैली में वह अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आजाद ने कांग्रेस की रैली वाले दिन ही अपनी रैली रखकर कांग्रेस से अपनी सीधी टक्कर दिखाने की कोशिश की है। कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही आजाद लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। लिहाजा उनकी पहली रैली को मीडिया में कांग्रेस की रैली के समानांतर तवज्जो मिलेगी। कांग्रेसी नेता इसीलिए आजाद को बीजेपी की कठपुतली बता रहे हैं।

कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी छोड़कर जाने वाले तमाम नेताओं पर पहले से ही बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं लेकिन उनके उठाए सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश नहीं की। आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद भी पार्टी उसी ढर्रे पर कायम है। उन कमियों को दूर करने पर उसकी कोई तवज्जो नहीं है, जिनकी वजह से लंबे समय तक वफादार रहे नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए हैं।

गुलाम नबी आजाद की तरफ से लग रहे झटके पर झटकों के बीच कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं आजाद के सामने भी जम्मू-कश्मीर में खुद को शरद पवार, ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी की तरह साबित करने की बड़ी चुनौती है।

दिल्ली का दारू घोटाला

● ब्यूरो रिपोर्ट

शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज FIR में सिसोदिया आरोपित नंबर एक हैं। वही, प्राथमिकी में 14 अन्य नाम भी हैं, जिनमें दो कंपनियों के नाम शामिल हैं।

ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति-2021 से जुड़ा हुआ है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस विभाग के भी प्रमुख हैं। इसलिए इस घोटाले के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया है। हालांकि, बाद में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले हुए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है।

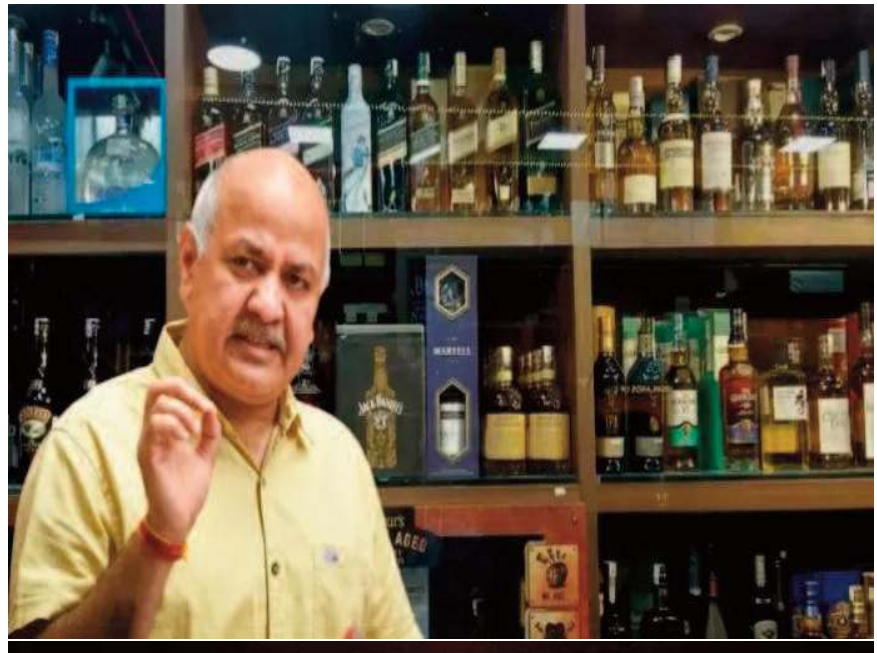

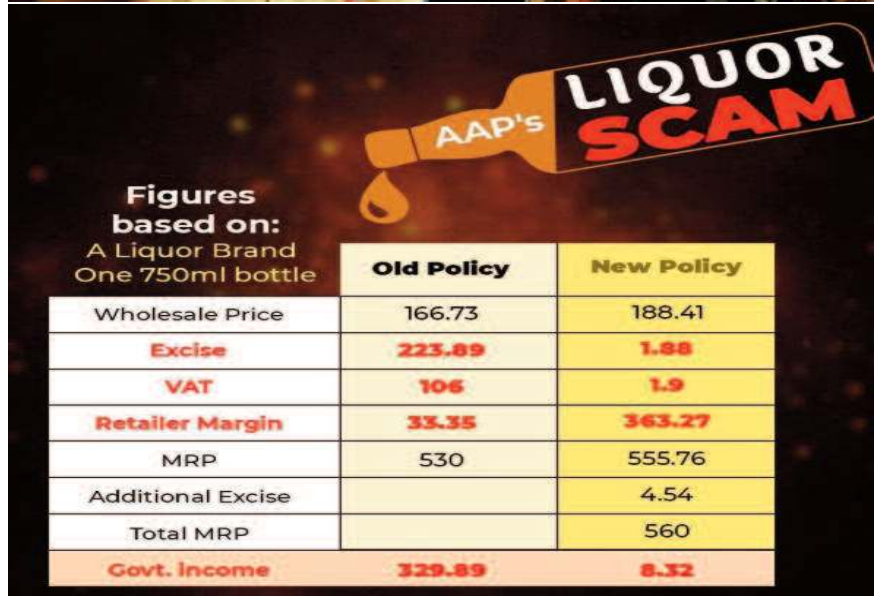

	Old Policy	New Policy
Wholesale Price	166.73	188.41
Excise	223.89	1.88
VAT	106	1.9
Retailer Margin	33.35	363.27
MRP	530	555.76
Additional Excise		4.54
Total MRP		560
Govt. Income	329.89	8.32

क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति

नई आबकारी नीति 2021-22 दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 कर दी थी। इसके साथ ही होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इसके तहत वे अपनी छतों समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते थे।

पुरानी आबकारी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई नीति में बार में मनोरंजन का इंतजाम करने की भी छूट दी गई थी। इसके अलावा, बार काउंटर पर खुल चुकी शराब की बोतल की शेल्फ लाइफ पर से भी पाबंदी हटा ली गई थी।

इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। इस नीति के यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। इन दुकानों के मालिक निजी क्षेत्र के लोग होंगे।

दिल्ली सरकार का तर्क

नई आबकारी नीति 2021-22 नीति को लेकर दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को कम करना और शराब व्यापार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त होगी।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि नई आबकारी नीति से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसका इस्तेमाल वह विकास के अन्य कामों में करेगी। इसके साथ ही शराब खरीदने वालों की वह शिकायत

भी दूर होगी कि उनके इलाके में शराब की दुकानें दूर है। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी।

भाजपा सहित विपक्षी दलों ने उठाई थी आपत्ति

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर भाजपा (BJP) सहित विपक्षी दलों ने आपत्ति उठाई थी। भाजपा का कहना था कि दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र घटाकर लोगों को शराबी बना रही है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नई आबकारी नीति में केवल 16 प्लेयर्स को इजाजत दी जा सकती थी, जिसके कारण एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके कारण छोटे वेंडर्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं।

विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगया। उन्होंने कहा कि शराब की थोक कीमतों के बारे में तो पता है, लेकिन उन्हें किस कीमत पर बेचना है, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है।

दिल्ली सरकार पर आरोप

दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि कैबिनेट को भरोसे में इसे जल्दबाजी में लागू किया गया। इतना ही नहीं, इसके लिए तमाम नियमों और प्रक्रियाओं की भी अनदेखी की गई। यह भी आरोप लगा कि एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से काम कर रहा है।

यहां तक कि कैबिनेट से यह भी पास करवा लिया गया कि अगर नीति को लागू करने के दौरान कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सकेंगे। जब तत्कालीन उप-राज्यपाल ने इस पर आपत्ति उठाई तो 21 मई की कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को वापस ले लिया गया।

मुख्य सचिव ने LG को दी रिपोर्ट

नई आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप-राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई नीति को लागू करने में जीएनसीटी एक्ट-1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है।

अपनी रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह से लाभ पहुंचाए गए। इसके लिए जान-बूझकर प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब उत्पादन, थोक और खुदरा बिक्री से

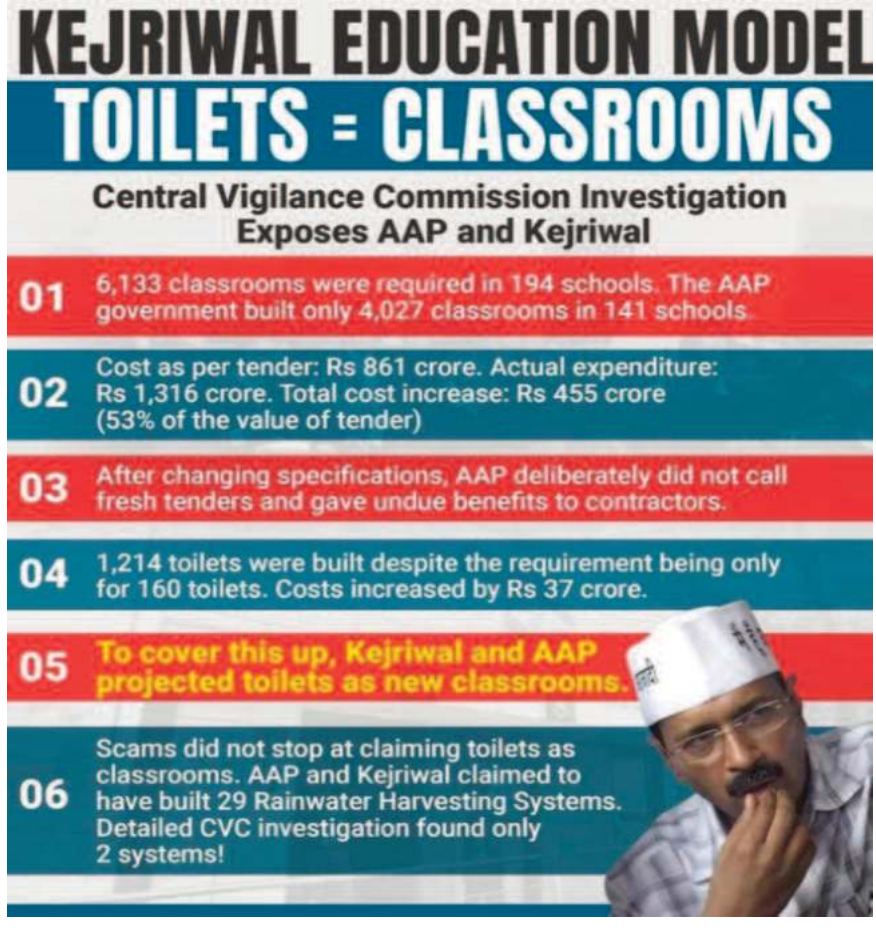

दारू घोटाला : कैसे हुआ खेला ....

आये थे भ्रष्टचार मिटाने पर खुद भ्रष्टचारी बन गये, आये थे नैतिकता कायम करने पर खुद अनैतिक हो गये, आये थे बुराइयां मिटाने पर खुद शराब की बुराइयों में समा गये, आये थे दिल्ली को वर्ल्ड क्लास का शहर बनाने पर दिल्ली को झुग्गियों का शहर बना डाले, आये थे दिल्ली को साफ और स्वच्छ पानी पिलाने के लिए पर दिल्ली की जनता को शराब में डूबा दिये, आये थे तिरंगा को मान बढाने पर रोहिंग्या, बांगलादेशियों और पाकिस्तानियों के संरक्षक व सहयोगी बन गये। ये पक्तियां अरविद केजरीवाल के उपर सही बैठती है। केजरीवाल का एक मंत्री सत्येन्द्र जैन पहले से ही भ्रष्टचार के आरोप में जेल में बंद हैं, उस पर बैमानी कंपनियां बना कर पैसों की हैराफेरी करने का आरोप है। सत्येन्द्र जैन उस स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री है जिस स्वास्थ्य मंत्रालय का अरविंद केजरीवाल खुद डुगडुगी बजाता है और कहता है कि उसका मुहल्ला किलिनिक दुनिया का सबसे लोकप्रिय मॉडल है, हालांकि दिल्ली की जनता यह जानती है कि मुहल्ला किलिनिक में कौन सा इलाज होता है और कौन सी दवाइयां वहां पर मिलती है, अधिकतर मुहल्ला किलिनिक सफेद हाथी के दांत हैं। मुहल्ला किलिनिक के नाम पर करोड़ों रूपयों का घपला हो रहा है। जब कोरोना काल था तब मुहल्ला किलिनिक गायब थी, दिल्ली की जनता उस भीषण व जानलेवा काल में सिर्फ केन्द्रीय अस्पतालों के भरोसे ही रही थी।

अब केजरीवाल का सबसे प्रिय पात्र, जिसे वे उप मुख्यमंत्री बना कर रखा है वे भी भ्रष्टचार के मीनार बन गये हैं। यहां बात केजरीवाल सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीश सिसौदिया की हो रही है। मनीष सिसौसिया के घर में सीबीआई का छापा पड़ चुका है। मनीष सिसौदिया के घर से सीबीआई ने भ्रष्टचार के कागजात यानी कि सबूत जुटाए हैं। पहले तो मनीष सिसौदिया और अरविंद केजरीवाल ने खूब पैंतरेबाजी की थी, जमकर धमकियां पिलायी थी और कहा था कि हिम्मत है तो सीबीआई जांच करा कर दिखाओ, भ्रष्टचार के प्रमाण पत्र दिखाओ। अब सीबीआई ने छापा मार कर भ्रष्टचार के सबूत भी जुटाये हैं और भ्रष्टचार की केजरीवाल-सिसौदिया गिरोह का भी पता कर लिया है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने जो भ्रष्टचार के सबूत जुटाये हैं उनमें केवल मनीष सिसौदिया के ही नाम नहीं बल्कि उसके भ्रष्टचार के गिरोह में कोई दर्जन भर से अधिक लोगों के नाम हैं।

भ्रष्टचार की बात उसी दिन पक्की हो गयी थी जिस दिन से शराब की दुकानों में बेतहाशा भीड़ जुटने लगी थी, लंबी-लंबी भीड़ की कतारें दिख रही थी। शराब की दुकानों पर लगी बड़ी भीड़ से लोग हैरान और परेशान थे। एक बोतल, एक पैटी पर दूसरा बोतल और दूसरी पैटी मुफ्त थी। जब कोई मुफ्त की चीज मिलती है तो फिर उस पर लालची लोग दौड़ लगाते ही है। जब शराब पर एक फ्री मिलेगी तब शराबी भीड़ लगायेंगे ही। लेकिन इस भीड़ के नेपथ्य में भ्रष्टचार की कहानियों की तह पर तह होगी, इसकी उम्मीद कम ही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार तर्क देती थी कि इससे दिल्ली सरकार की आय बढ़ेगी और दिल्ली की जनता कच्ची शराब पीना बंद करेगी, कच्ची शराब पीने से कितनी भयानक बीमारिया होती हैं, यह भी स्पष्ट है। कई राज्यों में जहां शराब बंदी है या फिर कच्ची शराब बनाने और पीने पर प्रतिबंध है वहां पर जहरीली शराब पीने से हुई मौतें भी ध्यान खीचंती हैं। लेकिन भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल की इस शराब नीति के खिलाफ आंदोलनों की झडी लगा दी थी और एक पर एक धरणा-प्रदर्शनों का आयोजन की थी। भाजपा का सीधा आरोप था कि इस शराब नीति में अरबों रूपयों का घोटाला हुआ है, प्राइवेट पार्टियों से पैसों की उगाही की गयी है।

भ्रष्टचार की बात पक्की होने के प्रमाण भी मिल गये हैं। मनीष सिसौदिया और अरविंद कजेरीवाल तो क्या आम आदमी पार्टी के पास इस करतूत का कोई जवाब हो ही नहीं सकता है कि टेंडर शुल्क क्यों माफ किया गया? टेंडर शुल्क कोई एक-दो करोड़ का नहीं है बल्कि टेंडर शुल्क की राशि जानकार आप हैरान और परेशान भी हो सकते हैं। टेंडर शुल्क की राशि डेढ सौ करोड़ के आसपास है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने शराब माफियाओं को डेढ सौ करोड़ रूपये का माफी दिया था। अगर टेंडर शुल्क माफ नहीं किया गया होता तो फिर ये डेढ़ सौ करोड़ रूपये दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार के खाते में आते। अगर सिसौदिया की शराब नीति अच्छी थी तो फिर इन्होंने अपनी ही शराब नीति क्यों वापस ली थी। सरकारी शराब दुकानों को बंद कर प्राइवेट दुकानों को शराब बेचने का आदेश क्यों दिया गया? प्राइवेट लाइसेंसे ऐसे-ऐसे को दिये गये जो मनीष सिसौदिया के नजदीक थे और शराब के क्षेत्र में बडे खिलाड़ी रहे हैं। जाहिरतौर पर प्राइवेट कंपनियों को शराब की दुकानें खोलने के लिए गलत ढंग से लाइसेंस दिये गये। इसके अलावा शराब दुकानें आवासीय आबादी के बीच भी खोली गयी।

ऐसे बैहया लोगों से कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। क्या आप शराब बेचने और दिल्ली शहर को शराब में डूबोने के लिए आये थे? देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जो शराब से होने वाले नुकसानों को देखते हुए शराब बेचना और शराब पीलना अनैतिक व अपराध माना गया है। देश के महापुरूषों ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया था और शराब को सबसे बड़ी बुराई बतायी थी। देश की लाखों महिलाएं अपने घर और परिवार को बचाने के लिए शराब दुकानों को बंद कराने में संघर्ष करती रही हैं। शराब के नशे से न केवल घर-द्वार बर्बाद होता

है बल्कि खेलता-हंसता परिवार और खुशहाल जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। कभी हरियाणा में बंसीलाल ने पूर्ण शराब बंदी लागू किया था। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में भी पूर्ण शराबबंदी हैं। अगर आप महान समाज सुधारक हैं, अगर आप महान राजनीतिज्ञ हैं तो फिर आपका काम शराब बेचना और देश की राजधानी दिल्ली को शराब में डूबोने का नहीं होना चाहिए था।

मनीष सिसौदिया सिर्फ शराब मंत्री ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आईकॉन बताया जाता है, दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल बताया जाता है। फिर इन प्रश्नों का उत्तर आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं देते कि केजरीवाल, सिसौदिया और आम आदमी पार्टी के विधायकों-नेताओ के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते है? एक ही प्रकार के लेख न्यूयार्क और खलील टाइम्स में छपवाने की करतूत क्यों करनी पड़ी। प्राइवेट स्कूल के बच्चों का फोटो सरकारी स्कूल के बच्चों का फोटो कह कर न्यूयार्क टाइम्स और खलील टाइम्स में छपवाने की जरूरत क्यों पड़ी? केजरीवाल सरकार एक भी नया स्कूल और एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं खोल पायी? मनीष सिसौदिया पिछले विधान सभा चुनाव में हारते-हारते बचे थे और मात्र 1600 वोटों से जीते थे। भाजपा की रवि नेगी ने इन्हें पानी पिला दिया था। जब मनीष सिसौदिया इतने लोकप्रिय थे तब अपने क्षेत्र से विशाल समर्थन क्यों नहीं जुटा पाये थे, इनके सरकारी स्कूलों के कायाकल्प करने के कथित दावों से जनता क्यों नहीं चमत्कृत हुई थी?

केजरीवाल का झूठ और अनैतिकता किसे नहीं मालूम है। लोकपाल के नाम पर जनता को ठगा , अन्ना को ठगा। अरूण जेटली, नितिन गडकरी और विक्रम मजेठिया जैसे लोगों पर झूठे आरोप लगा कर माफी मांगे। इन्होंने दावा किया था कि शीला दीक्षित के खिलाफ चार सौ पेज की भ्रष्टचार कहानी उसके पास है। आज तक केजरीवाल शीला दीक्षित के चार सौ पेज की भ्रष्टचार की कहानी जनता को नहीं दिखा पाये। शीला दीक्षित परलोक भी चली गयी। ऐसे कई अन्य भी उदाहरण है। सिर्फ बिजली-पानी पर थोड़ी राहत देकर भ्रष्टचार करने और झूठ फैलाने का जन्मसिद्ध अधिकार केजरीवाल गिरोह ने मान लिया है। अब कानून का पाठ पढ़ना ही होगा मनीष सिसौदिया और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टचारी गिरोह को।

- आचार्य श्री विष्णुगुप्त

जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दी गई, जो आबकारी नियमों का उल्लंघन है।

लाइसेंस पाने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किया गया। इसके अलावा, तमाम तरह की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया।

उप-राज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मिली रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उप-राज्यपाल ने यह सिफारिश 22 जुलाई 2022 को ही की थी।

उप-राज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को आधार बनाया। इसके लिए उप-राज्यपाल ने मुख्य सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट को इसमें शामिल किया और इसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दी

मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापे

CBI ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आवास पर शुक्रवार (19 अगस्त 2022) को छापेमारी की। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में CBI ने घर का एक-एक कोना छान मारा। यहां तक कि सिसोदिया के कार की भी तलाशी ली गई।

इसके साथ ही सीबीआई ने सिसोदिया के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबरें आईं कि उनके घर पर आबकारी विभाग के कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए, जो उनके या किसी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे।

सीबीआई ने यह रेड देश के 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ की। जिन अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें दो पूर्व आबकारी अधिकारी भी हैं। ये दोनों ने IAS हैं और दिल्ली सरकार में आबकारी अधिकारी रह चुके हैं।

CBI की FIR में मनीष सिसोदिया पर आरोप

CBI ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है। इस एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं। इनमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का ही है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 9 कारोबारी, 3 आबकारी अधिकारी और दो कंपनियां हैं।

सीबीआई ने अपनी FIR में कहा है कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी को एक करोड़ रुपए का भुगतान किया था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं में आरोपित बनाया है। ■

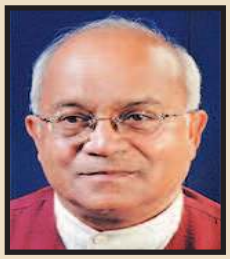

वेद प्रताप
वैदिक

रेवड़ियां बांटने की राजनीति

हिंदी की एक कहावत है कि 'अंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को देय।' अपने नेताओं ने अपने आचरण से इस कहावत को यों बदल दिया है कि 'अंधा बांटे रेवड़ी, सिर्फ खुद को ही देय।' सिर्फ खुद को फायदा करने के लिए ही आजकल हमारे सत्तारुढ़ दल सरकारी रेवड़ियां बांटते रहते हैं। आजकल देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां थोक वोट बटोरने के लालच में मतदाताओं को तरह-तरह की चीजें उपहार में बांटती रहती हैं। ये ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना भी करोड़ों लोग आराम से गुजर-बसर कर सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपनी महिला वोटरों को मुफ्त साड़ियां, सोने की चेन, बर्तन, मिक्स-ग्राइंडर और बच्चों को कंप्यूटर, पोषाख, भोजन आदि मुफ्त भेंट किए हैं। कई प्रदेश सरकारों ने मुफ्त साइकिलें भी भेंट में दी हैं। क्या ये सब चीजें जिंदा रहने के लिए बेहद जरुरी हैं? नहीं हैं, फिर भी इन्हें मुफ्त में इसीलिए बांटा जाता है कि सरकारों और नेताओं की छवि बनती है। इसका नतीजा क्या होता है? यह होता है कि हमारी प्रांतीय सरकारें गले-गले तक कर्ज में डूब जाती हैं। वे डूब जाएं तो डूब जाएं, मुफ्त रेवड़ियां बांटनेवाले नेता तो तिर जाते हैं। आजकल हमारी प्रांतीय सरकारें लगभग 15 लाख करोड़ रु. के कर्ज में डूबी हुई हैं। वे रेवड़ियां बांटने में एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए उतावली हो रही हैं। कुछ सरकारों ने तो अपने नागरिकों को बिजली और पानी मुफ्त में देने की घोषणा कर रखी है। महिलाओं के लिए बस-यात्रा मुफ्त कर दी गई है। इसका नतीजा यह है कि हमारी सरकारें देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में बहुत पिछड़ गई हैं। देश में गरीबी, बेरोजगारी, रोग और भुखमरी का बोलबाला है। इसी को लेकर आजकल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जमकर बहस चल रही है। एक याचिका में मांग की गई है कि उन राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिनकी सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय है कि यह तय करना न्यायालय नहीं, संसद का काम है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बना दी है, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने सुझाव देंगे। चुनाव आयोग ने इसका सदस्य बनने से इंकार कर दिया है, क्योंकि वह एक संवैधानिक संगठन है। सच्चाई तो यह है कि यह बहुत ही पेचीदा मामला है। सरकारें यदि राहत की राजनीति नहीं करेंगी तो उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यदि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकारें खाद्य-सामग्री नहीं बांटेंगी तो उनका रहना और न रहना एक बराबर ही हो जाएगा। इसी तरह महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को दिए गए मुफ्त अनाज को क्या कोई रिश्वत कह सकता है? वास्तव में भारत-जैसे विकासमान राष्ट्र में शिक्षा और चिकित्सा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जनता को जो भी राहत दी जाए, वह सराहनीय मानी जानी चाहिए लेकिन शेष सभी रेवड़ियों को परोसे जाने के पहले न्याय के तराजू पर तोला जाना चाहिए।

धनखड़ की जीत के अर्थ

जगदीप धनखड़ उप-राष्ट्रपति तो बन गए हैं लेकिन उनके चुनाव ने देश की भावी राजनीति के अस्पष्ट पहलुओं को भी स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहली बात तो यह कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है। उन्हें कुल 528 वोट मिले और मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट याने उन्हें लगभग ढाई-तीन गुने ज्यादा वोट! भाजपा के पास इतने सांसद तो दोनों सदनों में नहीं हैं। फिर कैसे मिले इतने वोट? जो वोट तृणमूल कांग्रेस के धनखड़ के खिलाफ पड़ने थे, वे नहीं पड़े। वे वोट तटस्थ रहे। इसका कोई कारण आज तक बताया नहीं गया। धनखड़ ने राज्यपाल के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी की जैसी खाट खड़ी की, वैसी किसी मुख्यमंत्री की क्या किसी राज्यपाल ने आज तक की है? इसी कारण भाजपा के विधायकों की संख्या बंगाल में 3 से 73 हो गई। इसके बावजूद ममता के सांसदों ने धनखड़ को हराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। इसका मुख्य कारण मुझे यह लगता है कि ममता कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थक के तौर पर बंगाल में दिखाई नहीं पड़ना चाहती थीं। इसका गहरा और दूरगामी अर्थ यह हुआ कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को ममता नेता की भूमिका नहीं देना चाहती हैं याने विपक्ष का भाजपा-विरोधी गठबंधन अब धराशायी हो गया है। कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भी धनखड़ का समर्थन किया है। हालांकि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का पद पार्टीमुक्त होता है लेकिन धनखड़ का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसे भाजपा के बाहर के सांसदों ने भी पसंद किया है, क्योंकि वी. पी. सिंह की सरकार में वे मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं और भाजपा में भी रहे हैं। उनके मित्रों का फैलाव कम्युनिस्ट पार्टियों और प्रांतीय पार्टियों में भी रहा है। वे एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर अपनी गुणवत्ता के बल पर देश के उच्चतम पदों तक पहुंचे हैं। ममता बेनर्जी के साथ उनकी खींच-तान काफी चर्चा का विषय बनी रही लेकिन वे स्वभाव से विनम्र और सर्वसमावेशी हैं। हमारी राज्यसभा को ऐसा ही सभापति आजकल चाहिए, क्योंकि उसमें विपक्ष का बहुमत है और उसके कारण इतना हंगामा होता रहता है कि या तो किसी भी विधेयक पर सांगोपांग बहस हो ही नहीं पाती है या फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। उप-राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद इस सत्र के अंतिम दो दिन की अध्यक्षता वे ही करेंगे। वे काफी अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं लेकिन अब वे अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए पक्ष और विपक्ष में सदन के अंदर और बाहर तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि भारत की राज्यसभा, जो कि उच्च सदन कहलाती है, वह अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन कर सके। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को अब शायद विपक्षी सांसदों को मुअत्तिल करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

क्या गहलोत को जनता का डर सताने लगा है?

● रामस्वरूप रावतसरे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के अंदर मेरा जादू परमानेंट है। मैं परमानेंट जादूगर हूं, मेरा जादू अपने आप चलता रहता है। मेरा जादू अलग तरह का जादू है, वो जादू देख लीजिए आप। लगातार सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, मेरा तो जिंदगी का मकसद है अंतिम सांस तक गरीब, असहाय की सेवा करना। जो गांधीजी ने कहा था उसमें सब आ जाते हैं। गहलोत जी का राजनीति में जादू चलता है यह सब देख रहे है लेकिन वही जादू अपराधों की रोक थाम के लिए नहीं चलता! आखिर क्या कारण हो सकता है। लेकिन वे खुश है, उनकी टीम के साथी खुश है। जो उन्हें यह बताते है कि उनके जादू की बदोलत ही प्रदेश में सब तरफ खुशहाली है। सब अपने अपने काम में लगे है। सभी विभागों में अपनी कार्यकुशलता के प्रति अत्यधिक चेतनता है। श्रेष्ठ सुशासन के कारण उनकी बढती लोकप्रियता से घर और बाहर के विरोधियों की गर्दनें झुकी हुई है। उनके जादू का ही प्रभाव है कि दिल्ली दरबार में यदाकदा कड़कने वाली बिजलियां एक बार मिलने भर से सब शांत हो जाती है। जैसे कि अब तक होता आया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गरीब चाहे ब्राह्मण-वैश्य ही क्यों न हो, मैं गरीब के साथ खड़ा हूं। उससे संतोष मिलता है। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मैं गरीबों के लिए खड़ा रहता हूं। मेरा रास्ता था, मैंने दोनों टर्म में शानदार गवर्नेंस दी, एक से बढ़कर एक स्कीम दी हैं। इस बार जनता कृपा करे हम पर, सरकार रिपीट करवाए। हम कई योजनाएं लेकर आए। गरीबों के लिए काम करने पर संतोष मिलता है, अच्छा लगता है, बाकी जनता चुनाव हरवा देती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस बार मैं चाहता हूं जनता हमें वापस जिताए, सरकार रिपीट करवाए। इतने हमने काम किए हैं, हर परिवार में हमारी कोई न कोई स्कीम पहुंच गई है। मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई, यह कम बात है क्या? नहीं है। पब्लिक से आह्वान करूंगा कि इस बार कृपा करो हम पर। सरकार बदलती है तो हमारी स्कीम्स बंद हो जाती हैं। वैसे एक बात जो बार बार गहलोत जी के मुहं से निकल जाती है, वह यह कि वे आजीवन सत्ता में रह कर जनता की सेवा करना चाहते है। अब उनके विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कैसे राजनीति की जाती है! किसके लिए की जाती है! समस्या का समाधान किये बिना ही समस्या को समाप्त कर देने में उनका लम्बा अनुभव है। इस अनुभव के चलते ही सचिन पायलट तो क्या कई दिग्गजों को आज तक किनारे पर ही रखा है।

वैसे राजनीति का एक पृष्ठ ऐसा भी होता है जिसमें लिखा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन पढने में किसी के भी नहीं आता। सभी को लगता है कि इसमें जो भी लिखा है। उनके हित को ध्यान में लेकर ही लिखा गया है। लेकिन होता इसके उल्टा है। जनता के सामने हाथ मिलाना, गले मिलना, मंच सांझा करना सुलझी और अनुभवी राजनीति का ही एक पार्ट होता है। लेकिन प्रतिद्वन्दी के बढते पैरों में कब किस प्रकार की जकड़न देनी है। इसका आभास कभी नहीं होने देते। खैर प्रजातंत्र में एक बार जो सत्ता का सुख भोग लेता है। वह जब तक उसकी चलती है दूसरे को आगे नहीं आने देता। पहले जैसे राजाओं के मंत्री संतरी, कामदार, पहरेदार होते थे, आज भी है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। एक विधायक या सांसद (जो अपने आपको जनता का सेवक कहाते है) इनसे मिलने के लिए इन्हीं सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मुख्यमंत्री या मंत्री से मिलने के लिए तो ओर भी लम्बी प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल बना हुआ है। इस जन सेवामें बिना कुछ खर्च किये सब कुछ मिलता है। कौन नहीं तैयार होगा!

राजस्थान में बढ रही आपराधिक घटनाओं तथा लचर कानून व्यवस्था को लेकर जैसे ही प्रदेश भाजपा कुछ मुखर हुई । वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज को भाजपा के साथ जोड़ते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के ट्रकों में दो नंबर का पैसा भरकर भाजपा के कार्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है। अशोक गहलोत का सार्वजनिक रूप से ऐसा आरोप लगाने के पीछे कुछ तो कारण होगा। वे किस लाईन को बड़ा करना चाहते है।

इधर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के साढ़े 3 साल के शासन में अब तक 7 लाख, 97 हजार 693 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 6 हजार 325 हत्याएं हो चुकी हैं। 5 हजार से ज्यादा लूट हो चुकी हैं। चोरी की वारदात 1 लाख 29 हजार 489 हो चुकी हैं। महिलाओं पर अत्याचार के मामले 1 लाख 45 हजार 288 दर्ज हो चुके हैं। बच्चियों, महिलाओं पर रेप और गैंगरेप संबंधी 22 हजार 148 दर्ज हो चुके हैं। 26 हजार 794 मामले एससी से संबंधित मामले दर्ज हुए। 7 हजार 374 मामले एसटी संबंधी दर्ज हुए हैं। साल 2020 के मुकाबले 2022 में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी, नकबजनी में बढ़ोतरी हुई है। चोरी के मामलों में 21.53 प्रतिशत, लूट 28.57 प्रतिशत, बलात्कार 19.34 प्रतिशत और महिला अत्याचार में 18.75 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

भाजपा के अनुसार इसलिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार फैल है। पूनियां जी को मालूम होना चाहिए ये सरकारी आंकड़े है जिसे सम्बन्धित विभाग द्वारा समय समय पर जारी किया गया है, ताकि सरकार में उनकी भी उपस्थिति और उपलब्धि का ऐहसास होता रहे। वे भी तो सरकार से वेतन पाते है। विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर उन्हीं के विभाग द्वारा जारी किये गये आंकड़ों को लेकर हमला करना कोई महत्व नहीं रखता है। वैसे भी किसी थाना क्षेत्र में अपराध की घटना होने से ही उसका महत्व है। न्यायालय हो और कोई मुकदमा नहीं हो ये कैसे सम्भव है।

अशोक गहलोत के सामने अब तक कई प्रकार के राजीतिक संकट आये लेकिन वे अडिग रहे। संकट खड़ा करने वाले ही संकटग्रस्त हो गये। उनकी गांधीगिरी ने कई दिग्गजों को धराशाही किया लेकिन जनता में ना तो उनकी गांधीगिरी काम आई और ना ही राजनीति का लम्बा अनुभव। इसीलिए तो वे कह रहे है कि जनता को भी उनके जादू का चमत्कार समझना चाहिए। गहलोत ने जनकल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। पहले के कार्यकालों में कोई कमी नहीं रहने दी थी। जानकार लोगों का कहना है कि आंकठ भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के चलते सुविधाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सब कुछ करने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। इस पर विचार होना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है, इस बार पुन: सत्ता में आने के लिए अशोक गहलोत का जादू जनता को रिझाने के काम आ जाये। ■

भाषा किसी देश की सांस्कृतिक समृद्धि की सूचक होती है

● डॉ कामिनी वर्मा

वैचारिक संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। धरती पर जब से मनुष्य का अस्तित्व है तभी से वह भाषा का प्रयोग कर रहा है। ध्वनि एवं संकेत दोनों रूपों में वैचारिक आदान-प्रदान होता रहा है। भारत भाषा और बोलियों की दृष्टि से समृद्ध देश है। भारत के लिए कहा जाता है कि

कोस कोस पर बदले पानी
चार कोस पर वाणी

यहां अनगिनत भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। वर्तमान में लगभग 780 भाषाएं व 2000 बोलियां प्रचलित है। भाषा और बोली देश की सांस्कृतिक समृद्धि की सूचक होती है । परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जैसे जैसे जीवन परिवर्तित होता है वैसे वैसे सांस्कृतिक मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। मनुष्य का जीवन स्तर, आचार-विचार, रहन-सहन में बदलाव का प्रभाव भाषा व बोली पर भी पड़ता है। पिछले 50 वर्षों में भारत में 220 भाषाएं प्रचलन से बाहर हो गईं और आगे आने वाले 50 वर्षों में 150 भाषाएं समाप्त होने के कगार पर हैं।

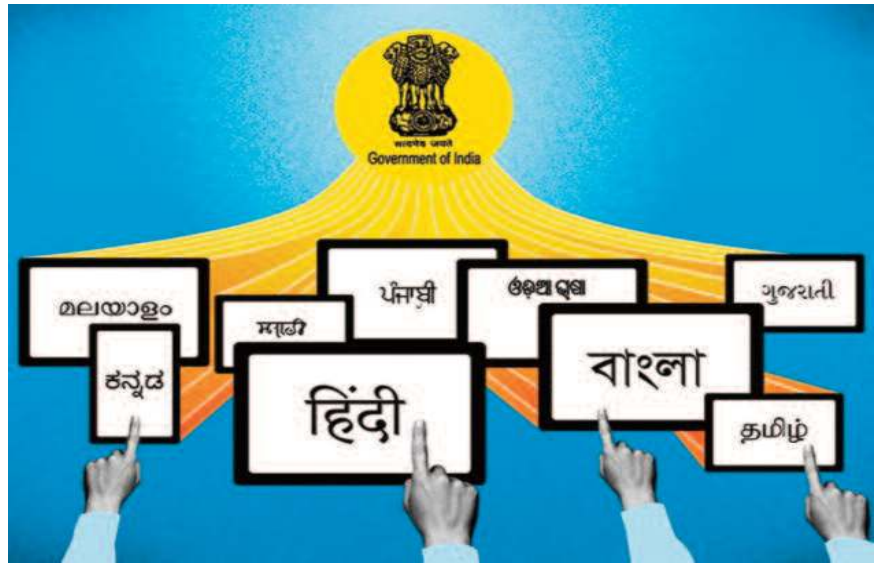

प्रोफेसर डॉ कामिनी वर्मा 'शिक्षक शिरोमणि अवार्ड' से सम्मानित

दिनांक 19 अगस्त 2022 को अभ्युदय वात्सल्यम् संस्था देहरादून द्वारा काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही की इतिहास विभाग की अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ कामिनी वर्मा को अखिल भारतीय नवाचार समागम-2022 कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम , टाउन हॉल, देहरादून के सभागार में 'शिक्षक शिरोमणि अवार्ड' से सम्मानित किया गया। लखनऊ निवासी डॉ कामिनी वर्मा वर्तमान में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में प्रोफेसर इतिहास पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी योगदान दे चुकी है। डॉक्टर वर्मा ख्याति लब्ध सामाजिक चिंतक एवं स्तंभकार है। समसामयिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर आपके स्तंभ जम्मू कश्मीर, नेपाल , कनाडा सहित संपूर्ण भारत में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने पांच पुस्तकों का संपादन किया है। 21 पुस्तकों तथा शोध ग्रंथों में आपके शोध पत्र तथा 20 पत्रिकाओं में समसामयिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आप कैदियों के पुनर्वास एवं कौशल विकास की 21 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जनपद ज्ञानपुर में कर चुकी है । आप राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम तथा नोडल अधिकारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य के रूप में कौमी एकता, पर्यावरण, महिला मतदाता जागरूकता, एड्स निवारण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अभियान चलाती रहती हैं। वर्तमान में मिशन शक्ति एवं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित कर रही है। आपके योगदान को देखते हुए आपको भारतीय शिक्षा रत्न अवॉर्ड, एशिया पेसिफिक इंटरनेशनल गोल्ड अवॉर्ड फॉर टैलेंटेड पर्सन, बेस्ट एजुकेशनिस्ट, राधाकृष्णन, बागेश्वरी नारी शक्ति सम्मान, राष्ट्रीय स्वर्णिम हिंद अवार्ड, दुर्गा शक्ति अवार्ड, सारस्वत सम्मान, इंडियाज बेस्टीज अवॉर्ड तथा हिंदी साहित्य सृजक तथा समता सैनिक दल द्वारा डा अंबेडकर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।

भाषा का राष्ट्र की एकता, अखंडता व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रभाषा देश को भावनात्मक व सांस्कृतिक रूप से संगठित करने में सहायक होती है। प्राचीन काल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर सौराष्ट्र तक समस्त सांस्कृतिक तथा धार्मिक चर्चा व वैचारिक आदान-प्रदान संस्कृत भाषा में होता था।

विदेशी आक्रमण व अपनी क्लिष्टता के कारण इसका महत्व न्यून हुआ और हिंदी वैचारिक अभिव्यक्ति की भाषा बनी। इसका सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता, अखंडता व सांस्कृतिक समृद्धि में अमूल्य योगदान है। यह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है।

यह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है। न सिर्फ हिन्दू बल्कि मुस्लिम साहित्यकारों, मालिक मुहम्मद जायसी, रसखान, ताज, रहीम ने भी।

इसके संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है। हिंदी के विषय मे अमीर खुसरो जो 'तूतिये हिन्द' के नाम से भी विख्यात है , कहते हैं 'चूं मत तती हिदं अर रास्त पुरसी, जे मन हिन्दवी पुरस ता

नग्ज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की 'तूती' हूं।'

'अगर मुझसे सच पूछते हो तो हिंदी में पूछो जिससे मैं कहीं' अच्छी बातें बता सकूं'

वास्तविकता भी यही है अपनी मूल भाषा में ही बेहतर वैचारिक सम्प्रेषण सम्भव है । हिंदी भाषा पढ़ने, लिखने व बोलने में सहज व सरल है तथा कविता , कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । यह उदार भाषा है जिसने अन्य भाषाओं के अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को उनके मूल रूप में ही आत्मसात कर लिया। देश में 65 प्रतिशत हिंदी भाषी जनसंख्या है, लगभग हर प्रान्त के लोग हिंदी जानते व समझते हैं। अन्य भाषाओं के समान हिंदी का भी विज्ञान है।

किंतु आज अपने ही देश मे हिंदी उपेक्षित व पिछड़ेपन का दंश सहन कर रही है। औपनिवेशिक काल मे ब्रिटिश सत्ता ने देश को राजनैतिक रूप को गुलाम बनाने के साथ साथ यहां की संस्कृति पर भी प्रहार किया। उनकी भाषा अंग्रेजी थी अत: व्यापारिक, राजनीतिक व व्यवहारिक कार्यों के लिए उन्होंने रंग व रक्त से भारतीय परन्तु सोच, रुचि, नैतिकता व बुद्धि से अंग्रेज परस्त वर्ग तैयार किया। थोड़ी सी अंग्रेजी जानने वाले को नौकरी व अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान की। यहीं से हिंदी के दुर्दिन प्रारम्भ हो गए। ■

चीन में मंदी की आहट

● जयप्रकाश रंजन

भारत ने सिर्फ पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सेना की गतिविधियों पर ही पैनी नजर नहीं बना कर रखी हुई है बल्कि हाल के महीनों मे चीन के इकोनोमी में गिरावट व कमजोरी के जो लक्षण दिखाई देने शुरू हुए हैं, उसकी भी करीबी निगरानी हो रही है। वजह यह है कि दोनो देशों के बीच सैन्य व कूटनीतिक तनाव के बावजूद आर्थिक रिश्तें लगातार मजबूत हो रहे हैं।

वर्ष 2022 के पहले छह महीने के द्विपक्षीय कारोबार आंकड़ों का संकेत यह है कि लगातार दूसरे वर्ष चीन और भारत का द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर को पार करेगा। चीन वैश्विक सप्लाई चेन के लिए अभी भी काफी महत्वपूर्ण है और उसकी इकोनोमी में कमजोरी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

यही वजह है कि सिर्फ वित्त मंत्रालय के अधिकारी ही नहीं बल्कि आरबीआइ भी चीन सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर सतर्क है और वहां की हर आर्थिक गतिविधि की भारतीय संदर्भ में समीक्षा हो रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक चीन की इकोनोमी से काफी अलग-अलग तरह के संकेत आ रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। तो वहां ब्याज दरों में 10 आधार अंकों की कमी की गई है। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरी दुनिया में बेहद सरल नियम बनाये जा रहे हैं। ताकि आर्थिक गतिविधियों पर असर नहीं हो, लेकिन वहां के कई बड़े औद्योगिक शहरों में अभी भी कई तरह के अवरोध लागू हैं।

चीन की दुनिया की इकोनोमी में काफी हिस्सेदारी है जिसे कम होने में समय लगेगा। अभी चीन की अर्थव्यवस्था नीचे आती है तो पूरी दुनिया की इकोनोमी पर इसका असर होगा। भारत के लिए भी चीन एक बहुत ही बड़ा आर्थिक साझेदार देश हैं।

दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का असर द्विपक्षीय कारोबार पर नहीं पड़ा

चीन की भारतीय इकोनोमी में अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मई, 2020 से दोनो देशों के बीच चल रहे सैन्य तनाव का भी असर द्विपक्षीय कारोबार पर नहीं पड़ा है। जुलाई, 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि जनवरी-जून, 2022 के दौरान इनका द्विपक्षीय कारोबार 67.08 अरब डॉलर का था। इस दौरान चीन से भारत को होने वाले निर्यात में 34.5 फीसद का इजाफा (57.51 अरब डॉलर) हुआ है, जबकि भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 35.3 फीसद की गिरावट (9.57 अरब डॉलर) हुई है। वर्ष 2021 में द्विपक्षीय कारोबार 125 अरब डॉलर का रहा था।

इस बढ़ते निर्यात का सीधा संबंध भारत के बढ़ते निर्यात से है। भारत के रसायन उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल काफी हद तक चीन से ही आते हैं। ऐसे में वहां की मंदी का असर भारत के उद्योगों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

अधिकारियों का कहना है कि नजर रखने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि चीन की इकोनोमी में गिरावट भारत के लिए कई नई संभावनाएं भी पैदा कर सकती हैं।

वर्ष 2022 में चीन की आर्थिक विकास दर 3.3 फीसद रहने का अनुमान

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2022 में चीन की आर्थिक विकास दर 3.3 फीसद रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले 40 वर्षों की न्यूनतम दर है। जबकि इस वर्ष भारत की विकास दर 7.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।

क्या हो रहा है चीन में

- पूरी दुनिया में कर्ज हुआ महंगा, चीन ने

किया सस्ता
- कई बड़े औद्योगिक शहरों में अभी भी काम काज सामान्य नहीं
- रीयल एस्टेट क्षेत्र में भारी मंदी, कई कंपनियों के दिवालिया होने की खबर
- चीन के कई बैंकों के पास फंड की कमी, ग्राहकों को नहीं दी जा रही जमा राशि

बीजिंग की इकोनॉमी में हुए ये दो बड़े सुराख

2008 के यूएस हाउसिंग बबल के फटने से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई थी। 14 साल बाद वैसे ही हालात चीन में बन रहे हैं। बीजिंग का रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। वहीं महंगाई के चलते (चीन में यह समस्या भी है) वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल है। आइये समझते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में ये सुराख हो कैसे रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट में बढ़ती महंगाई को थामने के लिए दुनियाभर के देश अपने केंद्रीय बैंकों के जरिये ब्याज दरों में वृद्धि करा रहे हैं। इससे महंगाई तो थोड़ी बहुत काबू में आ जाएगी लेकिन विकास दर सुस्त होने की वजह से मंदी का जोखिम बढ़ रहा है।

चीन में मंदी के कारण

ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का जोखिम कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। चीन और जापान पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक तो महंगाई के चलते चीन में दिक्कत बढ़ रही है। वहीं चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में नकदी की भारी कमी है।

इस संकट के कारण ही एशिया की सबसे अमीर महिला यांग हुयान ने पिछले एक साल में अपनी आधी से अधिक संपत्ति खो दी है।

कितना बड़ा है चीन का रियल एस्टेट

रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योग 17.5 ट्रिलियन डॉलर की चीनी जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा हैं। इसलिए इस सेक्टर में आया नकदी का संकट बड़ा हो गया है। कुछ विशेषज्ञ चीन की इस स्थिति की तुलना यूएस हाउसिंग बबल के फटने से कर रहे हैं। इसके चलते ही 2008 का वित्तीय संकट आया था और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी।

इस बार वैश्विक स्तर पर कहां है गड़बड़

ग्लोबल मार्केट में बढ़ती महंगाई को थामने के लिए दुनियाभर के देश अपने केंद्रीय बैंकों के जरिये ब्याज दरों में वृद्धि करा रहे हैं। इससे महंगाई तो थोड़ी बहुत काबू में आ जाएगी लेकिन विकास दर सुस्त होने की वजह से मंदी का जोखिम बढ़ रहा है।

अच्छे दिनों में लिया लोन, अब चुका नहीं पा रहे

रियल एस्टेट के इस नकदी संकट के चलते ही चीन में कई स्थानीय बैंकों ने पैसों की निकासी को फ्रीज कर दिया है। चीन की रियल एस्टेट कंपनियों ने बूम के वर्षों में बड़ी परियोजनाओं पर भारी मात्रा में उधार लिया था। बैंक पहले से ही कोरोना महामारी से पैदा हुई आर्थिक मंदी और बिल्डर्स द्वारा लोन डिफॉल्ट कर जाने से संकट में हैं। करीब चार लाख ग्राहक इन बैंकों में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं।

बैंकों के बाहर क्यों तैनात हुए टैंक

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ग्राहकों के पैसे निकालने पर लगी रोक के कारण कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। सरकार को बैंकों के बाहर टैंक तैनात करने पड़े हैं। वहीं बैंकों का कहना है कि सिस्टम अपग्रेडेशन के चलते वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं।

विकास दर भी घट रही

एशिया डेवलेपमेंट बैंक के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था के 2022 में 4.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पहले 5.1 फीसद का पूर्वानुमान दिया था। वहीं दूसरी तिमाही में चीन ने सालाना आधार पर केवल 0.4% की वृद्धि दर्ज की, जो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से सबसे कम है। ■

ताइवान पर अमेरिका और चीन में क्या हो सकता है युद्ध ?

ताइवान की राजधानी ताइपे के लिए सोमवार का ये दिन बाकी दिनों से अलग था। दोपहर के वक्त सालाना 'एयर रेड ड्रिल' शुरू हो गई। इस ड्रिल का उद्देश्य ताइवान के लोगों को चीन के संभावित हमले के लिए तैयार करना होता है।

ताइवान का पड़ोसी चीन दुनिया में 'सुपरपावर' की हैसियत रखता है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चीन नाराज है और यहां तनाव चरम पर है।

इस बीच, अमेरिका ने ताइवान के करीब चीन की सैन्य गतिविधि को 'उकसावे वाली कार्रवाई' बताया है और आरोप लगाया है कि इससे क्षेत्र में खतरे की स्थिति बन रही है

दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो 'आग से नहीं खेले।'

बढ़ते तनाव के बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में युद्ध छिड़ सकता है?

अधूरा अभियान

महाशक्तियों के बीच संघर्ष में ताइवान इतना अहम क्यों हो गया है, ये समझने के लिए हमें करीब 70 साल पीछे जाना होगा।

उस वक्त चीन में गृह युद्ध छिड़ा था। एक तरफ माओत्से तुंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट थे। दूसरी तरफ च्यांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी ताकतें थीं।

साल 1949 आते आते राष्ट्रवादी बुरी तरह पराजित होने लगे। तब च्यांग काई शेक को तय करना था कि वो अपनी सेना को कहां ले जाएं।

वाशिंटगन स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े और ताइवान के इतिहास के जानकार जेम्स लिन बताते हैं, 'वो एक ऐसे इलाके में चले जाना चाहते थे जहां फिर से ताकत बटोर सकें। एक ऐसी जगह जहां वो फिर से खड़े हो सकें और जो बड़ा इलाका उन्होंने गंवा दिया है, उसे फिर से हासिल कर सकें।'

वो बताते हैं कि उस वक्त च्यांग काई शेक के पास सीमित विकल्प थे।

जेम्स लिन के मुताबिक, ' वो सोचते थे कि कम्युनिस्ट राष्ट्र से सुरक्षा के हिसाब से ताइवान की क्षमता शायद सबसे अच्छी है। कम्युनिस्टों के पास सेना को ताइवान ले जाने के लिए संसाधन नहीं थे। इसीलिए काई शेक ताइवान गए। निर्वासन में रहते हुए उन्होंने वहां सरकार गठित की। कम्युनिस्ट अब तक ताइवान को अपने अधिकार में नहीं ले पाए हैं।'

चीन के लिए ताइवान हमेशा से ऐसा अभियान रहा, जो पूरा नहीं हो पाया है। शुरुआती दिनों में यहां की पूंजीवादी सरकार ने ताइवान के 'असली चीन' होने का दावा किया। अमेरिका ने पूरी मजबूती से ताइवान का समर्थन किया और इसे 'आजाद चीन' बताया।

लेकिन हकीकत में ये उस तरह आजाद नहीं था। चेंग काई शेक किसी तानाशाह की तरह थे। उन्होंने 'मार्शल लॉ' लागू किया था।

जेम्स लिन बताते हैं, 'अमेरिका का ताइवान को समर्थन इसके लोकतांत्रिक होने को लेकर नहीं था। समर्थन की वजह थी चीन के करीब इसकी रणनीतिक स्थिति। तब से ताइवान अमेरिकी विदेश नीति का बेशकीमती साझेदार बन गया।'

ताइवान में लोकतंत्र चार दशक बाद आया। 1990 के दशक से यहां राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। तब से ताइवान में ऐसे लोगों की संख्या लगातार घट रही है जो खुद को चीनी बताते हैं। हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ तीन प्रतिशत है।

जेम्स लिन कहते हैं, '1990 के दशक से ताइवान की अलग पहचान उभरने लगी। बीजिंग को ये बात खतरे की तरह लगती है। ये अब अनसुलझे गृह युद्ध की बात नहीं रह गई। ताइवान के लोग अपनी पहचान चीन से अलग देखने लगे हैं। चीन इसे अलगाववाद की तरह देखता है।'

लेकिन ताइवान के लिए उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैचारिक स्थिति एक त्रासदी बन गई है। वहां के लोग जो सोचते हैं, वैसा हाल फिलहाल होना मुश्किल है।

ईस्ट चाइना सी स्थित ये द्वीप अमेरिका और चीन दोनों के लिए बहुत अहम है।

रणनीति

साल 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। जापान का हमला अमेरिका के लिए बड़े झटके की तरह था। तब तक अमेरिकी मानते थे कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर

उन्हें विदेशी हमलों से बचाते रहेंगे।

फिर अमेरिका को लगा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए और उपाय करने होंगे। चीन और सोवियत समर्थन वाली कम्युनिस्ट सरकारों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में द्वीपों की पहली चेन तैयार की। ताइवान इस चेन की अहम कड़ी बना हुआ है।

लंदन स्थित थिंक टैंक 'चैटम हाउस' की सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर यू जे बताती हैं, 'साल 1954 में पहली बार ठोस भरोसा दिया गया कि अगर मेनलैंड चीन की ओर से ताइवान पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका उसे सैन्य मदद मुहैया कराएगा।'

वो बताती हैं कि दूसरा कदम था 1979 का 'ताइवान एक्ट'। इसके मुताबिक अगर बीजिंग एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश करता है तो अमेरिका सैन्य सहायता देगा।

डॉक्टर यू जे ये भी कहती हैं कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के संबंधों में दो धारा हैं। इनमें 'ताइवान रिलेशन्स एक्ट' के साथ 'स्ट्रैटजिक एम्बीग्यूटी' यानी 'रणनीतिक पेंच' वाली नीति भी है।

इनके सिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के फैसले से जाकर जुड़ते हैं। साल 1972 में निक्सन ने चीन के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। 'शंघाई घोषणापत्र' तभी सामने आया। इसी ने 'वन चाइना पॉलिसी' स्थापित की।

इसके मुताबिक अमेरिका ये मानता है कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ चीनी हैं। वो ये भी मानता है कि चीन एक है और ताइवान चीन का हिस्सा है।

ये नीति अमल में आई और ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सीट गंवा दी। 1970 के दशक के आखिर तक अमेरिका के चीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गए।

अमेरिका हमेशा कहता रहा है कि ये नीति सिर्फ़ बीजिंग के ताइवान पर दावे को मानती है, लेकिन इसे मंजूरी या मान्यता नहीं देती।

चीन 'वन चाइना सिद्धांत' की बात करना पसंद करता है। जो ताइवान को चीन का हिस्सा बताता है और यहां एक शब्द भर से पूरी दुनिया बदल जाती है।

डॉक्टर यू जे कहती हैं, 'वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि अमेरिका बीजिंग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वैध सरकार मानता है। 'वन चाइना प्रिंसिपल' का मतलब है कि अमेरिका को ये मान्यता देनी चाहिए कि सिर्फ़ बीजिंग की सरकार ही संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती सरकार है।'

ताइवान को भरोसा देने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1979 में 'ताइवान रिलेशन्स एक्ट' पर हस्ताक्षर किए। इसमें ताइवान को हथियार बेचने का वादा किया गया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके।

ताइवान के ख़िलाफ बल प्रयोग या जोर जबरदस्ती को लेकर भी इसमें चेतावनी दी गई है। लेकिन इसमें ये साफ नहीं है कि अगर चीन ने हमला किया तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा?

तब से अमेरिका की जो आधिकारिक नीति रही है, उसमें ये एक अहम 'रणनीतिक पेंच' है।

डॉक्टर यू जे कहती हैं, '40 साल पीछे जाएं तो इस एक्ट के जरिए मकसद पूरा हुआ लेकिन मुझे लगता है कि अब चीन उभार पर है। जो किसी हद तक अमेरिका के दबदबे को चुनौती देता है और अमेरिका को लगता है कि शायद ताइवान के मुद्दे को अब ज़्यादा देर तक परे नहीं रखा जा सकता। इसे लेकर और ज़्यादा स्पष्टता लाने की जरूरत है।'

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ताइवान के मुद्दे पर कई बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सिहरन की स्थिति पैदा कर चुके हैं।

हाल में जो बाइडन के जापान के दौरे के दौरान ऐसा देखने को मिला था। ■

चीन और भारत की नोंक-झोंक

आजकल भारत और चीन के बीच काफी नरम-गरम नोंक-झोंक चलती नजर आती है। गलवान घाटी विवाद ने तो तूल पकड़ा ही था लेकिन उसके बावजूद पिछले दो साल में भारत-चीन व्यापार में अपूर्व वृद्धि हुई है। भारत-चीन वायुसेवा आजकल बंद है लेकिन इसी हफ्ते भारतीय व्यापारियों का विशेष जहाज चीन पहुंचा है। गलवान घाटी विवाद से जन्मी कटुता के बावजूद दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बार-बार बैठकर आपसी संवाद कर रहे हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारतीय और चीनी विदेश मंत्री भी आपस में मिले हैं। इसी का नतीजा है कि विदेशी मामलों पर काफी खुलकर बोलनेवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के विरुद्ध लगभग मौन दिखाई पड़ते रहे। यही बात हमने तब देखी, जब अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान-यात्रा पर जबर्दस्त हंगामा हुआ। पेलोसी की ताइवान-यात्रा के समर्थन या विरोध में हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की चुप्पी आश्चर्यजनक थी लेकिन यह चुप्पी अब टूटी है। क्यों टूटी है? क्योंकि चीन ने इधर दो बड़े गलत काम किए हैं। एक तो उसने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल रउफ अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध कर दिया है और दूसरा उसने श्रीलंका के हंबनतोता बंदरगाह पर अपना जासूसी जहाज ठहराने की घोषणा कर दी थी। ये दोनों चीनी कदम शुद्ध भारतविरोधी हैं। अजहर को अमेरिका और भारत, दोनों ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने का यह दुष्कर्म पहली बार नहीं किया है। लगभग दो माह पहले उसने लश्करे-तय्यबा के अब्दुल रहमान मक्की के नाम पर भी रोक लगवा दी थी। इसी प्रकार जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद को आतंकवादी घोषित करने के मार्ग में भी चीन ने चार बार अड़ंगा लगाया था। अब्दुल रउफ अजहर पर आरोप है कि उसने 1998 में भारतीय जहाज के अपहरण, 2001 में भारतीय संसद पर हमले, 2014 में कठुआ के सैन्य-शिविर पर आक्रमण और 2016 में पठानकोट के वायुसेना पर हमले आयोजित किए थे। चीन इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है लेकिन उसने अपने लाखों उइगर मुसलमानों को यातना-शिविरों में झोंक रहा है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी उन्हें भी उकसाने में लगे रहते हैं। यह मैंने स्वयं चीन के शिन-च्यांग प्रांत में जाकर देखा है। इसीलिए इस चीनी कदम की भारतीय आलोचना सटीक है। जहां तक ताइवान का प्रश्न है, भारत की ओर से की गई नरम आलोचना भी समयानुकूल है। वह चीन-अमेरिका विवाद में खुद को किसी भी तरफ क्यों फिसलने दे?

डॉ वेदप्रताप वैदिक
(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

यूरोप में 500 साल का सबसे बड़ा सूखा

● ब्यूरो रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। खासकर यूरोप में अब इसका सबसे बुरा प्रभाव दिख रहा है। यह पूरा महाद्वीप 500 साल के अपने सबसे बुरे सूखे की तरफ बढ़ रहा है। यहां तक कि आमतौर पर बारिश से भीगा रहने वाला इंग्लैंड तक सूखे से गुजर रहा है। यहां सरकार ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर सूखे से गुजरने का एलान किया। इससे पहले फ्रांस और स्पेन के नेताओं ने भी कहा कि उनका देश अब तक की सबसे खतरनाक सूखे की स्थिति से गुजर रहा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो यूरोप में पिछले दो महीने से खास बारिश नहीं हुई, जिसके कारण आगे भी स्थिति के सुधरने की कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं अमेरिका के कई राज्य भी पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इनमें कैलिफोर्निया से लेकर हवाई जैसे राज्य भी शामिल हैं। इस बीच अमर उजाला आपको बता रहा है कि यूरोप में इस बार का सूखा कितना गंभीर है? कौन से देशों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव है? पिछले दशकों के मुकाबले इस दशक में सूखे की स्थिति क्या है? इसके अलावा कौन से देशों और उद्योगों को इसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है?

यूरोप में कहां-कहां पड़ा सबसे खराब सूखा?

1. पीने के पानी की कमी कहां?

वैसे तो लगभग पूरे यूरोप में ही स्थिति काफी खराब है। लेकिन फ्रांस और स्पेन में बारिश की कमी और जंगलों में लगी आग की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं ब्रिटेन में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले महीने ही इंग्लैंड में इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान (जबसे तापमान दर्ज करना शुरू किया गया) रिकॉर्ड किया गया था। इसके चलते यहां लोगों के पास पीने के पानी तक की कमी पैदा हो गई है।

यूरोपियन कमीशन (ईसी) के जॉइंट रिसर्च सेंटर ने पिछले हफ्ते एलान किया है कि यूरोपीय संघ का लगभग आधा क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम का पूरा भूमिगत क्षेत्र सूखे की चपेट में है। इस साल की शुरुआत से ही यूरोप में सूखे की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसके बाद सर्दियों और वसंत के मौसम में पूरे महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल में पानी की करीब 19 फीसदी कमी देखी गई। बीते 30 वर्षों में यह पांचवां मौका है, जब यूरोप में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा महाद्वीप तेज गर्मी और लू जैसी स्थितियों ने बारिश में कमी के असर को दोगुना कर दिया। मौजूदा समय में यूरोप का 10 फीसदी हिस्सा हाई अलर्ट पर है।

2. पेड़-पौधों का अस्तित्व कहां खतरे में?

यूरोप के जिन हिस्सों पर सूखे का सबसे बुरा असर देखा जा रहा है, उनमें मध्य और दक्षिण यूरोप शामिल हैं। यहां बारिश की कमी की वजह से जमीन में पानी भी काफी निचले स्तर पर चला गया है। आलम यह है कि पेड़-पौधे भी जमीन से पानी नहीं ले पा रहे और इनका सूखना जारी है। मध्य जर्मनी, पूर्वी हंगरी, इटली के निचले इलाके, दक्षिण-केंद्रीय और पश्चिमी फ्रांस, पुर्तगाल और उत्तरी स्पेन में तो कई पेड़-पौधों के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो गया है।

3. जलस्रोत?

इटली का पो नदी घाटी, जिसे देश के लिए सबसे अहम पानी का स्रोत माना जाता है, बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते पांच क्षेत्रों में सूखे का आपात घोषित किया गया और लोगों के पानी के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी तरह के कुछ कदम फ्रांस में भी उठाए गए हैं। उधर स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप के जल भंडार भी 10 साल के औसत से 31 फीसदी निचले स्तर पर हैं।

4. बिजली की कमी?

ब्रिटेन और यूरोप के जलस्रोतों में पानी की कमी का असर अब इन देशों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो अक्षय स्रोतों से बिजली पैदा करने पर निर्भर कई यूरोपीय देशों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। हाइड्रोपावर क्षेत्र में इस वक्त ऊर्जा उत्पादन 20 फीसदी तक नीचे गिरा है। उधर

सूखे की चपेट में आने से चीन ने महसूस की गर्मी, लू ने नदियों को सुखाया

चीनी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय सूखे की चेतावनी दी है। अलर्ट का उद्देश्य फसलों को भीषण तापमान से बचाने के लिए विशेषज्ञ टीमों को जुटाना है। चीन इस समय 1961 के बाद से सबसे भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है।

जैसा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के लगभग हर देश पर एक बड़ी चुनौती बना रहा है, चीन अलग नहीं है। चीनी सरकार ने पहली बार जंगल की आग के रूप में वर्ष के राष्ट्रीय सूखे की चेतावनी दी है, और गर्मी की लहरें देश को सूखा छोड़ देती हैं।

राष्ट्रीय सूखा चेतावनी का उद्देश्य यांग्त्जी नदी बेसिन में फसलों को चिलचिलाती तापमान से बचाने के लिए विशेषज्ञ टीमों को जुटाना है। दक्षिण-पश्चिम में सिचुआन से लेकर यांग्त्जी डेल्टा में शंघाई तक के क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी का अनुभव होने के बाद अलर्ट आया है, सरकारी अधिकारियों ने बार-बार वैश्विक जलवायु परिवर्तन का कारण बताया है।

चीन, इस समय, 1961 के बाद से सबसे मजबूत हीटवेव से गुजर रहा है, जो 13 जून से शुरू हुआ और दो महीने से अधिक समय तक चला। सीजीटीएन के अनुसार, 262 मौसम केंद्रों ने अत्यधिक उच्च तापमान दर्ज किया है, जो 2013 में 187 स्टेशनों से अधिक था। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (एनएमसी) ने उच्च तापमान के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जो इसकी चार स्तरीय मौसम चेतावनी प्रणाली में सबसे गंभीर चेतावनी थी।

नदियां सूखती हैं

राज्य प्रसारक सीसीटीवी ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र चोंगकिंग में 34 काउंटी में 66 नदियां सूख गई हैं। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि यांग्त्जी नदी के किनारे छह प्रांतों और नगर पालिकाओं में 783,000 लोग लू और सूखे की स्थिति से प्रभावित हुए हैं।

मध्य चीन के जियांग्शी प्रांत में यांग्त्जी के महत्वपूर्ण बाढ़ घाटियों में से एक में, पोयांग झील अब वर्ष के इस समय के लिए अपने सामान्य आकार के एक चौथाई तक सिकुड़ गई है। झील के झिंगजी हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन में जल स्तर घटकर 10.12 मीटर हो गया है, जो 22.63 मीटर के रिकॉर्ड उच्च स्तर के आधे से भी कम है।

चोंगकिंग में इस वर्ष वर्षा मौसमी मानदंड की तुलना में 60% कम है, और कई जिलों में मिट्टी में नमी की भारी कमी है। शुक्रवार की सुबह देश के 10 सबसे गर्म स्थानों में से चोंगकिंग में छह स्थान थे, जहां बिशन जिले में तापमान पहले से ही 39 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। शंघाई पहले से ही 37 डिग्री पर था।

जगह में बिजली राशन

जैसे ही चीन में लू की स्थिति बिगड़ती है, सरकार ने कई क्षेत्रों में बिजली राशनिंग की घोषणा की है। राशनिंग से कई क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बाधित होने की संभावना है, जो वैश्विक व्यापार को और प्रभावित कर सकता है। सिचुआन, झेजियांग, जिआंगसु, अनहुई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें बिजली आपूर्ति के लिए राशन देने के लिए प्रेरित किया गया है।

सीजीटीएन ने बताया कि सूखे ने दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में बिजली उत्पादन में भारी गिरावट को मजबूर कर दिया है। लोगों को खुद को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर पर निर्भर रहने के कारण, व्यस्त समय के दौरान बिजली का भार कुल बिजली भार का लगभग 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

कई बुनियादी ढांचे और आपातकालीन सेवाएं तनाव में आ गई हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पहाड़ और जंगल में आग लगने के कारण अग्निशामक हाई अलर्ट पर हैं। रॉयटर्स ने बताया कि फुलिंग जिले में गैस उपयोगिता ने शुक्रवार को ग्राहकों से कहा कि वे अगली सूचना तक आपूर्ति में कटौती करेंगे क्योंकि वे 'गंभीर सुरक्षा खतरों' से निपटते हैं।

इस बीच, जल संसाधन मंत्रालय ने सूखा प्रभावित कृषि क्षेत्रों को यह निर्धारित करने के लिए रोटा तैयार करने का निर्देश दिया है कि किसी विशेष समय पर आपूर्ति कौन कर सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे खत्म न हों।

चीनी मौसम एजेंसी ने घोषणा की कि 45 लाख वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय क्षेत्र हीटवेव से प्रभावित हुआ है और वर्तमान स्पेल केवल 26 अगस्त को समाप्त होना शुरू होगा।

परमाणु संयंत्रों से भी ऊर्जा उत्पादन काफी कम हो गया है, क्योंकि इन प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए नदी के पानी की जरूरत होती है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जब ब्रिटेन-यूरोप खुद ऊर्जा की पैदावार बढ़ाकर आत्मनिर्भर होने की कोशिश में हैं, ठीक उसी वक्त पानी की कमी उसके इरादों पर पानी फेर सकता है।

5. किन देशों में कृषि क्षेत्र पर असर?

यूरोप में पड़ रही इस भीषण गर्मी का असर उसकी खाद्यान्न आपूर्ति पर भी पड़ने की संभावना है। दरअसल, महाद्वीप के कई बड़े देशों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की वजह से कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे बुरी हालत रोमानिया, पोलैंड, स्लोवेनिया और

पाकिस्तान को मदद की जरुरत

पाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। अब प्राकृतिक संकट ने उसका दम फुला दिया है। घनघोर बरसात और बाढ़ के कारण लगभग आधा पाकिस्तान पानी में डूब गया है। सवा हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं। लाखों लोगों के घर ढह गए हैं। करोड़ लोगों को खाने-पीने की सांसत हो गई है। 4000 किमी की सड़कें उखड़ गई हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा पुल ढह गए हैं। 2010 में भी लगभग ऐसा ही भयंकर दृश्य पाकिस्तान में उपस्थित हुआ था लेकिन इस बार जो महाविनाश हो रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ऐसा वीभत्स दृश्य उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यदि यही स्थिति दो-तीन दिन और बनी रही तो सिंधु नदी और काबुल नदी का उफनता हुआ पानी पता नहीं कितने करोड़ अन्य लोगों को अनाथ कर देगा। इस साल पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में हर साल के मुकाबले तीन गुने से ज्यादा पानी बरसा है। कुछ गांवों और शहरों में इस बार 8-10 गुना पानी ने खेत-खलिहान और बस्तियों को पूरी तरह डुबा दिया है। पाकिस्तान के 150 जिलों में से 110 जिले इस वक्त आधे या पूरे डूबे हुए हैं। यदि प्रकृति का प्रकोप इसी तरह कुछ दिन और चलता रहा तो पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान और यूक्रेन से भी बदतर हो सकती है। उसके नेता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश और कई मुस्लिम राष्ट्रों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रों के नाम अपील जारी करके पाकिस्तान के लिए मदद मांगी है। ब्रिटेन ने 15 लाख पौंड भिजवाए हैं। ईरान, यूएई और सउदी अरब भी जल्दी ही मदद भिजवानेवाले हैं। यूएई 3000 टन अनाज और दवाइयां भी भिजवा रहा है लेकिन पाकिस्तान के कई पत्रकारों और नेताओं ने मुझसे फोन पर कहा है कि यदि इस मौके पर भारत भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो कमाल हो जाएगा। वैसे तो 2010 के संकट के समय मैंने खुद राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को फोन करके पूछा था कि अगर भारत कुछ मदद पहुंचाए तो कैसा रहेगा? यही सवाल आज भी हमारे सामने है। हमने श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूक्रेन को आड़े वक्त में मदद करके जो सदभावना अर्जित की है, वह अमूल्य है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, शाहबाज शरीफ ने भारत के साथ आपसी रिश्ते सुधारने की बात पिछले हफ्ते ही कही थी। यों भी पाकिस्तान के सिंध, पख्तूनख्वाह और बलूच इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यदि नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त मदद की पहल करे तो उससे दो लक्ष्य पूरे होंगे। एक तो दक्षिण एशिया के वरिष्ट राष्ट्र होने का दायित्व हम निभाएंगे। दूसरा, भारत की मदद से पाकिस्तान की आम जनता इतनी प्रभावित होगी कि उसका असर उसकी फौज पर भी पड़ेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से लड़ना ही रहा है। यह भी संभव है कि इस पहल के कारण दक्षेस (सार्क) के जो दरवाजे सात-आठ साल से बंद हैं, वे खुल जाएं। हम यह न भूलें कि 1947 में विभाजन की दीवारें हमारे बीच जरुर खिंच गई हैं लेकिन हमारे पहाड़, नदियां, जंगल, मैदान और मौसम एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।

- डॉ वेदप्रताप वैदिक

क्रोएशिया की है। यहां पानी की कमी के चलते इस बार फसलों की पैदावार कम रहने के आसार हैं। जॉइंट रिसर्च सेंटर के मुताबिक, इन देशों में पानी और ऊर्जा संरक्षण के आपात कदम उठाने जरूरी होंगे।

बीते दशक के मुकाबले इस साल कितनी गंभीर है सूखे की समस्या?

इस साल सूखे की अवधि और इसके फैलाव का दायरा देखा जाए तो महाद्वीप का यह सूखा 70 साल में सबसे भयानक है। सूखे पर निगरानी रखने वाली यूरोप की संस्था- यूरोपियन ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक, बीते दशक के मुकाबले इस साल सूखा ज्यादा क्षेत्र में फैला है। इसके अलावा जुलाई 2012, 2015, 2018 के मुकाबले इस साल पेड़-पौधों के सूखने और मिट्टी की नमी में कमी भी काफी ज्यादा है।

दूसरी तरफ स्कैंडिनिवियन देशों (डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड) की हालत इस बार पिछले दशक के मुकाबले ज्यादा नहीं बिगड़ी है। जबकि 2018 में इस क्षेत्र ने सात दशकों का सबसे बड़ा सूखा झेला था। हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर 2018 में यूरोप के कुछ क्षेत्रों में पड़े सूखे के 2022 के हालात से तुलना करें तो यह साल सबसे बुरे सूखे से गुजरने वाला है।

सूखे से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित?

जलवायु परिवर्तन किस तरह देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, इसका उदाहरण 2022 की एनवॉयरमेंट रिसर्च लेटर्स की रिपोर्ट में मिलता है। खासकर भीषण गर्मी की वजह से फसल के नुकसान और सूखे की बात करें तो पिछले 50 वर्षों में यह तीन गुना हो गया है। 1998 से 2017 के बीच तो सूखे और फसलों के खराब होने से यूरोप-ब्रिटेन को 124 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

पिछले साल प्रकाशित हुई एक रिसर्च के मुताबिक, भीषण गर्मी की वजह से यूरोप और ब्रिटेन इस वक्त सालाना 9 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठा रहे हैं। अगर तापमान आने वाले 10 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो यूरोप-ब्रिटेन का हर वर्ष करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए

दाल की खेती वाले क्षेत्रों में बाढ़ तो चावल वाले क्षेत्रों में सूखा

लू मानसून सीजन के बिगड़े मिजाज ने खेती की तस्वीर को खराब कर दिया है। जहां दाल वाली फसलों की खेती होती है, वहां भारी बारिश और बाढ़ आ गई है। उसके उलट जिन क्षेत्रों में चावल की अत्यधिक खेती होती है, वहां सूखा पड़ गया है। मौसम की इस उलट पुलट में ना धान की रोपाई का रकबा बढ़ पाया और ना ही दाल वाली फसलों की खेती हो सकी। खरीफ सीजन वाली फसलों में इन्हीं फसलों का बोआई रकबा घटा है जो अब बढ़ने से रहा। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ सकता है।

मानसून के बादलों का रुख मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अलग रहा है। वैसे तो आंकड़ों में देशभर में भले ही बरसात सामान्य से कम नहीं हुई हो, लेकिन परंपरागत क्राप पैटर्न के हिसाब से चालू सीजन नें मानसून की बारिश नहीं हुई है। परंपरागत तौर पर जून के अंतिम सप्ताह में जिन पूर्वी राज्यों में बरसात समय से होती रही है और रुक-रुक कर पूरे सीजन यानी सितंबर तक होने वाली बारिश इस बार धोखा दे गई।

खेतों में खड़ी धान की नर्सरी हो गई खराब

जून से पिछले सप्ताह तक यहां सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है। इससे खेतों में खड़ी धान की नर्सरी खराब हो गई। नर्सरी की रोपाई हर हाल में 25 दिनों के भीतर होनी चाहिए, जो सामान्य तौर पर नहीं हो सकी है। इससे जिन किसानों ने नलकूपों के भरोसे विलंब से रोपाई कर भी दी है, उनकी उत्पादकता के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

मौसम विभाग देश के 703 जिलों में मानसून की सक्रियता का आंकड़ा दर्ज करता है। उसके मुताबिक देश के 216 जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। इन्हीं राज्यों में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

अभी तक 243.70 लाख हेक्टेयर में चुकी है धान की खेती

चालू सीजन में अभी तक 243.70 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि 374.63 लाख हेक्टेयर हो गई थी। लगभग 31 लाख हेक्टेयर रकबा कम दर्ज किया गया है। दूसरी

तरफ दलहनी फसलों की खेती वाले राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सामान्य से अधिक बरसात हो रही है, जिसका विपरीत असर दलहनी फसलों की खेती पर पड़ा है।

दलहनी फसलों के लिए कम बारिश वाला क्षेत्र ही होता है उपयुक्त

मौसम विभाग के मुताबिक 235 जिलों में सामान्य बरसात हुई। जबकि 165 जिलों में अधिक और 84 जिलों में अत्यधिक बरसात दर्ज की गई है। दलहनी फसलों के लिए कम बारिश वाला क्षेत्र ही उपयुक्त होता है। लेकिन अधिक बारिश होने की वजह से एक ओर तो बोआई घट गई और दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों की जड़ों के पानी में डूबने और सड़ने का खतरा है। लिहाजा दाल की फसलों की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा।

खरीफ सीजन में अब तक कुल 125.57 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक कुल 132.65 लाख हेक्टेयर में खेती हो चुकी थी। इस बार कुल 7.08 लाख हेक्टेयर कम रकबा में दलहनी फसलों की खेती हुई हैं।

- सुरेंद्र प्रसाद सिंह

कदम नहीं उठाए गए और सन 2100 तक तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया, तो यूरोप-ब्रिटेन को हर महीने 65.5 अरब डॉलर का नुकसान होगा।

यूरोप में सूखे की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान स्पेन को होने की संभावना है। इस देश को हर साल गर्मी की मार के चलते 1.52 अरब डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इटली और फ्रांस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। जहां इटली को 1.43 अरब डॉलर, वहीं फ्रांस को हर साल 1.24 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जर्मनी को हर साल 1.022 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहा है। पांचवें स्थान पर ब्रिटेन है, जिसकी अर्थव्यवस्था को 70.4 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ■

आर.के. सिन्हा

खेलों में भारत के बढ़ते कदम, 61 पदकों के साथ बना खेल महाशक्ति

यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं हैं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भारत की लगभग सांकेतिक उपस्थिति ही रहा करती थी। हम हॉकी में तो कभी-कभार बेहतर प्रदर्शन कर लिया करते थे, पर शेष खेलों में हमारा प्रदर्शन औसत से नीचे या खराब ही रहता था। हमारे खिलाड़ियों- अधिकरियों की टोलियां वहां पर जाकर मौज-मस्ती करके वापस आ जाया करती थी। हिन्दुस्तानी खेल प्रेमियों की निगाहें तरस जाती थीं कि एक अदद पदक को देखने के लिए।

पर गुजरे दशक से स्थितियां तेजी से बदल रही हैं खासकर मोदी सरकार के आने के बाद। सबसे बड़ी बात ये है कि हम बैडमिंटन में विश्व चैंपियन बनने लगे हैं, हमारा धावक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है और क्रिकेट में तो हम विश्व की सबस बड़ी शक्ति हैं ही। इस कामनवेल्थ गेम में 22 स्वर्ण पदकों सहित कुल 61 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया। पहली बार भारत को 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक मिले। 6 स्वर्ण पदक तो भारत ने कुश्ती में कब्जाये और 6 अन्य में जीते। 8 स्वर्ण पदक सेकंड फील्ड में हासिल की। पैरा पॉवर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और भारतीय शटलर पी. वी सिन्धु ने आखिरी दिन बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में पी.वी.सिन्धु के अतिरिक्त लक्ष्य सेन ने एकल में और चिराग-सात्विक साईराज ने जुगल में स्वर्ण पदक जीता। ईशा-गायत्री और श्रीकांत ने भी कास्यं पदक प्राप्त किये। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार पदकों की बारिश हुई। इसका कुछ श्रेय तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तो जायेगा ही।

बेटियां वेटलिफ्टिंग तथा कुश्ती जैसी स्पर्धाओं में देश की झोली पदकों से भर देती हैं। चालू कॉमनवेल्थ खेलों की वेटलिफ्टिंग स्पर्धाओं में मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा और अचिंता शुली ने भारत के लिए तीन गोल्ड मेडल जीते, जबकि संकेत महादेव सरगर, बिंद्यारानी देवी सोरोखैबम और विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल और लवप्रीत सिंह, गुरुराजा, हरजिंदर कौर और गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर कुश्ती मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। कुश्ती मुकाबलों के पहले ही दिन साक्षी मलिक ने महिला 62 किलो भारवर्ग के फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेज गोंजालेज को हराकर गोल्ड मेडल जीता। भगवान शिव के भक्त बजरंग पूनिया ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलो भारवर्ग के फाइनल में बजरंग पूनिया ने कनाडा के एल. मैकलीन को 9-2 मात दी। वहीं अंशु मलिक सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहीं। जबकि दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल कांस्य का पदक हासिल करने में सफल रहे। कुश्ती में रवि दहिया और दीपक पुनिया ने भी स्वर्ण पदक हासिल किये।

एक तरफ हमारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करते हैं। जो पहली बार भारत में हो रही है। शतरंज ओलंपियाड का चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर मामल्लापुरम में हो रहा है और इसमें रिकॉर्ड खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''यह खास टूर्नामेंट है और हमारे लिये यह सम्मान की बात है कि इसका आयोजन भारत में हो रहा है और वह भी तमिलनाडु में जिसका शतरंज से सुनहरा नाता रहा है।'' तमिलनाडु सरकार ने टूर्नामेंट का जबर्दस्त प्रचार भी किया है । पारंपरिक तमिल परिधान पहने ओलंपियाड के शुभंकर 'थम्बी' के कटआउट जगह-जगह लगाये गए हैं। ओलंपियाड रूस में होना था ढ्ढ लेकिन, यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद उससे

मेजबानी छीन ली गई। शतरंज के जानकारों का मानना है कि इसके आयोजन सन्देश में शतरंज की लोकप्रियता और बढेगी ।

कॉमनवेल्थ खेलों से ठीक पहले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया था। उन्होंने इस चैंपियनशिप में 19 साल बाद भारत को पदक दिलाया। उनकी उपलब्धि पर सारा देश गर्व कर रहा था। वे दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद इतिहास रचने में कामयाब रहे। वह भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। उनसे पहले लंबी कूद में भारतीय महिला एथलीट अंजू बेबी जॉर्ज ने यहां पदक जीता था। अंजू ने साल 2003 में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल अपने नाम किया था।

और बीती मई के महीने में भारत ने थॉमस कप जीता था। लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, एच एस प्रणय और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने जो धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया उसने उस धारणा को धराशायी कर दिया कि भारतीय खेलों के लिए नहीं बने हैं। लंबे समय से हम भारतीयों ने अपने मन में इन भ्रांतियों को पनपने दिया। कहा जाता रहा है कि भारतीयों में वह जीतने वाला दम नहीं होता। हम सिर्फ देश में ही अच्छा खेलते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेकार साबित होते हैं। अफसोस कि हमने खुद दूसरों को अपने ऊपर हंसने का मौका दिया है। भारतीय बैडमिंटन की लंबी छलांग की बात करेंगे तो पी.वी. सिधु को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उसने कुछ हफ्ते पहले सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप को जीता। उसने अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी चीन की वैंग झी यी को धूल चटाई। सिंधु के लिए ये किसी कड़ी परीक्षा की तरह था। लेकिन वो जंग ही क्या जिसे भारत की सिंधु पार नहीं कर पाए। मुकाबला टक्कर का था पर कोर्ट पर सिंधु की फुर्ती के सामने चीनी दीवार ढेर हो गई। सिंधु ने महत्वपूर्ण लम्हों पर धैर्य बरकरार रखना सीख लिया है। सिंधु का मौजूदा सत्र का यह तीसरा खिताब है। सिंधु ओलिंपिक में रजत और कांस्य पदक के अलावा विश्व चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं।

बहरहाल, ये कहना पड़ेगा कि भारत खेलों में चौतरफा स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हमारी क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहले इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में शानदार प्रदर्शन किया। ये वास्तव में सुखद स्थिति है।

पर एक पहलू को देखना होगा कि हमें खेलों में उपलब्धियां पूर्वोत्तर या हरियाणा से ही अधिक क्यों मिल रही हैं। दरअसल चानू मीराबाई और साक्षी मलिक जैसी महिला खिलाड़ी सारे देश की आधी आबादी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। इन सबने कठिन और विपरीत हालातों में भी अपने देश का नाम रोशन किया है। इन्होंने देश को गौरव और आनंद के अनेक लम्हें दिये हैं। ये ओलंपिक तथा कॉमनवेल्थ जैसे मंचों पर अपनी श्रेष्ठता को साबित कर रही हैं। इनकी कामयाबियों से सारा देश अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। इनके रास्ते पर देश की लाखों-करोड़ों बेटियां भी चलें तो अच्छा रहेगा। पर अब भी बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सफल खिलाड़ियों का निकलना बाकी है। इन राज्यों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उभरती हुई प्रतिभाओं को सुविधायें देनी होंगी। झारखंड से बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी खास तौर पर निकलते रहे हैं।

भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों की कुश्ती स्पर्धा में उम्मीद के मुताबिक सही प्रदर्शन किया। भारत को पदक दिलवाने वाले लगभग सब पहलवान हरियाणा से थे। इन हरियाणा के पहलवानों पर देश को गर्व है। पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर आदि जिलों के अपने अखाडों से श्रेष्ठ पहलवान क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या हालत है इन जिलों के अखाड़ों की? उत्तर सुनकर सिर शर्म से झुक जाएगा कि बदहाल इन आखाड़ो को कोई पूछने वाला नही है। रुस्तमे हिन्द मंगला राय, हिन्द केसरी विजय बहादुर, मनोहर पहलवान कभी तो इन्हीं अखाड़ों से निकले थे।

बिहार को भी खेलना होगा। याद नहीं आता कि 10-12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश से कब कोई नामवर खिलाड़ी निकला । बिहारी समाज को खेलों पर फोकस करना होगा। खेलों में करियर बनाना कतई गलत नहीं है। इन सब राज्यों में श्रेष्ठ खेल मैदान बनाये जाने चाहिए। इन सब राज्यों में खेलों का कल्चर विकसित करना जरूरी है। हरेक भारतवासी की यह चाहत है कि भारत दुनिया में खेलों की महाशक्ति बने। बेशक, हम इस दिशा में तेजी से बढ़ भी रहे हैं। लेकिन, अब भी हमारे देश के कुछ राज्यों में खेलों की संस्कृति विकसित नहीं हो पा रही है। इसी तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा कुछ अन्य महानगरों से भी पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में 1982 के एशियाई खेल हुए। उसके बाद 2012 में कॉमनवेल्थ खेल हुए। इस लिए यहां तमाम विश्व स्तरीय स्टेडियम बने। इनमें उच्च कोटि की सुविधाएं दी गईं। इसके बावजूद दिल्ली भी बहुत सारे खिलाड़ी देश को नहीं दे रही है। इन पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं)

कमीशन का खेल : दवा कंपनी और डॉक्टरों के बीच की सांठगांठ

-प्रियंका 'सौरभ'

दवा के फुटकर-थोक विक्रेता, डॉक्टरों और कंपनियों का ऐसा गठजोड़ है कि दवा बाजार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हाल यह है कि शिखर पर पहुंचने के लिए बीमारों की जेब से धन निकाल कर बंदरबांट किया जा रहा है। मेडिकल बाजार में अंकुश न होने के कारण मनमानी ऐसी है कि जो साल्ट नौ रुपये में 10 गोली मिल जाती है, उसे नब्बे रुपये में ब्रांडेड का टैग देकर बेचा रहा है। लगातार बढ़ रहे इस बाजार का तिलिस्म ऐसा है कि इस पर न तो सरकार अंकुश लगा पाई और ना ही अधिकारी। अंधेर तो यह है कि जब अफसर भी बीमार होते हैं तो उन्हें भी ब्रांडेड दवा ही खरीदनी पड़ती है।

डॉक्टरों को दवा कंपनियों की तरफ से मिलने वाले उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दवाओं की बिक्री को लेकर कंपनियों और डॉक्टरों की गठजोड़ को लेकर एक याचिका में ऐसा दावा किया गया है जिसे सुनकर खुद जज भी हैरान है। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर किसी खास दवा को प्रिस्क्राइब करने के लिए कंपनी डॉक्टरों को करोड़ों रुपए के उपहार देती है। उदाहरण के तौर पर अक्सर बुखार में दी जाने वाली एक कंपनी की दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1 हजार करोड़ रुपये के उपहार दिए गए ताकि उनकी दवा का प्रमोशन हो। इस याचिका में कहा गया है कि जो डॉक्टर उपहार लेकर दवा की सलाह देते हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए।

दवा के फुटकर-थोक विक्रेता, डॉक्टर और कंपनियों का ऐसा गठजोड़ है कि दवा बाजार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हाल यह है कि शिखर पर पहुंचने के लिए बीमारों की जेब से धन निकाल कर बंदरबांट किया जा रहा है। मेडिकल बाजार में अंकुश न होने के कारण मनमानी ऐसी है कि जो साल्ट नौ रुपये में 10 गोली मिल जाती है, उसे नब्बे रुपये में ब्रांडेड का टैग देकर बेचा रहा है। लगातार बढ़ रहे इस बाजार का तिलिस्म ऐसा है कि इस पर न तो सरकार अंकुश लगा पाई और ना ही अधिकारी। अंधेर तो यह है कि जब अफसर भी बीमार होते हैं तो उन्हें भी ब्रांडेड दवा ही खरीदनी पड़ती है।

अगर इस तरह का काम किया जाता है तो ना केवल दवा के ओवर यूज के केस बढ़ेंगे बल्कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ सकते हैं। इस तरह के घोटालों से मार्केट में दवाओं की कीमत और बिना मतलब की दवाओं की भी समस्या पैदा होती है। हो सकता है कि कोरोना महामारी के समय ऐसी दवाओं का ज्यादा ही प्रमोशन किया गया और

अनैतिक तरीके से मार्केट में सप्लाई किया गया। दवा कंपनी और डॉक्टरों के बीच की सांठगांठ फार्मा कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत और प्रलोभन के माध्यम से बढ़ती जा रही है। चिकित्सा प्रतिनिधियों ने यह भी उद्धृत किया कि केवल 10-20% डॉक्टर ही एमसीआई आचार संहिता का पालन करते हैं, जबकि कुछ मामलों में डॉक्टर किसी उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की भी मांग करते हैं। न केवल एलोपैथी, बल्कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कंपनियों के चिकित्सा प्रतिनिधियों ने उच्च बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारी दबाव में होने की बात कही है।

रिपोर्ट में चिकित्सा प्रतिनिधियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि कंपनी के अधिकारी डॉक्टरों द्वारा उत्पन्न व्यवसाय की निगरानी भी करते हैं, जिन पर उन्होंने 'निवेश' किया है। फार्मा कंपनियां चिकित्सा प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं या सत्र आयोजित कर रही हैं, जो वे जिस उत्पाद को संभाल रही हैं, उसके बारे में अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के बजाय, बिक्री कौशल और 'ग्राहक (डॉक्टरों) संबंधों के प्रबंधन' पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। रिपोर्ट में एक नए चलन का भी उल्लेख किया गया है - प्रचार-सह-वितरण कंपनियां इन दिनों नई संस्थाएं बनाती हैं जो फार्मा कंपनियों की फ्रेंचाइजी हैं जो निर्माताओं से थोक में दवाएं खरीदती हैं, अपने खुद के ब्रांड नाम देती हैं और उन्हें सीधे खुदरा विक्रेताओं और डॉक्टरों को उपहार, नकद, आतिथ्य और यात्रा सुविधाओं सहित छूट और प्रोत्साहन पर बेचती हैं।

डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एक आचार संहिता है जो उन्हें फार्मा कंपनियों से कोई उपहार, नकद, यात्रा सुविधाएं या आतिथ्य स्वीकार करने से रोकती है। हालांकि फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए एक स्वैच्छिक कोड है जिसे यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस या यूसीएमपी के रूप में जाना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रचलित कदाचार की जांच के लिए एक बहुत प्रभावी तंत्र नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि अनैतिक आचरण के दोषियों को दंडित करने के लिए कोई कानून नहीं है। नतीजा मरीज महंगी दवा खरीदने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार अभी भी फार्मा कंपनियों के लिए एक समान मार्केटिंग प्रैक्टिस कोड लागू करने के 2015 के प्रस्ताव पर बैठी है, जिसमें कड़े दंड का प्रावधान है।

डेढ़ साल पहले, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनैतिक प्रथाओं पर शासन करने के लिए कानून मंत्रालय को भेजे गए नियामक संहिताओं के एक प्रारूप को खारिज कर दिया गया था। फिर भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार रिपोर्ट के जवाब में कहा कि मसौदे पर चर्चा की जा रही है स्वास्थ्य के लिए खतरा उन लाखों लोगों के लिए है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकने वाली दवाओं को धकेलने वाले तर्कहीन नुस्खे का शिकार हो जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुख्य कारण है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। बैक्टीरिया समय के साथ स्वाभाविक रूप से दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित करते हैं, सुपरबग बन जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर या अनुचित उपयोग इस प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज करते हैं।

फार्मा कंपनियों की ओर से अनैतिक प्रचार को पहचानने और दंडित करने के लिए एक अनिवार्य कोड की आवश्यकता है। दवा के प्रचार पर होने वाले खर्च का दवा कंपनियों द्वारा अनिवार्य खुलासा, सतत चिकित्सा शिक्षा में दवा संबंधी सामग्री की जांच, स्वास्थ्य देखभाल सिर्फ एक उपभोक्ता उत्पाद नहीं है। ये उससे अधिक है। रोगियों को पहले रखने के आदर्श हमारी संस्कृति में निहित हैं। यह एक बड़ी कमी है जब बड़ी स्वास्थ्य प्रणालियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों, डिवाइस कंपनियों और बीमा कंपनियों के कार्यों का रोगियों पर व्यक्तिगत चिकित्सकों के कार्यों की तुलना में अधिक प्रभाव हो सकता है।

इस साठगांठ की समस्या से निपटने के लिए नया कानून लाने की सख्त जरूरत है, जिसके तहत दवा कंपनियों को डॉक्टरों को 'शोध, लेख्वरों, सफर और मनोरंजन के लिए दी जाने वाली राशि का खुलासा करना जरूरी होगा। एक ऐसी नैतिक संहिता की भी बात हो, जिसके तहत फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को किसी भी तरह का उपहार, धन या दूसरी तरह के फायदे अपनी दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए नही दे सकें और न ही वे ऐसी जगहों पर बैठकों या सम्मेलनों का आयोजन करें, जो मनोरंजन, खेल के आयोजनों या मौज मस्ती और अवकाश देने से जुड़ी हों। अनैतिक तरीके अपनाने पर सजा देने की जरूरत पर भी जोर हो। डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों की इस अनैतिक साठगांठ को तोड़ने के लिए केवल कानून ही कारगर हो सकता है। दूसरी ओर जन औषधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी जरूरत है, जिससे मरीजों को उपचार के नाम पर न तो लूटा ही जा सके और न ही उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़े। ■

This issue Published on 1st September, 2022 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089

Career Plus People - Born to Lead

2022 IAS/PCS 2023

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

SUBJECTS AVAILABLE

GEN. STUDIES (for Prelims/Mains), CSAT & ESSAY

HISTORY | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION

SANSKRIT "LITERATURE" | HINDI "LITERATURE"

By Most Renowned & Competent Facilities under the Leadership & Direction of

Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jublee Year (Since 1997)

Career Plus

English / हिन्दी Medium Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study Material & Test Series

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9

9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com